

ISSN-0971-8397



योजना

सितंबर 2010

विकास को समर्पित मासिक

मूल्य : 10 रुपये



खेलों का विकास

राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी

प्रतिस्पर्धा	सं. खिलाड़ी का नाम	स्वर्ण पदक	श्रेणी	वर्ष तथा स्थान
एथलेटिक्स	1. मिल्खा सिंह	1	440 गज	1958 कार्डिफ खेल
बैडमिंटन	1. प्रकाश पादुकोण	1	1978 एडमंट खेल	
	2. सैयद मोदी	1	1982 ब्रिस्बेन खेल	
मुक्केबाजी	1. मोहम्मद अली कमर	1	लाइट फ्लाइवेट 48 किलो भार श्रेणी	2002 मैनचेस्टर खेल
	2. अखिल कुमार	1	बैंटमवेट 54 किलो भार श्रेणी	2006 मेलबोर्न खेल
टेबल टेनिस	1. अंचित शरद कमल	1	एकल	2006 मेलबोर्न खेल
	2. पुरुष टीम	1	"	
हॉकी	1. महिला हॉकी टीम	1	2002 मानचेस्टर खेल	
निशानेबाजी	1. अशोक पंडित	1	25 मीटर सेंटर फायर	1990 आकलैंड खेल
	2. जसपाल राणा	1	25 मीटर सेंटर पिस्टल	1994 विक्टोरिया खेल
	3. जसपाल राणा	1	सेंटर फॉयर पिस्टल पेअर्स	"
	4. मनशेर सिंह	1	ट्रैप	"
	5. जसपाल राणा	1	सेंटर फॉयर पिस्टल	1998 कुआलालंपुर खेल
	6. रूपा उन्नीकृष्णन	1	महिला स्पोर्ट राइफल प्रोन	"
	7. जसपाल राणा/अशोक पंडित	1	सेंटर फॉयर पिस्टल पेअर्स	"
	8. मनशेर सिंह/मानवजीत सिंह	1	ट्रैप पेअर्स	"
	9. अभिनव बिंद्रा/समीर अंबेकर	1	10 मीटर एयर राइफल पेअर्स	2002 मैनचेस्टर खेल
	10. समरेश जंग/विवेक सिंह	1	50 मीटर पिस्टल पेअर्स	"
	11. अंजलि वेदपाठक/सुमा शिरुर	1	महिला 10 मीटर एयर राइफल पेअर्स	"
	12. मुराद अली खान/राज्यवर्द्धन सिंह राठौर	1	डबल ट्रैप पेअर्स	"
	13. अंजलि वेदपाठक भागवत/राज कुमारी	1	महिला 50 मीटर एयर राइफल श्री पोजीशंस पेअर्स	"
	14. जसपाल राणा/समरेश जंग	1	25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल पेअर्स	"
	15. मुकेश कुमार/भंवर लाल ढका	1	25 मीटर रेपिड फॉयर पिस्टल पेअर्स	"
	16. जसपाल राणा/महावीर सिंह	1	सेंटर फॉयर पिस्टल पेअर्स	"
	17. अंजलि वेदपाठक भागवत	1	10 मीटर एयर राइफल	"
	18. राज्यवर्द्धन सिंह राठौर	1	डबल ट्रैप	"
	19. अंजलि वेदपाठक भागवत	1	50 मीटर राइफल श्री पोजीशंस	"
	20. जसपाल राणा	1	25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल	"
	21. चरण सिंह	1	25 मीटर राइफल श्री पोजीशंस	"
	22. जसपाल राणा	1	सेंटर फॉयर पिस्टल	"
	23. अभिनव बिंद्रा/गगन नारंग	1	25 मीटर एयर राइफल पेअर्स	2006 मेलबोर्न खेल
	24. सुषमा राणा/सरोजा कुमारी	1	महिला 25 मीटर पिस्टल पेअर्स	"
	25. तेजस्विनी सावंत/अवनीत कौर सिद्धू	1	महिला 10 मीटर एयर राइफल पेअर्स	"
	26. समरेश जंग/विवेक सिंह	1	10 मीटर एयर पिस्टल पेअर्स	"
	27. समरेश जंग/रौनक पंडित	1	25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल पेअर्स	"
	28. पेम्बा तमांग/विजय कुमार	1	25 मीटर रेपिड फॉयर पिस्टल पेअर्स	"
	29. अभिनव बिंद्रा/गगन नारंग	1	50 मीटर राइफल श्री पोजीशंस	"
	30. समरेश जंग/जसपाल राणा	1	25 मीटर सेंटर फॉयर पिस्टल पेअर्स	"
	31. तेजस्विनी सावंत	1	महिला 10 मीटर एयर राइफल	"
	32. गगन नारंग	1	10 मीटर एयर राइफल	"
	33. समरेश जंग	1	50 मीटर एयर पिस्टल	"



योजना

वर्ष : 54 • अंक : 9 • सितंबर 2010 • भाद्रपक्ष-आश्विन, शक संवत् 1932 • कुल पृष्ठ : 56

प्रधान संपादक
नीता प्रसाद

वरिष्ठ संपादक
राकेशरेणु

संपादक
रेमी कुमारी

संपादकीय कार्यालय

538, योजना भवन, संसद मार्ग,

नयी दिल्ली-110 001

दूरभाष : 23717910, 23096738

टेलीफैक्स : 23359578

ई-मेल : exeed.yojana@gmail.com

yojanahindi@gmail.com

वेबसाइट : www.yojana.gov.in

www.publicationsdivision.nic.in

a) dpd@nic.in

b) dpd@hub.nic.in

संयुक्त निदेशक (उत्पादन)

जे.के. चंद्रा

व्यापार व्यवस्थापक (प्रसार एवं विज्ञापन)

सूर्यकांत शर्मा

दूरभाष : 26100207, 26105590

फैक्स : 26175516

ई-मेल : pdjucir@gmail.com

आवरण : साधना सक्सेना

इस अंक में

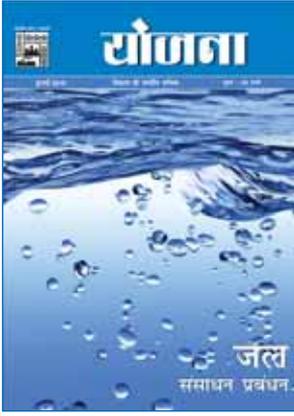
• संपादकीय	—	5
• पेईचिंग : भारतीय खेलों की विभाजन रेखा	बेरिया मजूमदार	7
• भारत में खेल कानून की आवश्यकता	फ्रांसिस कुरियाकोज दीपा कैलाशम अय्यर	10
• खेल चिकित्सा की चुनौतियां और संभावनाएं	ए. के. अरुण	12
• भारत में खेल समस्याएं और संभावनाएं	कौशल्या बाजपेयी	16
• प्रशिक्षण भावी खेल प्रबंधकों का	आदित्य कुमार	19
• खेल नीति, विकास और शिक्षा	कौशलेंद्र प्रपन	21
• शिक्षा में खेलों का समागम	रचना शर्मा	23
• क्या आप जानते हैं : राष्ट्रमंडल खेल	—	26
• भारतीय खेलों के लिए एक यादगार क्षण	हरपाल सिंह बेदी	27
• भिवानी बना मिनी क्यूबा	धर्मन्द्र सिंह	30
• भारत के स्वर्णिम कीर्ति स्तंभ	देवेन्द्र भारद्वाज	31
• राष्ट्रमंडल खेल : ऐसे हुआ जन्म	—	26
• उन्नीसवें राष्ट्रमंडल खेल दिल्ली में	—	35
• जहां चाह वहां राह : ज्ञानवान समाज का निर्माण	शैलेन्द्र सिन्हा	37
• झरोखा जम्मू-कश्मीर का : स्वर्ग में संकट	—	39
• शोधयात्रा : विकलांगों के लिए जुगाड़ वाली कार	—	41
• हिंदी के प्रसार में मीडिया की भूमिका	सुभाष सेतिया	43
• सीमाओं के आर-पार हिंदी को दुलार	उमेश चतुर्वेदी	45
• प्रोजेक्ट चीता	सुरेश प्रकाश अवस्थी	48
• खबरों में	—	51

योजना हिंदी के अतिरिक्त असमिया, बांग्ला, अंग्रेजी, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, तमिल, उड़िया, पंजाबी, तेलुगु तथा उर्दू भाषाओं में भी प्रकाशित की जाती है। पत्रिका मंगवाने हेतु, नयी सदस्यता, नवीकरण, पुराने अंकों की प्राप्ति एवं एजेंसी आदि के लिए मनीआर्डर/डिमांड ड्राफ्ट/पोस्टल आर्डर 'निदेशक, प्रकाशन विभाग' के नाम से बनवा कर निम्न पते पर भेजें : व्यापार व्यवस्थापक (प्रसार एवं विज्ञापन), प्रकाशन विभाग, ईस्ट ब्लॉक IV, लेवल VII, आर.के. पुरम, नयी दिल्ली-110066 दूरभाष : 26100207, 26105590, तार : सूचनाप्रकाशन।

सदस्य बनने अथवा पत्रिका मंगाने के लिए आप हमारे निम्नलिखित बिक्री केंद्रों पर भी संपर्क कर सकते हैं :- सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नयी दिल्ली-110003 (दूरभाष : 24367260, 5610), हाल सं. 196, पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054 (दूरभाष : 23890205) * 701, सी- विंग, सातवीं मंजिल, केंद्रीय सदन, बेलापुर, नवी मुंबई-400614 (दूरभाष : 27570686) * 8, एस्प्लानेड ईस्ट, कोलकाता-700069 (दूरभाष : 22488030) * 'ए' विंग, राजाजी भवन, बंसल नगर, चेन्नई-600090 (दूरभाष : 24917673) * प्रेस रोड नयी गवर्नमेंट प्रेस के निकट, तिरुवनंतपुरम-695001 (दूरभाष : 2330650) * ब्लॉक सं-4, पहला तल, गृहकल्प, एमजी रोड, नामपल्ली, हैदराबाद-500001 (दूरभाष : 24605383) * फर्स्ट फ्लोर, 'एफ' विंग, केंद्रीय सदन, कोरामंगला, बंगलुरु-560034 (दूरभाष : 25537244) * बिहार राज्य कोऑपरेटिव बैंक भवन, अशोक राजपथ, पटना-800004 (दूरभाष : 2683407) * हॉल सं-1, दूसरा तल, केंद्रीय भवन, सेक्टर-H, अलीगंज, लखनऊ-226024 (दूरभाष : 2225455) * अंबिका कॉम्प्लेक्स, फर्स्ट फ्लोर, पाल्दी, अहमदाबाद-380007 (दूरभाष : 26588669) * के.के.बी. रोड, नयी कॉलोनी, मकान संख्या-7, चेनीकुटी, गुवाहाटी-781003 (दूरभाष : 2665090)

चढ़े की दरें : वार्षिक : 100 रु. द्विवार्षिक : 180 रु.; त्रैवार्षिक : 250 रु.; विदेशों में वार्षिक दरें : पड़ोसी देश : 500 रु.; यूरोपीय एवं अन्य देश : 700 रु.

'योजना' में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। जरूरी नहीं कि ये लेखक भारत सरकार के जिन मंत्रालयों, विभागों अथवा संगठनों से संबद्ध हैं, उनका भी यही दृष्टिकोण हो। पत्रिका में प्रकाशित विज्ञापनों की विषयवस्तु के लिए 'योजना' उत्तरदायी नहीं है।



आपकी राय



मनुष्य ही जिम्मेदार

योजना का जुलाई 2010 अंक पढ़ा। अंक के सभी लेख पसंद आए। यह अंक लोगों को सचेत करने वाला है, क्योंकि अगर हमने पानी की क्रीमता अभी नहीं जानी, तो आगे चलकर शायद यह नसीब नहीं हो। आज जिस तरह पानी बरबाद किया जा रहा है इससे तो यही लगता है कि हमारी आने वाले पीढ़ियों के लिए शुद्ध पानी मिलना शायद नामुमकिन हो जाएगा। पानी की बरबादी के लिए मनुष्य ही जिम्मेदार है। आज कारखानों तथा घरों का गंदा पानी नदियों में छोड़ा जा रहा है जिससे नदियों का साफ़ जल दूषित हो रहा है। आज घर-घर में समरसेविल पंप लग गए हैं जिनसे मिनटों में कई लीटर पानी निकलता है, कई लोग पंप चलाकर छोड़ देते हैं, जिससे काफ़ी मात्रा में पानी बरबाद होता है। जंगल कटते जा रहे हैं। हरे-भरे पेड़ों की जगह कॉलोनियां बन गई हैं। जंगल कटने से वर्षा पर भी फ़र्क पड़ा है। प्रदूषण के कारण अब वर्षा पहले से कम होती है, जिससे धरती को जल की पर्याप्त आपूर्ति नहीं हो पाती है। आज नदियों में बांध बनाकर उनकी धारा को रोका जा रहा है, जिससे नदियों में जल न के बराबर ही बह रहा है। उत्तराखंड का उदाहरण लें तो वहां टिहरी बांध बनने से गंगा की धारा में पहले से काफ़ी परिवर्तन हुआ है। कई लोगों को विस्थापन का दर्द भी झेलना पड़ रहा है। ऐसा ही एक बांध उत्तराखंड में भारत-नेपाल सीमा पर कुमाऊं क्षेत्र में बनना है, जोकि नेपाल सरकार व भारत सरकार का संयुक्त उपक्रम होगा। यह बांध है पंचेश्वर। इस बांध के द्वारा भी नदी के पानी को रोककर बिजली बनाई जाएगी। कई गांव इसमें भी डूब क्षेत्र में आ रहे हैं। टनकपुर-बागेश्वर रेल लाइन, जिसका सर्वे हाल में हुआ था, वह भी इस बांध की हद में आ रहा

है। अगर यह बांध बना, तो फिर से नदी जल को रोका जाएगा और नदी की धारा में परिवर्तन होगा। अगर देखा जाए तो उत्तराखंड में कई स्थान ऐसे हैं जहां एक ही नदी पर कई छोटे-छोटे बांध प्रस्तावित हैं। अगर वे बांध बनते हैं, तो फिर क्या होगा? अगर ऐसा हो गया तो फिर उत्तराखंड पर्वतीय राज्य कम बांध राज्य ज्यादा कहलाएगा।

गर्मी आते ही जैसे भी उत्तराखंड के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पानी के लिए हाहाकार मच जाता है। अल्मोड़ा में ऐसे कई क्षेत्र हैं, जहां पानी काफ़ी मशक्कत के बाद मिलता है। अल्मोड़ा नगर में ही पानी टैंकरों से सप्लाई किया जाता है। कई इलाकों में तो लोग आधी रात से जंगलों में छोटे-छोटे थारों से पानी लेने जाते हैं। इन हालात में वहां का जीवन काफ़ी मुश्किलोंभरा हो जाता है। सरकार अपनी तरफ से जलापूर्ति के लिए प्रयास तो करती है पर शायद वह नाकाफ़ी है। ग्लोबल वार्मिंग का असर इतना हो रहा है कि ग्लेशियरों की बर्फ पिघलने लगी है। इससे समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है, अगर यू ही समुद्रों का पानी बढ़ता गया तो समुद्र के किनारे बसे शहरों के लिए ख़तरा पैदा हो जाएगा। समुद्र के बढ़ने से बंगाल की खाड़ी से लगे सुंदरवन के लिए भी ख़तरा बढ़ गया है। सुंदरवन के कई टापू डूबने की कगार पर पहुंच गए हैं तथा दो टापू तो डूब भी चुके हैं। यह क्षेत्र बाघों का घर है। इससे बंगाल टाइगर को भी ख़तरा पैदा हो गया है।

इस अंक में जल संसाधन प्रबंधन पर आधारित सभी लेखों के साथ-साथ, ख़तरों में पक्षी, मखाने की खेती से किसान हुए खुशहाल, बिजली न डीजल फिर भी सिंचाई, घाटी में गूंजी नयी सदा : कश्मीर कालिंग लेख भी बहुत बढ़िया लगे।

महेन्द्र प्रताप सिंह
मेहरागांव, अल्मोड़ा, उत्तराखंड

एक सुझाव

मैं योजना का नियमित पाठक हूं। मुझे इस पत्रिका के लेख बहुत अच्छे एवं रुचिकर लगते हैं। आज के समय में सारा संसार ऊर्जा की कमी का सामना कर रहा है, सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पादन के लिए मेरा एक सुझाव है। इस प्राकल्प में उत्तल लेंसों को एक बड़े भू-भाग में लगा देंगे। उत्तल लेंस प्रकाश को अभिसारित करता है एवं वहां पर प्रकाश सबसे अधिक ऊर्जाशील होता है। उत्तल लेंसों के नीचे सतह से थोड़ी ऊपर लोहे की चादरें बिछा देंगे और उन्हीं लोहे की चादरों के ऊपर प्रकाश किरणें एकत्रित होंगी जो चादर को गर्म कर देंगी। ऊष्मा चालन विधि से स्थानांतरित होगी जो टैंक वाले जल को भाप में बदल देगी। अब भाप टैंक के ऊपरी हिस्से में स्थापित पिस्टन से टकराएगा, तो पिस्टन बार-बार घूमेगा। पिस्टन से पहिए को जोड़कर पट्टे के द्वारा जनरेटर को घुमाएंगे। जनरेटर के द्वारा विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होगा और हम ऊर्जा समस्या से निजात पा सकेंगे। उत्तल लेंस के रूप में हम उस आकृति के फ्रेम में आसुत जल भरकर उपयोग कर सकते हैं।

शिवम रामराज उत्तल
जवाहर नवोदय विद्यालय, सरसौल, कानपुर

सही रखरखाव भी ज़रूरी

योजना का जुलाई 2010 अंक, जल संसाधन एवं प्रबंधन पर केंद्रित काफ़ी समीचीन एवं प्रासंगिक लगा। लेखों की विपुलता के बावजूद स्थायी स्तंभों की अहमियत शायद ही कम हुई है। प्रत्येक लेख में जल प्रबंधन पर विशेष जोर दिया गया है। इसके अलावा कई लेख ऐसे भी हैं जिसमें जल प्रबंधन की दिशा में गंगा, यमुना और देश की अन्य प्रमुख नदियों में हो रहे प्रदूषण को रोकने के उपाय पर गहन चर्चा की

गई है। हमारे यहां एक तरफ गंगा, यमुना जैसी प्रमुख नदियों को राष्ट्रीय धरोहर का दर्जा दिया जा रहा है वहीं दूसरी ओर उसके जल का अनुचित दोहन हो रहा है। समुचित जल प्रबंधन के अभाव में जल लगातार प्रदूषित होता जा रहा है। यह न केवल हमारे लिए खेद का विषय है बल्कि भविष्य में इस समस्या की भयावहता का सही आकलन करने का संकेत भी है। समय रहते जागने की जरूरत है, वरना जल संकट की समस्या इतनी गंभीर व भयावह रूप ले लेगी कि उससे निजात पाना मुश्किल ही नहीं असंभव हो जाएगा। यों तो संपादकीय में आपने इस ओर इशारा किया है परंतु लोगों की सोच को सही दिशा देना भी एक बड़ी चुनौती है। सरकारी अथवा गैर-सरकारी स्तर पर प्रयास तो अवश्य हुए हैं पर यह प्रयास हमेशा कम पड़ते रहे हैं। इस तरह के प्रयास में सतत तेजी लाने की आवश्यकता है। सामुदायिक कार्यों में प्रत्येक व्यक्ति की भूमिका अति महत्वपूर्ण होती है। जल संसाधन प्रबंधन के साथ-साथ पर्यावरण एवं प्रदूषण प्रबंधन भी काफ़ी महत्व रखता है। पर्यावरण एवं प्रदूषण की समस्या अति गंभीर होने के कारण कई अन्य समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं जिनका प्रभाव जनजीवन पर पड़ता है।

गिरीश चंद्र पांडे तथा योगेश कुमार ने अपने-अपने लेख में जल प्रबंधन को काफ़ी महत्व दिया है तथा इसके सही एवं सार्थक निदान में वे जनसहभागिता की जरूरत पर जोर देते हैं। जल प्रबंधन में गुणवत्ता की स्थिरता भी जरूरी है। जल संचय से ही सारी समस्याएं छूमंतर नहीं हो सकती हैं बल्कि समुचित रखरखाव एवं सही जल प्रबंधन भी बहुत जरूरी है। इतने अच्छे अंक के लिए योजना परिवार को साधुवाद।

राकेश कुमार
नालंदा, बिहार

पर्यावरण संरक्षण जरूरी

मैं योजना का नियमित पाठक हूँ। मुझे इस पत्रिका के लेख बहुत रुचिकर लगते हैं।

भारत महाशक्ति हो सकता है, अगर पड़ोसी देशों के साथ इसके संबंध में मिठास रहे। किंतु वह सबसे खराब पड़ोसियों के साथ रह रहा है। भारत जिधर भी देखता है उधर ही संकट नजर आता है। ऊपर से जलवायु परिवर्तन ख़तरे को और बढ़ा रहा है। कार्बन उत्सर्जन में कटौती के लिए योजना बनाने से पहले ही दुर्भाग्य से जलवायु परिवर्तन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर

विभाजनकारी मुद्दा हो गया है। जलवायु परिवर्तन हमें तीन तरह से प्रभावित करता है— पहला, जलवायु परिवर्तन प्राकृतिक संसाधनों पर विभिन्न देशों में प्रतिस्पर्धा को तीव्र कर सकता है, इससे इन संसाधनों पर टकराव बढ़ सकता है। उदाहरण के लिए पानी को लेकर एक नया खेल शुरू हो सकता है। तिब्बत से निकलने वाली अनेक नदियों के स्रोत पर नियंत्रण रखने वाला चीन इस स्थिति का फ़ायदा उठा सकता है। ग्लेशियर और पहाड़ों का बर्फ़ तेज़ी से पिघलने लगा है; इससे नदियों में जल प्रवाह बढ़ जाएगा। पानी का विशाल भंडार तिब्बत में है जो दुनियाभर में अनोखा है। विश्व में किसी अन्य क्षेत्र में पानी का इतना विपुल स्रोत नहीं है जो विश्व की करीब आधी आबादी की जरूरतें पूरी कर सके। इसमें चीन और दक्षिण भारत, पूर्वी एशिया का इलाक़ा शामिल है। तिब्बत ग्लेशियर, भूमिगत जल के बड़े स्रोत और ऊंचाई के कारण विश्व का महानतम नदी तंत्र है। दूसरे तूफ़ान, बाढ़ और सूखा जैसी मौसमी आपदाओं में वृद्धि के कारण एक देश के नागरिक दूसरे देशों में शरण लेंगे और इससे दूसरे इलाक़ों में पलायन बढ़ेगा। बाहरी लोगों के आगमन से उस देश की सामाजिक, आर्थिक स्थिति छिन्न-भिन्न हो सकती है जिससे जातीय संतुलन बिगड़ सकता है और आंतरिक और क्षेत्रीय सुरक्षा का खतरा पैदा हो सकता है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि सभी समाज जातीय, सांस्कृतिक और धर्म के प्रभावी मिश्रण होते हैं। विश्व के सातवें सबसे बड़े देश भारत को बांग्लादेश की ओर से भारी घुसपैठ का सामना करना पड़ सकता है जहां पर खारे पानी के कारण कृषि योग्य भूमि घट रही है।

जलवायु परिवर्तन का भारत की सुरक्षा पर तीसरा असर यह होगा कि इसके चलते प्रभावित होने वाले आर्थिक क्षेत्रों के कारण मानव जीवन को भारी नुक़सान होगा। तब सामाजिक एवं आर्थिक असमानता और गहरी हो जाएगी।

हम लोगों को इस स्थिति को कम करने के लिए— बढ़ती जनसंख्या, प्रतिव्यक्ति खपत, जीवाश्म ईंधन के अत्यधिक दोहन की मानसिकता को कम करना होगा और ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत जंगल एवं वनस्पतियों, साथ-साथ प्रदूषणरहित उद्योगों की संख्या बढ़ानी होगी।

आनन्द कुमार
जवाहर नवोदय विद्यालय
सरसौल, कानपुर

इन विषयों पर अंक दें

हम योजना के नियमित पाठक हैं और हमारा अनुरोध है कि निम्न विषयों पर विशेषांक दें : गरीबी एवं कुपोषण, पर्यावरण, जनसंख्या, परिवहन एवं संचार, ग्रामीण विकास, नगरीकरण एवं औद्योगीकरण, कृषि एवं विभिन्न क्रांतियां, कृषि का बदलाव एवं विकास, विज्ञान प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष एवं ब्रह्मांड, समुद्री संसाधन, भारतीय अर्थव्यवस्था की दशा एवं दिशा, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, पर्यटन, ग्रामीण गरीबी, ऊर्जा एवं खाद्य सुरक्षा, अकाल, सूखा, बाढ़, वन संसाधन, भारत के राज्य, शिक्षा परिदृश्य, शिक्षा विशेषांक, पंचायत एवं नरेगा, औद्योगीकरण, भूमि सुधार एवं कृषि विशेषांक, भ्रष्टाचार एवं भारतीय समस्याएं, सामाजिक समस्याएं, लघु एवं कुटीर उद्योग इत्यादि।

संजय, सुभाष एवं विजय कुमार
छपरा, सारण, बिहार

जागृत करता अंक

योजना का जुलाई 2010 अंक जल संसाधन प्रबंधन के ज्वलंत मुद्दे की भलीभांति व्याख्या करने में सफल रहा। यह अंक स्पष्ट करता है कि देश में फैल रही जल प्रबंधन समस्याओं की जड़ में गैर-पारदर्शी और गैर-भागीदारी प्रक्रिया वाली अनुपयुक्त नीति और विनिमय है। जल स्रोतों का सूखना तथा प्रदूषित होना गंभीर समस्या है। हमारी कृषि आधारित अर्थव्यवस्था समुचित ढंग से हो सके, इसके लिए आवश्यक है कि नदियों को आपस में जोड़ा जाए, जल-संचयन के सभी संभव विधियों और उपायों का उपयोग किया जाए। पानी का पुनर्प्रयोग संभव बनाना होगा। हमारी जनसंख्या का एक तिहाई अंश प्रतिवर्ष बाढ़ और सूखे की विभीषिका से त्रस्त है। उपलब्ध जल-संसाधनों का सही-सही आकलन एवं उनका वैज्ञानिक प्रबंधन किया जाना चाहिए। सामान्यतः बाढ़ प्रभावित लोगों की संख्या लगभग 26 करोड़ है। इसी तरह सूखा प्रभावित लगभग 8.6 करोड़ लोग हैं।

इस अंक के आलेख तथा संपादकीय विभिन्न तथ्यों के माध्यमों से जल-संसाधन प्रबंधन की महत्ता पर प्रकाश डालते हैं। यह जनजागरण फैलाने वाला अंक है। यह भारत के साथ-साथ वैश्विक संदर्भ में भी समस्याओं की पहचान करता है।

प्रवीण कुमार शर्मा
दिलावरगंज, किशनगंज, बिहार
ई-मेल : prabinkr.s@gmail.com

प्रतियोगिता साहित्य

सम्पूर्ण मासिक करियर पत्रिका

टॉपर से भेंटवार्ता



बृजबिहारी लाल
SSC Graduate Level

“ मेरे विचार से एक प्रमाणिक पत्रिका में वह सब कुछ होना चाहिए जिसकी एक प्रतियोगी परीक्षार्थी को कामयाबी के लिए जरूरत है। यानि कि ‘एक सम्पूर्ण पत्रिका’। ”

प्रमुख आकर्षण :

- राष्ट्रीय
- राज्य
- विधि/विधान
- पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण
- नवीनतम सामान्य ज्ञान
- करियर लेख
- परीक्षाओं में सफलता की रणनीति
- टॉपर से भेंटवार्ता
- पूछें आप, बताएं हम
- प्रमुख अंतरराष्ट्रीय संगठन/विश्व के देश
- रोजगार के अवसर
- निबन्ध प्रतियोगिता
- मासिक सफरनामा
- अंतरराष्ट्रीय
- आर्थिक
- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी
- खेलकूद समाचार
- समसामयिक आलेख
- हल व मॉडल प्रश्न पत्र



सदस्यता कूपन

मैं 'प्रतियोगिता साहित्य' हिन्दी मासिक पत्रिका की सदस्यता के लिए

बैंक ड्राफ्ट/मनीआर्डर संख्या दिनांक आहरित बैंक (बैंक का नाम)

..... से भुगतान 'प्रतियोगिता साहित्य' के पक्ष में भेज रहा/रही हूँ।

1 वर्ष (12 अंक) भुगतान रु. 200/- 2 वर्ष (24 अंक) भुगतान रु. 350/-

नाम :

पूरा पता :

जिला : पिनकोड राज्य

फोन : मोबाईल

ईमेल :

नोट : ● कूपन पूर्ण भरें ● भुगतान के साथ कूपन भी भेजें ● बैंक ड्राफ्ट के पीछे अपना नाम, फोन नं. भी लिखें ● बैंक स्वीकार नहीं है नियम : ● धनराशि भेजते समय अपना नाम व पता (डाक पिनकोड सहित) स्पष्ट लिखें। ● पत्रिका हर माह की 7 तारीख को साधारण डाक से भेजी जाएगी। डाक सम्बन्धी किसी भी गड़बड़ी के लिए 'प्रतियोगिता साहित्य' प्रबन्धतंत्र उत्तरदायी नहीं होगा। कूपन भेजने का पता :

प्रतियोगिता साहित्य, 3/20बी, आगरा मथुरा बाईपास, निकट तुलसी सिनेमा, आगरा-282 002 (उ.प्र.)

फोन : (0562) 4058468 फैक्स 2851568 Email : info@psagra.in Website : www.psagra.in

खेलों और खेल प्रतियोगिताओं से जुड़े आरोपों और घोटालों को झुठलाना और नकारना आसान हो सकता है, परंतु उनसे बच पाना आसान नहीं। एक ऐसे समाज में जहां अधिकांश लोगों को हाड़ तोड़ मेहनत के बावजूद पेटभर रोटी नसीब नहीं होती, वहां खेलों को प्रायः एक सपनों की दुनिया का मनोरंजन का साधन माना जाता था। परंतु जैसे-जैसे भारतीय समाज की स्थिति में पिछले दो दशकों से बेहतरीन बदलाव आ रहा है, खेलों के बारे में लोगों के नज़रिये में भी बदलाव दिखने लगा है। खेल एक ऐसी वास्तविकता है जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

भारत का मध्यवर्गीय समाज अब खेलों और मनोरंजन का अधिक आनंद लेने लगा है। सप्ताहांत अब लंबे हो गए हैं और युवा पीढ़ी इन सप्ताहांतों में बाज़ारों और मॉल्स में घूमने-फिरने तथा वक्त काटने के अलावा कुछ और विकल्प की तलाश में भी है। अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में दर्शकों की भारी भीड़ इसी बदलाव की ओर संकेत करती है। हाल के दिनों में मैराथन दौड़ जैसी प्रतियोगिताओं में बड़ी संख्या में लोगों की भागीदारी बढ़ी है और इनमें सभी आयु वर्ग के लोग शामिल हैं। विश्व कप फुटबॉल और इंग्लिश प्रीमियर लीग जैसे लोकप्रिय खेल स्पर्धाओं के सीधे टेलीविज़न प्रसारण से लोगों की रुचि में और भी इज़ाफ़ा हुआ है। शहरी जनसंख्या के एक बड़े तबके की आमदनी में वृद्धि से ऐसा होना अवश्यभावी था। भारत की शहरी जनसंख्या 40 करोड़ के करीब पहुंच गई है और इतनी बड़ी संख्या के पसंद और नापसंद की अनदेखी नहीं की जा सकती।

क्रिकेट की इंडियन प्रीमियर लीग ने लोगों की इसी दिलचस्पी को भुनाया और अब फिर अगले चरण की तैयारी है। परंतु तमाम शहरों के लोग क्रिकेट के अलावा अन्य खेलों के महारथियों में भी अपना आदर्श तलाश रहे हैं। चक दे इंडिया और खेल की विषयवस्तु वाली अन्य फ़िल्मों की सफलता से पता चलता है कि फ़िल्म उद्योग भी इस अवसर का लाभ उठाने से पीछे नहीं रहना चाहता।

लोगों की बढ़ती रुचि और मांग की तुलना में अच्छी प्रतियोगिताओं का अभाव महसूस किया जा रहा है। क्रिकेट और टेनिस के अलावा अन्य ऐसा कोई सार्थक खेल नहीं है जो शहरवासियों की इस भूख को शांत कर सके। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि प्रतियोगिताओं का आयोजन करने वाली खेल संस्थाएं अभी भी इस विश्वास पर जी रही हैं कि खिलाड़ी, शौकिया खिलाड़ी के रूप में किसी भी उम्र तक खेलों में बना रह सकता है। अधिकांश खेल संघ नेताओं और नौकरशाहों की मिलीभगत के चंगुल में फंस कर रह गए हैं। भारतीय खेलों का स्तर कितना पिछड़ा हुआ है, इसके बारे में उनमें कोई बैचनी हो, ऐसी बात नज़र नहीं आती। खेलों का प्रबंधन पेशेवर तौर पर नहीं किया जाता और न ही ख़राब प्रदर्शन के लिए कोई जवाबदेही है। यही कारण है कि युवाओं में खेल को अपने करियर के रूप में अपनाने की कोई रुचि नहीं दिखाई देती और अब जब कुछ खेलों में पैसा आने लगा है तो आयोजकों को यह समझ में नहीं आ रहा कि इस पैसे का कैसे सदुपयोग किया जाए।

विभिन्न एजेंसियों ने वर्तमान में जिन घोटालों का खुलासा किया है, उससे यह स्पष्ट होता है कि मांग और पूर्ति के बीच कितनी बड़ी खाई है। उदाहरण के लिए, राष्ट्रमंडल खेलों के आयोजन को लेकर अंतिम समय में जो उठा-पटक मची हुई है वह सब हमारे खेल प्रशासकों की जड़ता का नतीजा है। उन्हें आयोजन की बोली लगाते समय इस बात का अंदाज़ा ही नहीं था कि इस आकार की प्रतियोगिता के आयोजन में कितनी गहन योजना बनानी होती है और उसमें कितना समय लगता है। निविदाओं में कुछ कमी हो सकती है और आयोजन स्थलों, भवनों के निर्माण की जांच-परख बाद में भी की जा सकती है, अब खेलों की तारीख़ निकट आ गई है, तो हमारा सारा ध्यान उधर ही होना चाहिए। समय अब कोने में दुबक कर बैठने का नहीं है; भविष्य के लिए बड़ी और बेहतर प्रतियोगिताओं के आयोजन के बारे में सोचने का है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि खेलों के प्रति आकर्षण लगातार बढ़ रहा है। आपकी पत्रिका *योजना* के इस अंक में इन्हीं नयी प्रवृत्तियों पर नज़र डालने का प्रयास किया गया है; आगे क्या करना है, इसके बारे में भी विचार किया गया है। □



'आसानी से धन' कभी नहीं मिलता झूठे वादों के शिकार न बनें

भारतीय रिज़र्व बैंक आम जनता को सावधान करता है कि :

- भारत के बैंकों अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक को विप्रेषित/अंतरित करने का दावा करने वाली समुद्रपारीय संस्थाओं द्वारा सस्ती निधियों और बहुमूल्य वस्तुओं के काल्पनिक प्रस्तावों का शिकार न बनें।
- भारतीय रिज़र्व बैंक न तो व्यक्तियों / कंपनियों / न्यासों के नाम पर भारत में किसी खाते का रखरखाव करता है और न वितरण के लिए निधियाँ धारित करता है और ना ही किसी पदाधिकारी अथवा प्रतिनिधि को लॉटरी योजनाओं का प्रस्ताव करने और भुगतान करने के लिए प्राधिकृत करता है।
- लॉटरी या लॉटरी जैसी योजनाओं में सहभागिता के लिए किसी भी स्वरूप में विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के अंतर्गत प्रतिबंधित है।
- भारतीय निवासियों सहित अनजान विदेशी संस्थाओं अथवा व्यक्तियों से योजनाओं / प्रस्तावों में सहभागिता के लिए कोई विप्रेषण न करें।



भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA
Website : www.rbi.org.in

जनहित में जारी :



उपभेक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार,
कृषि भवन, नई दिल्ली - 110 001, वेबसाइट : www.fcamin.nic.in



उपभेक्ता इन नम्बरों पर भी सम्पर्क कर सकते हैं : राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन सं. (1800-11-4000 प्रशुल्क मुक्त) (बीएसएनएल/एमटीएनएल से) 011-27662955, 56, 57, 58 (सामान्य कॉल प्रभार लागू) (पूर्वाहन 9.30 बजे से अपराहन 5.30 बजे तक - सोमवार से शनिवार।

पेईचिंग : भारतीय खेलों की विभाजन रेखा

● बेरिया मजूमदार



सर दाराजी जी टाटा ने जब 1920 के ऐंटवर्प ओलंपिक खेलों की तैयारी के मद्देनजर भारतीय एथलीटों की पहली आधुनिक प्रतियोगिता का आयोजन किया, उन्होंने महसूस किया कि नंगे पैर दौड़ने के बावजूद भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन यूरोप अथवा अन्यत्र उसी समय के प्रदर्शनों के मुकाबले कमतर नहीं था। इससे प्रभावित होते हुए उन्होंने तीन सर्वश्रेष्ठ धावकों को ऐंटवर्प भेजने का व्यय उन्होंने स्वयं व्यक्तिगत रूप से उठाया। यह एक ऐसा क़दम था, जिसने उन्हीं के शब्दों में कहें तो, “शहर में राष्ट्रवादी तत्वों की महत्वाकांक्षा को हवा दे दी।” पुणे के इस तूफानी दिन के नवासी बरस बाद, व्यक्तिगत

स्पर्धा में स्वर्ण पदक पाने के टाटा के तब के स्वप्न को भारतीय निशानेबाज अभिनव बिंद्रा ने पूरा किया और 2008 के पेईचिंग ओलंपिक खेलों में ‘होली ग्रेल’ में अपना स्थान बनाया। जैसे ही भारतीय तिरंगा पेईचिंग में फहराया गया, चश्माधारी निशानेबाज के चेहरे पर जो गंभीरता और गर्व का भाव था, उसने करोड़ों भारतीयों को हर्षोल्लास से भर दिया। मीडिया पर चर्चा के दौरान वे उन लोगों की बहस का केंद्र बने रहे जो छाती पीट-पीटकर अपनी शेखियां बघार रहे थे। परंतु वे राष्ट्र के एक आदर्श के रूप में भी उभर कर सामने आए। भारत में इस समय 50 से अधिक चौबीसों घंटे प्रसारित होने वाले टीवी समाचार चैनल हैं। भारत में मीडिया जगत में जो क्रांति हो रही है, वैसी संभवतः अन्यत्र कहीं नहीं हो रही। पेईचिंग की सफलता ने देश में एक अभूतपूर्व दीवानगी पैदा कर दी है। एक अरब से भी अधिक जनसंख्या वाले इस देश में, जहां प्रतिस्पर्धी मीडिया उद्योग रोजाना एक नये नायक और नयी कहानियों की तलाश में लगा रहता है, बिंद्रा का अकेला स्वर्ण पदक, देशभर में उत्सव मनाने का

एक औचित्यपूर्ण कारण बन गया। ऐसा लगा कि जैसे भारत ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त कर लिया है।

भारतीय खेलों के लिए, पेईचिंग एक विभाजनकारी रेखा के रूप में देखा जा रहा है। यह एक शानदार खेल आयोजन से भी अधिक कुछ था; सिर्फ इसलिए नहीं कि ओलंपिक खेलों में भारत का यह अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था, बल्कि इसलिए भी कि इसने भारतीय खेलों में एक नयी शुरुआत का भरोसा दिलाया है। बिंद्रा कोई अकेले ही नहीं थे। कुछ और खिलाड़ियों ने भी बैडमिंटन, टेनिस तथा तीरंदाजी में शानदार प्रदर्शन किया, परंतु कमी केवल इतनी रही कि वे विजय मंच पर नहीं पहुंच सके। और जब लुका-छुपी का यह दौर चल ही रहा था, विजेन्द्र सिंह (मुक्केबाजी 75 किग्रा. वर्ग में, कांस्य पदक) और सुशील कुमार (68 किग्रा. वर्ग की फ्री स्टाइल कुश्ती में कांस्य पदक के शानदार प्रदर्शन के कारण भारतीय तिरंगा पेईचिंग में दो बार और लहराया। उनकी उपलब्धियों का टेलीविजन पर घंटों विश्लेषण किया गया

और उन्हें रातोंरात राष्ट्रीय हस्ती बना दिया। इसके बाद मीडिया में जो भावनाएं प्रकट की गईं, गर्मगर्म चर्चाएं हुईं, वे इस बात की ओर संकेत कर रहीं थीं कि पहली बार हॉकी के अलावा, ओलंपिक खेल भी चर्चा के केंद्र में छाया रहेगा। इसे एक प्रकार से राष्ट्रीय जागरुकता का प्रमाण माना जा सकता है। यह इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि दशकों की उपेक्षा और दुर्व्यवहार से ओलंपिक खेलों की जो दुर्गति हुई है, वह बदल सकती है। ठीक उस समय जब देश गुजरात और कर्नाटक में सिलेसिलेवार बम विस्फोटों, और नवंबर 2008 में मुंबई में अभूतपूर्व खून-खराबे के रोष और दुखभरे प्रभाव से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, ओलंपिक खेलों में पदकों की सफलता ने देश में आशा के एक नये युग के संचार का काम किया। इसके बाद दिसंबर 2008 में मास्को में हुई विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारतीय मुक्केबाजों की सफलता और सुपर सीरीज़ बैडमिंटन प्रतियोगिताओं में सायना नेहवाल की कामयाबी ने इस बात को साबित कर दिया कि सफलता और विजय, खेलों को राष्ट्र की कल्पना में सबसे आगे लाकर खड़ा करने में समर्थ हैं। इसके बाद जो चर्चा उभरकर सामने आई, उसमें तीन बातें प्रमुख थीं— एक राष्ट्रवादी खेल के मैदान के तौर पर खेलों पर मीडिया का नये सिरे से जोर, एक नयी भारतीय ओलंपिक संस्कृति का उदय और साथ ही यह भय भी कि भारतीय खेल ढांचे में बिना किसी सिलसिलेवार परिवर्तन के, यह आशा पुनः मिथ्या साबित हो सकती है।

भारत के खेल इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि मीडिया ने इन उपलब्धियों को भी उतना ही महत्व दिया जितना आमतौर पर क्रिकेट को दिया जाता रहा है। रातोंरात, बिंद्रा के पास विज्ञापनों के प्रायोजन संबंधी प्रस्तावों के ढेर लग गए। ऐसे प्रस्ताव आमतौर पर कुछ लाड़ले क्रिकेटरों को ही नसीब होते हैं। प्रमुख अंग्रेजी समाचार टीवी चैनल 'टाइम्स नाऊ' द्वारा कराए गए एक सर्वेक्षण से पता चला कि क्रिकेट का राष्ट्रीय धर्म अब लोकप्रियता के पायदान में नीचे की ओर खिसक रहा है। सर्वेक्षण के अनुसार चेन्नई के 53 प्रतिशत और कोलकाता में 44 प्रतिशत खेल प्रेमी ओलंपिक खेलों के प्रसारण से चिपके रहे। इसके विपरीत, चेन्नई के 41

प्रतिशत या कोलकाता के 29 प्रतिशत खेल प्रेमियों ने भारत और श्रीलंका के बीच चल रहे क्रिकेट मैच को देखना पसंद किया। मुंबई में जिन खेल प्रेमियों से बात की गई, आश्चर्यजनक रूप से, उनमें से 64 प्रतिशत लोगों ने भारत और श्रीलंका के बीच चल रही क्रिकेट शृंखला के बारे में अनभिज्ञता प्रकट की।

पेईचिंग में पदकों की कामयाबी, भारतीय मानकों के हिसाब से अभूतपूर्व रही। इसने देश को जगाकर यह अहसास कराया है कि ओलंपिक खेलों का भी महत्व है और भारत इसमें भी जीत सकता है। ऐसा लगा कि पदक विजेताओं ने जैसे राष्ट्रीय अभिलाषा को पूरा कर दिखाया हो। इसी सिलसिले में यह मिसाल भी कायम करने की कोशिश की कि उथल-पुथल से भरे राष्ट्रीय माहौल में खेलों का क्या महत्व है। इन सफलताओं



ने यह दिखा दिया कि अंतरराष्ट्रीय खेल सफलताओं में देशवासियों को एक करने की संभावना छिपी हुई है। ओलंपिक खेलों में भारत की कुछ महान उपलब्धियां ऐसे समय आई जब देश निर्मम आतंकी हमलों का उत्तर तलाशने की कोशिश कर रहा था और इसलिए उनका प्रभाव कुछ ज्यादा ही दिखाई दे रहा था। ओलंपिक खेलों के कुछ दिनों पहले, अधिकांश भारतीय देश में राजनीतिक संकट से जूझ रहे थे। उन्हें इस बात से कोई सरोकार नहीं था कि 56 सदस्यों वाला छोटा-सा भारतीय दल पेईचिंग में कुछ हासिल कर सकेगा। यहां तक कि भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष सुरेश कलमाड़ी ने एक बयान जारी कर खिलाड़ियों से किसी चमत्कार की अपेक्षा नहीं करने की अपील देशवासियों से की। सीमित अपेक्षाओं और मायूसी की इस पृष्ठभूमि

के विरुद्ध भारतीयों की सफलता कुछ ज्यादा ही चमक बिखेर रही थी।

पेईचिंग के तीन पदक विजेताओं की सफलता जहां एक ओर उनके अपने कौशल के साबित होने का प्रमाण थी, वहीं यह भारत की वृहद कथा के रूपक के तौर पर सामने आई। उन्होंने अपनी उपलब्धियों से भारतीय खेलों की विफलता की लंबी दास्तां का अंत कर दिया था; ठीक उसी तरह जैसे 1990 के दशक में भारतीय आईटी उद्योग ने 1950 के दशक से भारतीय अर्थव्यवस्था में चली आ रही 'हिंदू विकास दर' के अध्याय का समापन कर दिया था। जिस प्रकार इंफोसिस के प्रणेता नारायण मूर्ति और विप्रो के सूत्रधार अजीम प्रेमजी ने दशकों के लाइसेंस परमिट राज और अलग-थलग पड़े राष्ट्र को आईटी क्षेत्र में अपने प्रयासों से वैश्विक स्तर पर स्थापित किया था, ठीक उसी प्रकार पेईचिंग की सफलताओं से भारत ने खेलों में आत्मविश्वास के एक नये युग में प्रवेश किया था। जैसाकि जॉन मैकलून का कहनी है, "ओलंपिक खेल प्रतीकात्मक बल की एक ऐसी प्याली है जिसमें समूचा विश्व अपनी ऊर्जाओं को उड़ेलता है और हर चार वर्ष बाद, इसके लिए बने मंच से अपनी आशाओं और भय का प्रदर्शन करता है। प्रत्येक भारतीय के लिए वह भय एक प्रश्न के रूप में आता है : एक अरब लोग और कोई स्वर्ण पदक नहीं। क्यों? पेईचिंग में इसका उत्तर मिला और इसीलिए पूरे राष्ट्र में दीवानगी का आलम छाया रहा।

भारतीय खेल लेखन का इतिहास लंबे अरसे से खेलों की विफलता की शिकायतों से भरा पड़ा है। विश्लेषकों ने इसके लिए व्यवस्था को दोषी ठहराया है, उन्होंने उन नेताओं को दोषी ठहराया है जो उन्हें चलाते हैं और यहां तक कि उन्होंने भारतीय जीव संरचना (आनुवंशिकी) पर भी सवाल उठाए। यह सामूहिक राष्ट्रीय रीति-सी बन गई है कि हर चौथे वर्ष जब भी ओलंपिक खेलों में असफलता मिले, हर किसी को दोषी ठहराओ और फिर सब कुछ भूलकर चार वर्ष बाद पुनः उसी दबे हुए गुस्से का इजहार करो। पेईचिंग में भाग लेने वाले एथलीटों ने दिखा दिया कि इस व्यवस्था के बावजूद सफलता हासिल की जा सकती है। कुछ समीक्षक मजाक में कहते हैं कि भारत में कुछ चीजों, विशेषकर खेलों को, तब

तक गंभीरता से नहीं लिया जाता, जब तक वे अपने बलबूते अपना स्थान नहीं बना लेते। अभिनव बिंद्रा की सफलता ने भी उसी तरह की कहानी दोहराई है। ऐशो-आराम से भरे परिवार में जन्मे अभिनव ने अपने घर में ही 'इंडोर शूटिंग रेंज' बनवा रखा था। बचपन से ही निशानेबाजी के शौकीन बिंद्रा को शुरू-शुरू में सिडनी और एथेंस में विफलताओं का सामना करना पड़ा। वे बड़ी आसानी से खेल छोड़ सकते थे और व्यवस्था को दोष देते हुए विश्व चैंपियनशिप और राष्ट्रमंडल खेलों में प्राप्त पदकों से ही संतोष करके रह सकते थे। परंतु उन्होंने धैर्य बनाए रखा। यह हार की पीड़ा से उपजी जीत थी, सफलता के फ़ौलादी इरादों की जीत थी। यह उन लोगों को भारत का जवाब था जो सूरीनाम के एंटनी नेप्टी और इथियोपिया के धावकों की ओर इशारा करते हुए भारतीय व्यवस्था की खामियां गिनाते रहते थे। इससे यह सिद्ध हो गया है कि सरकारी खेल सुविधाओं का उपयोग किए बिना भी सफलता हासिल की जा सकती है। देश में कुशल और सक्षम व्यवस्था क़ायम करने के खिलाफ़ यह कोई तर्क नहीं है, ऐसा करना तो मूर्खता ही होगी। परंतु खेलों में ऐसे क्षण भी आते हैं जब सब कुछ अपने ऊपर भरोसे पर टिका होता है।

पेईचिंग के बाद प्रश्न उठा कि क्या हम देश में राष्ट्रीय खेल संस्कृति का उदय देखने जा रहे हैं? या फिर भारतीय लोग खुशी में तालियां

बजाकर, पेईचिंग का उत्साह समाप्त होने के बाद पुनः अपने पुराने खेल क्रिकेट की ओर लौट जाएंगे? पेईचिंग में जीते तीन पदक निश्चय ही भारत के खराब खेल प्रदर्शन की वर्षों की हताशा को ठीक करने में उत्प्रेरक का काम करेंगे। विभिन्न राज्य सरकारों ने मुक्केबाजी, कुश्ती, बैडमिंटन और निशानेबाजी में अकादमियां स्थापित करने का वायदा किया है और अब राष्ट्रमंडल खेलों की पूर्व संध्या पर भारत में भी अपनी एक ओलंपिक खेल संस्कृति जन्म लेती दिख रही है। एक ओर जहां इन वायदों को पूरा करना ज़रूरी है, वहीं यह भी याद रखना महत्वपूर्ण है कि ओलंपिक खेलों के पहले कम से कम 15 उद्योग घरानों ने भारतीय निशानेबाजों को प्रायोजित करने का आग्रह ठुकरा दिया था। पेईचिंग विजेता और सायना नेहवाल जहां डेरों प्रशंसा और श्रेष्ठतम कार्पोरेट प्रस्तावों के सर्वथा हक्रदार हैं, वहीं यह कहना भी मुनासिब होगा कि उनकी जीत की विरासत तभी कायम रह पाएगी जब अन्य खिलाड़ियों के लिए प्रशिक्षण का उत्कृष्ट ढांचा तैयार करने हेतु धन का अभाव न रहे।

आगामी अक्टूबर 2010 में पेईचिंग की विरासत की सबसे कड़ी परीक्षा होने जा रही है। यदि उन खेलों में भारत 2006 के मेलबर्न राष्ट्रमंडल खेलों में प्राप्त पदकों से अधिक पदक प्राप्त करता है तो दो वर्ष बाद लंदन में होने वाले अगले ओलंपिक खेलों के लिए इससे भारतीय

(ओलंपिक) खेलों को अभूतपूर्व प्रोत्साहन मिलेगा। दिल्ली 2010 में यदि हम विफल रहे तो आयोजक के तौर पर और साथ ही जीते हुए पदकों की संख्या की दृष्टि से, यह दुर्भाग्यपूर्ण होगा। पेईचिंग की विरासत, अगले ओलंपिक खेलों तक खेल के इतिहास की पुस्तकों में ही दबी पड़ी रहेगी।

इस संदर्भ में यहां एक वरिष्ठ पत्रकार और अभिनव बिंद्रा के बीच हुई बातचीत का एक रोचक अंश बताना उचित होगा। पेईचिंग में पदक जीतने के बाद भारत लौटने पर *टाइम्स नाऊ* टीवी चैनल की राजनीतिक संपादक नविका कुमार में अभिनव बिंद्रा से पूछा था : "यह अभिनव बिंद्रा का पदक है या भारत का?" उपयुक्त राजनीतिक आचरण के आदर्श, बिंद्रा ने बिना कोई समय गंवाए जवाब दिया, "निश्चय ही यह भारत का पदक है।"

अभिनव और उसके सहयोगियों की बदौलत यदि व्यवस्था में कोई आमूल-चूल परिवर्तन आता है, तो यह निश्चय ही सदा के लिए भारत का पदक ही रहेगा। परंतु यदि भारत के खेल ढांचे में कोई आधारभूत बदलाव नहीं आता है तो अभिनव का स्वर्ण पदक, सदैव उनका ही पदक रहेगा-स्वतंत्रता के बाद अगणित विफलताओं में खोया हुआ मात्र व्यक्तिगत प्रतिभा का एक क्षण! □

(लेखक अनेक राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खेल संस्थाओं और पत्रिकाओं से जुड़े हैं।
ई-मेल : criterion@yahoo.com)

योजना

आगामी अंक

अक्टूबर 2010 अंक

योजना का अक्टूबर अंक 'खाद्य सुरक्षा' पर केंद्रित होगा।

का नवंबर 2010 अंक 'दूरसंचार का विकास' पर केंद्रित होगा।

भारत में खेल कानून की आवश्यकता

● फ्रांसिस कुरियाकोज
दीपा कैलाशम अय्यर

मनोरंजन और व्यक्तिगत मन बहलाव के एक साधन से ऊपर उठकर खेल अब विश्वभर में एक अति प्रतिस्पर्धी उद्योग के रूप में विकसित हो चुका है। विश्व व्यापार का तीन प्रतिशत अंश खेलों के नाम है और यह अब राजस्व पैदा करने वाले सबसे बड़े स्रोतों में शामिल हो चुका है। यह अब राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियों के एक महत्वपूर्ण तथा अवश्यम्भावी अंग का रूप ले चुका है। पेईचिंग ओलंपिक खेलों ने चीन के जिस उदार शक्ति का परिचय पूरे विश्व को तीन महीनों में ही करा दिया, वह तीन दशकों की कूटनीति और राजनय भी नहीं कर सका था। किसी भी अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता के आयोजन की सफल बोली विकासशील देशों के लिए अपनी प्रगति, विकास और विश्व में अपना मुकाम दिखाने का अनूठा अवसर प्रदान करती है। भारत आगामी अक्टूबर में राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी करेगा। दिल्ली में होने वाले इस खेल आयोजन में 85 देशों के 5,000 खिलाड़ी और 12 लाख से अधिक दर्शकों के भाग लेने की आशा है। इन खेलों के आयोजन के सिलसिले में दिल्ली में 2 ख़रब 60 अरब रुपये का निवेश हो रहा है जिसके बाद दिल्ली दुनियाभर के खेल प्रेमियों के लिए आकर्षण के केंद्र के रूप में उभरकर सामने आएगी। यह एक इतना व्यय साध्य आयोजन है कि दिमाग चकरा जाए। बुनियादी ढांचे, लाइसेंसिंग, प्रायोजन, मीडिया अधिकार और आदर्श खेल गतिविधियां जैसी अनेक जटिल समस्याएं इस आयोजन से जुड़ी हैं

जो सर्वथा विलक्षण हैं। यह एक ऐसा उपयुक्त अवसर है जब भारत में खेलों से संबंधित सरल कानूनी प्रावधानों की आवश्यकता के बारे में विवेचना करनी चाहिए।

कानूनों की आवश्यकता

पिछले कुछ दशकों से खेल जगत विवादों और घोटालों का शिकार रहा है। ओलंपिक खेलों के आयोजन की बोली, हाल का आईपीएल घोटाला और भारतीय महिला हॉकी टीम की यौन प्रताड़ना के आरोपों ने पूरे राष्ट्र को झकझोर कर रख दिया है। वर्ष 1928 से लेकर 1956 तक लगातार 6 स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली भारतीय हॉकी पुरुष टीम अब इतने निचले पायदान पर आ खड़ी हुई है कि वह वर्ष 2008 के ओलंपिक खेलों में भाग लेने की योग्यता तक न पा सकी। इस एक अकेली घटना ने उस दोषपूर्ण प्रणाली के कुशासन और बिखराव का पर्दाफाश कर दिया है जिसने हमारे संसाधनों को मिट्टी में मिला दिया है। यहां तक कि भद्रजनों का खेल कहा जाने वाला क्रिकेट भी मैच फिक्सिंग और सट्टेबाजी के कलंक से अछूता नहीं रहा है। ये सभी घटनाएं अति प्रतिस्पर्धी खेल दुनिया के स्याह पहलू को उजागर करती हैं।

खेल जगत के अर्थशास्त्र की कार्यप्रणाली के बारे में सायमन रॉटनबर्न ने काफी शोध किया है। पेशेवर खेल पर अपनी पुस्तक में उन्होंने इसकी विवेचना अन्य किसी आर्थिक गतिविधि पर लागू प्रतिमानों के आधार पर की है और उन्होंने कुछ शानदार निष्कर्ष निकाले हैं। उन्होंने खेल प्रतियोगिता

को एक संयुक्त उत्पाद और विभिन्न कारकों के सम्मिलित प्रयास के रूप में परिभाषित किया है। उन्होंने कहा कि खेल की कोई भी एक टीम या खिलाड़ी अकेले ही खेल का दिलचस्प और दमदार स्वतंत्र उत्पाद नहीं दे सकता। अतः खेल-तमाशे के लिए एक 'प्रतिस्पर्धी संतुलन' की आवश्यकता है और शुद्ध बाज़ार पर लागू साधारण नियमों को इसमें लागू करने के पहले उनमें कुछ संशोधन करना पड़ेगा। यद्यपि खेलों को बढ़ावा देने में स्पर्धा की ही सबसे मूल्यवान भूमिका होती है, तथापि किसी खेल आयोजन की सफलता के लिए 'प्रतिस्पर्धी संतुलन' अथवा प्रतियोगियों की समानता की आवश्यकता होती है। दो टीमों के बीच टक्कर के मुक़ाबले से पैदा होने वाली उत्तेजना से ही खेल में पैसा आता है। अतः असंयत खुले बाज़ार से लोकहित को साधने वाला सिद्धांत यहां लागू नहीं होता। खेल की दुनिया जिस दूसरे खंभे पर टिकी है, वह है परिणाम की अनिश्चितता। इन्हीं दो कारकों ने उस व्यवस्था को परिभाषित किया है, जिसके अनुसार खेल उद्योग काम करता है।

खेलों की दुनिया में जिन प्रमुख समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उन्हें मोटे तौर पर निम्नानुसार श्रेणियों में बांटा जा सकता है :

● **श्रम संबंधी मुद्दे** : खिलाड़ियों और मालिकों को खेलने के घंटे, पारिश्रमिक और कामकाजी स्थितियों से जुड़े अनिवार्य मुद्दों को तय करना होगा। खिलाड़ियों की ओर से उनका व्यवसाय देखने वाले एजेंटों को वफ़ादार

और ईमानदार होने के साथ ही खेलों के हित में सोचना होगा। प्रदर्शन सुधारने के लिए मादक द्रव्यों के सेवन की समस्या, मादक द्रव्य नीतियों का एक अभिन्न पहलू है। दवाओं के परीक्षण, प्रतिबंधित दवाओं की सूची, दंड, निजता से जुड़े मुद्दे और अपील का अधिकार जैसे मुद्दों के बारे में संबंधित नोडल एजेंसी को स्पष्ट रूप से बताना चाहिए।

- **संविदा भंग कानून** : संविदा भंग कानून पहले खेलों के कानून का हिस्सा नहीं हुआ करते थे। परंतु चोट पहुंचाने के आपराधिक इरादे से जानबूझकर संविदा भंग करने के लिए दंड मिलना ही चाहिए। इसी प्रकार, प्रचार का अधिकार इस्तेमाल करने के लिए खिलाड़ी के चरित्र और प्रतिष्ठा का भी ध्यान रखना होगा।
- **जवाबदेही कानून** : सरकारी निकायों और खेल विभाग की देखरेख के लिए अधिकृत अन्य एजेंसियों द्वारा किए जाने वाले मौद्रिक सौदे में जवाबदेही सुनिश्चित करने और भ्रष्टाचार रोकने की आवश्यकता है। विभिन्न खेल संघों में पदाधिकारियों के कार्यकाल और आयु सीमा संबंधी प्रतिबंधों को लागू करना काफी समय से लंबित है। ऐसे समझौतों को जो सबसे अलग प्रकृति के हों और इसलिए जो व्यापार पद्धतियों के कानून के विरुद्ध जाते हों, उन्हें प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए। किसी भी प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए अनिवार्य सुविधाओं को किसी प्रतिद्वंद्वी को देने से इंकार करने की घटना से सख्ती से निपटा जाना चाहिए। यह हमारे देश में विशेष रूप से लागू होता है, जहां खेल प्रशासन का संगठन पिरामिड जैसा होता है, जिसके शीर्ष पर बैठा व्यक्ति ही उस एजेंसी को अपनी मर्जी से चलाता है।
- **प्रसारण अधिकार** : भारत के प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के अनुसार वह समझौता अवैध होता है जिससे प्रतिस्पर्धात्मकता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसके बावजूद बीसीसीआई (भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड) काफी लंबे समय से विशिष्ट सहभागियों को प्रसारण अधिकार बेचता रहा है। आम लोगों में खेलों को देखने की दिलचस्पी बनाए रखने के सिद्धांत के पीछे यथार्थ यह है कि खेल एक क्षणिक उत्पादक है। किसी जीवंत

स्पर्धा में परिणाम की अनिश्चितता का तत्व बहुत निर्णायक महत्व का होता है और उसका स्थान कोई और नहीं ले सकता। कुछ थोड़े से लोगों में प्रसारण अधिकारों का केंद्रित होना, मीडिया अधिकारों में निष्पक्षता की संभावनाओं को बाधित करता है।

समस्या की व्यापकता और उसके सूक्ष्म भेदों से यह स्पष्ट हो जाता है कि खेल कानून अब न तो कोई व्यावहारिक रहेगा और न ही किसी क्षेत्राधिकार के अधीन कानूनों का मिश्रण रहेगा, बल्कि अपने आप में यह एक कानून रहेगा। संविधान की सातवीं अनुसूची में 33वीं प्रविष्टि ने राज्यों के साथ-साथ केंद्र को भी खेलों से जुड़े संघों के नियमन, पंजीकरण और मान्यता के बारे में कानून बनाने का प्रावधान रखा गया है। राजस्थान और हिमाचल प्रदेश ऐसे दो राज्य हैं जिनमें वर्तमान में कार्यशील खेल कानून बने हुए हैं। भारत में प्रादेशिक खेल संस्थाएं कंपनी कानून के तहत अलाभकारी संगठनों के तौर पर काम करती हैं। प्रतियोगिता कानून 2002, प्रतियोगिता की वकालत को बढ़ावा देता है, प्रभुत्व का दुरुपयोग और गैर प्रतियोगी समझौतों को रोकता है। परंतु खेल के किसी व्यापक कानून का लक्ष्य एक वृहद आदर्श और संकल्पना होना चाहिए। कानून निर्माताओं को खेलों से संबंधित विभिन्न मुद्दों के बारे में विचारों और सूचनाओं का प्रचार-प्रसार करना चाहिए और इस संकल्प को पूरा करने से पूर्व सम्मेलनों के जरिये तमाम प्रकार के दृष्टिकोणों के आदान-प्रदान को प्रोत्साहित करना चाहिए।

भारत में व्यापक खेल कानून की परिकल्पना

- कानून को प्रतियोगियों और निर्णय लेने की प्रक्रिया से जुड़े निकायों में सदाचरण और खेल भावना के नियमों को स्थापित और प्रोत्साहित करने वाला होना चाहिए। इस परिकल्पना के पीछे जो प्रमुख विचार है वह है— कानूनी मुद्दों का नैतिक समाधान। इससे संविदा के व्यावहारिक पक्ष में जो सुधार आएगा, उससे खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ेगा। संविदाओं में यह बात पूरी तरह से स्पष्ट होनी चाहिए कि खिलाड़ियों और एजेंटों से क्या अपेक्षाएं और वचनबद्धता अपेक्षित हैं।
- खेल निकायों और खिलाड़ियों को परामर्श सेवाएं दी जानी चाहिए। इस तरह के स्वस्थ संप्रेषण के लिए कानूनी बिरादरी और खेल समुदाय के बीच समन्वय एक पूर्व शर्त है।

● राष्ट्रीय पहचान और भारत का प्रतिनिधित्व करने की भावना राजनीतिक निर्णयों से ऊपर रहनी चाहिए। बेहतर होगा कि किसी खिलाड़ी को ही संगठन का शीर्ष पद सौंपा जाए बजाय इसके कि उस पर प्रशासक, नेता अथवा निहित स्वार्थी वाला कोई व्यक्ति बैठा हो।

- भ्रष्टाचार रोकने के लिए खेल संघों के पदाधिकारियों पर कार्यकाल की सीमा और आयु की पाबंदी को लागू करना जरूरी है। यदि किसी खिलाड़ी अथवा प्रतिद्वंद्वी संगठन को अनिवार्य सुविधाएं नहीं मुहैया कराई जातीं, या फिर जानबूझकर अलहदा नीतियां अपनाई जाती हैं, तो संबंधित प्रशासक की सेवाएं समाप्त कर दी जानी चाहिए। अधिकारों के दुरुपयोग के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए।
- खिलाड़ियों और टीमों की वेतन की सीमा तय की जानी चाहिए। उन गतिविधियों को कतई सहन नहीं किया जाना चाहिए जो किसी नये खिलाड़ी के मार्ग में बाधाएं खड़ी करती हैं या मौजूदा खिलाड़ियों को बाहर कर देती हैं जिससे प्रतियोगिता समय से पहले ही समाप्त हो जाती है।
- महिला खिलाड़ियों के साथ अधिक संवेदनशीलता पूर्वक व्यवहार करना चाहिए और उन्हें कानूनी सहायता प्रदान करनी चाहिए। प्रताड़ना और भेदभाव करने वालों को सख्त सजा दी जानी चाहिए।
- सतत शिक्षा के जरिये खेलों के क्षेत्र में उत्कृष्ट अनुसंधान को बढ़ावा देना चाहिए। खेल कानून का क्षेत्र हमारे देश में अपेक्षाकृत नया है और अभी अपने प्रारंभिक चरण में है। इसके बावजूद, यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसको परिभाषित करने के साथ-साथ इसका गहन अध्ययन करने की जरूरत है, इसे अपनाया जाना चाहिए। एक सुनियोजित विस्तृत प्रतियोगिता अनुसरण कार्यक्रम सभी उद्यमियों के लिए लाभप्रद हो सकता है। एक नया दृष्टिकोण, एक स्वतंत्र प्राधिकरण और एक समग्र कानून, समय की मांग है। □

(लेखकद्वय में से प्रथम केरल विश्वविद्यालय, तिरुवनंतपुरम के मार इवानियोस कॉलेज में वाणिज्य और प्रबंधन के सहायक प्रोफेसर रह चुके हैं तथा द्वितीय पुडुचेरी स्थित स्वतंत्र पत्रकार हैं।

ई-मेल : francyge83@yahoo.co.uk,
deepa_7ki@yahoo.co.in)



खेलों का विकास

खेल चिकित्सा की चुनौतियां और संभावनाएं

● ए. के. अरुण

यों तो खेल स्वस्थ जीवन के अभिन्न अंग हैं लेकिन सभ्यता के विकासक्रम में अध्ययन की बढ़ती महत्ता ने खेलों को पढ़ाई से कमतर कर दिया है। पहले जमाने में समाज में लोकोक्ति चल पड़ी थी - *खेलोगे-कूदोगे होंगे खराब, पढ़ोगे-लिखोगे बनोगे नवाब*। दिनोंदिन खेलों की बढ़ती महत्ता और उपयोगिता ने इस लोकोक्ति को उलट कर रख दिया है। व्यावसायिक शिक्षा में खेल इन दिनों सर्वाधिक चर्चित और महत्वपूर्ण विषय बना हुआ है। हालांकि मीडिया की चकाचौंध में खेल का महत्व बढ़ने से यह विवाद का विषय भी बन गया है। खेल-कूद और शारीरिक क्षमता के कुछ चिकित्सीय पहलुओं पर केंद्रित इस लेख में हम संक्षेप में खेल की राजनीति, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा शारीरिक शिक्षा एवं खेल के विभिन्न मनोवैज्ञानिक पहलुओं को भी समझने की कोशिश करेंगे।

पृष्ठभूमि

आदिमकालीन स्रोतों में इस बात के प्रमाण

उपलब्ध हैं कि मनुष्य ने आखेट और युद्ध क्षेत्र की कठिनाइयों का सामना करने के लिए प्रशिक्षण की प्रक्रिया से अपने शरीर को बलिष्ठ बनाया है। इस प्रक्रिया की अभिव्यक्ति विभिन्न खेलों अथवा उत्सवों में नृत्य तथा शारीरिक कला प्रदर्शन के रूप में होती थी। कहते हैं कि बाद में राजतंत्रों के विकास में शारीरिक शिक्षा एवं खेलों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यूनानी तथा मिनोअन संस्कृति में इसके प्रमाण स्पष्ट रूप से मिलते हैं। इन संस्कृतियों में शारीरिक शिक्षा एवं खेल पर मुख्य रूप से उच्च वर्गों का विशेषाधिकार था। इस उच्च वर्ग से ही योद्धा बनते थे। इस शिक्षा का मूलतः सैनिक तैयारियों से संबंध था। परवर्ती यूनानी सभ्यताओं में पहली बार शारीरिक शिक्षा एवं खेल को महत्व देकर अधिक व्यापक बनाया गया। इसका उद्देश्य नौजवानों के स्वास्थ्य में सुधार करना तथा रोग और अशक्तता के उपचार के साधन के रूप में भी उसका विकास करना था। इसी दौर में नागरिकों के बीच एथलीट

उभरकर आया जिसका काम विभिन्न प्रकार के खेलकूद एवं उत्सवों में होने वाली प्रतियोगिताओं में भाग लेना था।

रोमन साम्राज्य को शुरुआती दिनों में सैन्य उद्देश्य के अनुकूल ढाला जाने लगा था। खेल और व्यायाम के चिकित्सीय व्यवहार पर इस दौरान गालिन ने विशेष बल दिया था। गालिन उस दौर में सशस्त्र क्रीडकों, एथलीटों की टीम के चिकित्सक थे। खेलकूद संबंधी प्रतियोगिताओं के बारे में रोमन लोगों के विचार यूनानियों के विचार से भिन्न थे। हालांकि रोमन खेलकूद के अभ्यास द्वारा शारीरिक क्षमता विकसित करने के इच्छुक थे लेकिन उन्होंने सार्वजनिक प्रतियोगिताओं में कभी भाग नहीं लिया। संभवतः वे खेलकूद में उग्रता को पसंद नहीं करते थे और खेलकूद की प्रतियोगिताएं अक्सर उग्र होती थीं। रोमन साम्राज्य के पतन के बाद उत्तरवर्ती रोमन साम्राज्य में किए गए दैनिक उत्पीड़न की प्रतिक्रिया स्वरूप शरीर साधना को निन्दित कार्य समझा जाने लगा। कई



पीढ़ियों तक यह माना जाता रहा कि शारीरिक शिक्षा का उपयोग एकमात्र युद्ध के लिए ही है। 15वीं शताब्दी के बाद मनोरंजन और चिकित्सा के क्षेत्र में व्यायाम का महत्व बढ़ता गया। 19वीं शताब्दी के अंत तक खेलकूद का रूप काफ़ी सुव्यवस्थित हो गया। इसमें उच्च वर्ग के वर्चस्व को तोड़कर श्रमजीवी वर्ग के लोग भी भाग लेने लगे। धीरे-धीरे खेल राष्ट्रीय भावना से जुड़ते चले गए। डे कोबर्टिन के द्वारा आधुनिक ओलंपिक खेलों के प्रचलन के बाद खेल खिलाड़ियों की राष्ट्रीयता या संबंधित देशों की भावना से जुड़ गए। खेलों का राजनीतिक महत्व बढ़ गया। खेलों, खिलाड़ियों का महत्व बढ़ने के साथ-साथ उनके स्वास्थ्य की चिंता और खिलाड़ियों के उपचार, फ़िटनेस, खेल दुर्घटना से बचाव आदि के मामले को भी महत्व मिला इससे 'खेल चिकित्सा' विषय को प्रमुखता मिली और यह विशेष क्षेत्र उभरकर सामने आया।

खेल चिकित्सा में शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को महत्व देने के साथ-साथ भौतिक चिकित्सा का विशेष योगदान है। आपाधापी के युग में स्वास्थ्य एक महत्वपूर्ण विषय बन गया है। बेहतर स्वास्थ्य के लिए खेलकूद व शारीरिक शिक्षा का महत्व नकारा नहीं जा सकता। इस बात का भी उन लोगों को अहसास हो रहा है कि शारीरिक व मानसिक रोगों से बचाव व उपचार के लिए भी खेल ज़रूरी है। लेकिन खेल के दौरान होने वाले स्वास्थ्य क्षति या दुर्घटना का समय पर उपचार भी उतना ही ज़रूरी है जितना शरीर को खेल के लिए तैयार करना।

शारीरिक औषधियों के मामलों में प्रयुक्त बहुत से तकनीकों की खोज ज्यादातर प्रशिक्षकों ने खेल के मैदानों या व्यायामशालाओं में ही की, लेकिन आश्चर्य की बात है कि आज तक औषधि और शारीरिक प्रशिक्षण तथा एथलीट प्रशिक्षण के बीच समुचित संबंध स्थापित न हो सका। इससे शारीरिक शिक्षा तथा एथलीट प्रशिक्षण के क्षेत्र में होने वाली प्रगति का उपयोग हम चिकित्सा क्षेत्र में नहीं कर पा रहे हैं। भविष्य में शायद चिकित्सा और शारीरिक शिक्षा के बीच परस्पर संबंध स्थापित हो और एक-दूसरे की मदद से बेहतर सेवा लोगों को मिल सके। वास्तव में किसी एथलीट को अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए तैयार करने या किसी पक्षाघात से पीड़ित व्यक्ति का उपचार करने, दोनों का उद्देश्य और तरीका लगभग एक जैसा ही होता है। हां, इसमें

केवल मात्राओं का अंतर हो सकता है। इस प्रक्रिया को ही प्रशिक्षण कहा जाता है।

प्रशिक्षण किसी व्यक्ति की कार्यक्षमता पर दो प्रकार से प्रभाव डालता है। पहला सामान्य तथा दूसरा प्रभाव विशिष्ट होता है। प्रशिक्षण की प्रक्रिया शरीर की विभिन्न क्रियात्मक तंत्रों में निश्चित परिवर्तन लाती है जिसे आमतौर पर मापा जा सकता है। इनमें से कुछ परिवर्तन, विशेषकर ऐसे जिसका संबंध हृदयवाहिका और श्वसन तंत्रों से है, अवश्य पैदा होते हैं, भले ही आप कैसा भी प्रशिक्षण किसी भी पद्धति से क्यों न कर रहे हों। जिस मात्रा में ये परिवर्तन होते हैं उससे प्रशिक्षण द्वारा सामान्य स्वास्थ्य में कितना सुधार आ रहा है उसका हिसाब लगाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त अन्य परिवर्तन भी होते हैं, जिसे आसानी से नहीं मापा जा सकता। जैसे तंत्रिका पेशी तंत्रों में परिवर्तन, शरीर के अंतःस्रावी द्रवों में परिवर्तन आदि।

किसी व्यक्ति विशेष की शारीरिक कार्यक्षमता और उसकी शारीरिक योग्यता का निर्धारण कई बातों से होता है। इसमें मुख्य है, सक्रियता का स्तर, जिसके आधार पर दैनिक कार्य और मनोरंजन के कार्य किए जाते हैं। अतः यदि अन्य सब बातें एक जैसी हो तो शारीरिक श्रम करने वाले या व्यावसायिक खिलाड़ी की कार्यक्षमता बैठे रहने वाले व्यक्ति की तुलना में अधिक होगी। (यद्यपि यह आवश्यक नहीं कि उसमें अंतर्निहित क्षमता भी अधिक हो) कार्यक्षमता और अंतर्निहित क्षमता का निर्धारण आनुवांशिक बातों पर भी निर्भर करता है। किसी निर्धारित सक्रियता में व्यक्ति के प्रदर्शन स्तर का निर्धारण केवल उसकी योग्यता का सामान्य स्तर पर उसकी अंतर्निहित क्षमता से ही नहीं बल्कि उसे किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, उससे भी किया जाता है। किसी खेल में प्रभावी रूप से भाग लेने के लिए निम्नलिखित पांच बातें आवश्यक मानी जाती हैं : प्रगति, शक्ति, दम, दक्षता एवं नम्यता। हालांकि ये गुण एक-दूसरे पर आश्रित हैं लेकिन इन्हें विभिन्न तरीकों से खासतौर पर प्राप्त किया जा सकता है। इस आधार पर खेलों का वर्गीकरण भी किया जा सकता है। जैसे ताक़त के खेल उदाहरण के लिए भारोत्तोलन, गोला फेंकना आदि, सहिष्णुता वाले खेल जैसे लंबी दौड़, मैराथन आदि। तेज़ गति वाले खेल जैसे 100 मीटर दौड़, विंग थ्रो आदि। वास्तव में अधिकांश खेल और दौड़-कूद को इस प्रकार

सीमित रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता क्योंकि ऐसे वर्गीकरण से अक्सर धोखा हो जाता है।

खेल में चूँकि क्षमता या ताक़त ज्यादा मायने रखता है इसलिए खिलाड़ी विशेष प्रशिक्षण के साथ-साथ विशेष भोजन पर भी ध्यान देते हैं। मशहूर एथलीट हब्र इलियट जब अपनी सफलता के शिखर पर थे तब बहुत से एथलीट उनके देखा-देखी अधिक मात्रा में बादाम और व्हीट जर्म का तेल इस्तेमाल करने लगे क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि इलियट इनका नियमित इस्तेमाल करते हैं। चिकित्सा व विज्ञान की नज़र में यह एक मनोवैज्ञानिक बात है। यह उतना सत्य नहीं है। संक्षेप में कह सकते हैं, जिसके स्तर का निर्धारण विभिन्न शरीर के क्रियात्मक और मानसिक बातों के द्वारा होता है और जिसे स्थिर रखना, बढ़ाना या कम करना व्यक्ति विशेष की परिस्थितियों के अनुसार होता है। दैनिक जीवन की घटनाओं का किसी व्यक्ति पर जो दबाव होता है उससे निबटने के लिए उसमें जो योग्यता होती है उस पर इसका सीधा प्रभाव पड़ता है।

मनोवैज्ञानिक पहलू

व्यक्ति व्यायाम एवं खेल की ओर क्यों प्रवृत्त होता है? कह सकते हैं कि तत्काल अभिप्रेरण की वजह से व्यक्ति खेल में प्रवृत्त होता है। फिर यह भी सवाल उठ सकता है कि क्या खेलने की आदत किसी विशिष्ट एवं निर्धारित आवश्यकताओं एवं लालसा की पूर्ति का फल है? अभिप्रेरण तथा व्यक्तित्व के एक-दूसरे से संबंध होने के कारण किसी व्यक्ति के खेल के प्रति व्यवहार के प्रेक्षण से कुछ अनुमान लगाया जा सकता है क्योंकि किसी दी गई स्थिति के प्रति किसी व्यक्ति की प्रतिक्रिया उस स्थिति में उस व्यक्ति के अभिप्रेरण पर आधारित होगी।

अभिप्रेरण के बहुत से सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं, जिनमें फ्रायड, हैब्स तथा मसलो के सिद्धांत शामिल हैं। हालांकि ये सिद्धांत संतोषजनक नहीं हैं फिर भी यहां इनकी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। एक सिद्धांत कहता है कि किसी भी क्रिया का कारण अवचेतन बलों द्वारा उत्पन्न अंतर्द्वंद्व के तनाव को जिसमें शमन, प्रक्षेपण तथा रूपांतरण भी शामिल है, सुरक्षा प्रक्रिया द्वारा कम होता है। इस धारणा के अनुसार खेलों में भाग लेना तथा शारीरिक योग्यता का विकास करना वृत्तिक ऊर्जा को नयी दिशा देता है। इसके विमोचन के द्वारा

तनाव से छुटकारा मिलता है। दूसरा सिद्धांत अन्य कई आधारभूत प्रवृत्तियों तथा लालसाओं के बारे में है जो प्रवृत्ति और संतुष्टि के सीधे संबंध की व्याख्या करता है।

साधारणतया ऐसा प्रतीत होता है कि स्वास्थ्य का विकास एवं खेल मनोवैज्ञानिक संतोष के लिए होता है। यह संतोष प्रत्यक्ष या परोक्ष किसी भी प्रकार का हो सकता है। यह स्थिति उन स्कूली बच्चों में देखी जा सकती है जो खेलों में भाग न लेने के परिणाम के डर से अभिप्रेत होकर किसी खेल में भाग लेता है। हालांकि अपेक्षाकृत उसे कुछ अन्य प्रेरक प्रवृत्तियां खेलों में भाग न लेने के लिए उकसाती हैं। प्रवृत्तियों के इस टकराव का परिणाम सदा एक-दूसरे को निष्फल करना नहीं होता बल्कि यह इन व्यक्तियों के विवाद को और भड़काता है। जैसे कोई व्यक्ति फुटबॉल खेलने में रुचि नहीं लेता और उसे फुटबॉल खेलना पड़ता है तब वह विक्षुब्ध, अधिक खाने वाला बन जाता है और अपना वजन बढ़ा लेता है। इन व्यक्तियों के लिए अनिवार्य खेल की नीति ज्यादातर विफल होती है। इसे अनुशासन के विरोध में एक दलील की तरह नहीं देखना चाहिए, बल्कि अनुशासन लागू करने के लिए एक विचार के रूप में समझना चाहिए। अतः खेल-कूद की परिभाषा 'आनंद के लिए दी गई शारीरिक क्रिया' के रूप में दी जा सकती है। हालांकि इसे सीधे लाभ या किसी बीमारी या अशक्तता के इलाज के लिए भी काम में लाया जा सकता है।

सामान्यतः एक निष्कर्ष यह निकाला जाता है कि श्रेष्ठ खिलाड़ी अत्यधिक संवेदनशील होते हैं। व्यक्तित्व सूची पर किए गए कई अध्ययनों से यह पता चला है कि वास्तव में सभी एथलीट, पुरुष-महिला खिलाड़ी या सामान्य व्यक्ति मनोवैज्ञानिक तौर पर ज्यादा भिन्न नहीं होते। अध्ययन बताता है कि खिलाड़ी के कुछ समूहों में कुछ ऐसे विशेष लक्षण होते हैं जिनका संबंध अच्छे मानसिक स्वास्थ्य से होता है। असाधारण खिलाड़ियों के ये विशिष्ट लक्षण उन्हें साधारण खिलाड़ियों से अलग करते हैं। इसके अलावा अंतः दृष्टि, संस्कार, नीरसता, स्वरूप की हानि आदि ऐसे बिंदु हैं जो खिलाड़ियों के व्यक्तित्व और खेलकूद से जुड़े होते हैं। हां, खिलाड़ियों की कुछ विशिष्ट समस्याएं खेल या प्रशिक्षण के दौरान आ सकती हैं जिससे पुरुष तथा महिला खिलाड़ियों में कुछ विशिष्ट मनोवैज्ञानिक समस्याएं

पैदा हो सकती हैं। जैसे यौन भावना, आहार, आरोग्यता, शारीरिक व मानसिक क्षति आदि। ये सब केवल खेल चिकित्सा के महत्वपूर्ण विषय हैं।

रोग और अशक्तता

किसी भी खिलाड़ी के लिए रोग और अशक्तता चाहे वह जन्मजात हो या जन्मोत्तर, उसकी शारीरिक क्षमता पर असर डालता है। आमतौर पर खेल का प्राथमिक प्रयोजन है मनोरंजन तथा फिटनेस लेकिन अशक्त व्यक्तियों के लिए खेल का एक और महत्वपूर्ण प्रयोजन क्षमता पुनः प्राप्ति का प्रयास है। वास्तव में खेल का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए - आनंद। अतः रोगियों को खेल-कूद में मज्जा लेने के लिए प्रोत्साहित करना तथा उसे शारीरिक लाभ दिलाना, यह दोनों लक्ष्य होने चाहिए। इसके लिए वैसे खेल का चयन करना चाहिए जिससे शरीर और मन दोनों तैयार हों। इससे एकाग्रता, अर्धवसाय और दृढ़ता उत्पन्न होती है। यह मान्यता काफ़ी पहले से चली आ रही है कि स्थानीय और सामान्य दोनों प्रकार की योग्यता की पुनः प्राप्ति में व्यायाम व खेल का मौलिक महत्व है। एक स्वस्थ व्यक्ति तथा अशक्त व्यक्ति के लिए प्रशिक्षण का मूल सिद्धांत एक-सा ही है। अर्थात् शक्ति, गति, नम्यता, सहनशीलता, दक्षता एवं मानसिक क्षमता का विकास।

नेत्रहीन एवं अंग-भंग वाले व्यक्तियों के लिए भी खेल उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने अन्य सामान्य व्यक्ति के लिए। नेत्रहीनों के खेल में सबसे पहली आवश्यकता यह है कि ये खेलकूद विशेषकर उनके लिए तथा पास खड़े दर्शकों के लिए सुरक्षित हों। यदि नेत्रहीनों के साथ कोई सहयोग करनेवाला हो तो बहुत से खेलों को सुरक्षित बनाया जा सकता है। अंग-भंग लोगों के लिए भी अधिकांश खेल खेले जा सकने वाले होते हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर के एथलीट केरोली टेकाक्स तथा डगलस बेडर इसके उदाहरण हैं। आमतौर पर अंग-भंग का कारण साधारण अभिघात की तुलना में एथरोसकलेरोसिस काफ़ी अधिक सीमित करने वाला होता है। दृष्टिहीन व्यक्ति भी खेल में अच्छा करते हैं। ऐसे लोगों के लिए कई खेल विकसित किए गए हैं जो पहियेदार कुर्सी पर बैठकर खेले जाते हैं। इनमें धनुर्विद्या, टेबल टेनिस, बॉस्केट बॉल, तैराकी, असिक्रीड़ा, स्नूकर तथा विभिन्न प्रकार की दौड़ शामिल हैं। ऐसे ही पक्षाघात ग्रस्त लोगों,

गतिविधिमग्नस्त लोगों के लिए भी खेल के प्रावधान हैं।

मानसिक रोगियों तथा अशक्त खिलाड़ियों के लिए खेल इनके मनोगति महत्व के अनुसार चुना जा सकता है। अशक्त लोगों के खेल में भाग लेने के प्रति आम लोगों की प्रतिक्रिया भी महत्वपूर्ण होती है। विशेषज्ञों को इस बात पर गंभीरता और संवेदनशीलता से ध्यान देना चाहिए।

चिकित्सा

खेल चिकित्सा में एक कठिनाई अक्सर आती है जब खिलाड़ियों में दुर्घटना के उपरांत हुई क्षति और रोग के बीच सीमा-रेखा नगण्य होती है। रोग के दैनिक सामान्य ख़तरे विशेषकर संक्रमण के ख़तरे के अलावा एथलीट होने का जोखिम भी उठाना पड़ता है। जैसे यदि कोई व्यक्ति या खिलाड़ी बहुत क्रियाशील है तो उसका अग्र पोलियो बहुत तीव्र रूप धारण कर लेता है। ऐसे में यदि प्रशिक्षण के दबाव को नियंत्रित नहीं किया गया तो इस एथलीट की स्वाभाविक संक्रमण प्रतिरोध क्षमता घट सकती है और अन्य अतिरिक्त घटकों से स्थिति और बिगड़ सकती है। खेल चिकित्सा में रोग की रोकथाम का पहला सिद्धांत यह है कि एथलीट या खिलाड़ी इस बात से सुरक्षित हो जाए कि उसका सामान्य स्वास्थ्य बहुत ऊंचे स्तर का है, जिससे वह कम-से-कम जोखिम और हानिकारक स्थितियों का मुकाबला करते हुए प्रशिक्षण और प्रतियोगिता में भाग ले सके। रोग विरोधी इम्यूनीकरण से ऐसे कई रोग नियंत्रित हो गए हैं जो कभी मानव जीवन के लिए घातक माने जाते थे, जैसे- डिप्थीरिया, चेचक, टिटनेस आदि रोग अब काफ़ी हद तक नियंत्रित हो चुके हैं। आजकल खिलाड़ियों का विदेश आना-जाना बढ़ा है इसलिए भी रोग प्रतिरोध ज़रूरी है। विदेशों में कई महामारियों के ख़तरे भी देखे जा रहे हैं। स्वाइन फ्लू, सार्स, एंथ्रेक्स, एचआईवी/एड्स, मैमिजोकाक्सिमिया, बीएसई आदि अनेक महामारियां भी अंतरराष्ट्रीय एथलीटों के लिए ख़तरनाक हैं। अंतरराष्ट्रीय आवाजाही के लिए भी कुछ टीके अनिवार्य कर दिए गए हैं ताकि महामारियों के संक्रमण से खिलाड़ियों व लोगों को बचाया जा सके। इसके अलावा खेल चिकित्सा में खिलाड़ियों में विशेष रूप से होने वाले रोगों का इलाज भी महत्वपूर्ण है। जैसे क्रैम्प, पार्श्वशूल, बिल्डिंग, एलर्जी, एनिमिया, पास्टूरल, डिफ्रेक्ट्स आदि। ये सभी

रोग समुचित उपचार से ठीक व नियंत्रित किए जा सकते हैं।

खेल चिकित्सा में प्राथमिक उपचार एवं तत्काल उपचार का विशेष महत्व है। इसमें निम्न बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए :

- प्रत्येक घायल खिलाड़ी एक इंसान है महज रोगी नहीं।
- उपचार के कोई स्थापित नियम नहीं होते उसे परिस्थिति के अनुसार तय करना पड़ता है।
- उपचार का उद्देश्य सामान्य कार्यक्षमता को यथासंभव शीघ्र प्राप्त करना तथा क्षति को नियंत्रित करना है।
- यथासंभव योग्यता स्तर को बनाए रखना चाहिए।
- बाहरी घाव को भरने से पहले ही क्रियात्मक क्षमता की पुनःप्राप्ति की जानी चाहिए।
- रोगी या पीड़ित खिलाड़ी को आत्मविश्वास शीघ्र पुनः प्राप्त हो जाए।
- जब तक प्रतियोगिता एवं प्रशिक्षण के लिए सामान्य स्थिति बहाल न हो जाए तब तक चिकित्सा अधूरी है।
- प्रभावी उपचार के लिए टीम भावना जरूरी है।
- योग्य बने रहना एक पूर्णकालिक कार्य है। दुर्घटना में क्षति की चिकित्सा के लिए सदा प्रामाणिक तकनीक व तरीके ही इस्तेमाल करने चाहिए। पारंपरिक चिकित्सा जैसे, गर्म सेंक, बर्फ का सेक, स्टीम बाथ, मालिश, अल्ट्रावायलेट किरण से उपचार, डायथर्मी, वायवरेटर, एक्स्प्रेसर, एक्स्पंपंक्चर व कई देसी दवाइयां, होमियोपैथी आदि सर्वथा सुरक्षित माध्यम हैं बशर्ते कि यह चिकित्सा संबंधित विशेषज्ञ की निगरानी में हो।

समुचित पोषण

खेल चिकित्सा में एथलीट या खिलाड़ी का समुचित पोषण बेहद अहम पहलू है। इसके अंतर्गत पोषण के सभी तत्व जैसे- कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और विटामिन तथा लवण आदि का समावेश है। खिलाड़ियों के लिए प्रोटीन मौलिक और महत्वपूर्ण तत्व है। इसका विशेष महत्व इसलिए है कि इसमें अनेक एमिनो एसिड पाए जाते हैं जो बेहद जरूरी हैं और उसे शरीर में संश्लिष्ट नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए फेनिल एलेनिन, मेकाईओनीन, ट्रीटाफ्रान आदि। ये कोशिकाओं की संरचना एवं रक्त वर्णकों के निर्माण में सहायक होते हैं। ये शरीर



में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने तथा कई मामलों में ऊर्जा के बेहतर स्रोत हैं। कार्बोहाइड्रेट अपेक्षाकृत जटिल जैव तत्व हैं जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने हैं। ये ऊर्जा के सीधे स्रोत हैं। वसा भी शरीर के लिए जरूरी तत्व है और कई ऊतकों के निर्माण के लिए आवश्यक है।

एथलीट या खिलाड़ी के लिए आमतौर पर 3,000 से 3,500 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है जिसे विभिन्न भोजन स्रोतों से प्राप्त किया जाता है। राष्ट्रीय पोषण संस्थान, हैदराबाद की अनुशांसा के अनुसार एक सामान्य एथलीट के भोजन में प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट का अनुपात 1:1:4 होना चाहिए।

जल शरीर का अत्यंत महत्वपूर्ण घटक है। जो शरीर के भार का लगभग 70 प्रतिशत होता है। एथलीटों को शीतोष्ण जलवायु में प्रतिदिन 5 लीटर या इससे ज्यादा पानी पीना चाहिए। 70 किलोग्राम वजन वाले एथलीट के लिए शरीर से 2 लीटर पानी का क्षय उसकी शारीरिक प्रक्रिया में रुकावट डालने के लिए काफी है। इसके अतिरिक्त एथलीट को रोजाना 4 ग्राम नमक की जरूरत पड़ती है। नमक के अतिरिक्त स्वास्थ्य के लिए अन्य आवश्यक लवणों में लोहा, पोटेशियम, कैल्शियम, फ़ास्फ़ोरस आदि भी होने चाहिए। इसके साथ-साथ विभिन्न विटामिन भी आवश्यक हैं। जैसे- विटामिन ए, बी1, बी2, निकोटिनिक अम्ल, विटामिन सी, डी, ई एवं के। खिलाड़ियों का आहार ऐसा होना चाहिए जिसमें ये सारे तत्व अवश्य मौजूद हों।

खिलाड़ियों के भोजन को उनके खेल व प्रवृत्ति के अनुसार विशेषज्ञ पोषण बिज्ञानी निर्धारित करते हैं। उसमें अलग-अलग वर्ग व खिलाड़ियों के लिए उनकी जरूरतों के अनुसार भोजन का निर्धारण किया जाता है। जैसे, एथलीट एवं दौड़ में शामिल खिलाड़ियों के लिए हलके, द्रव वाले भोजन होते हैं जबकि मुक्केबाज या कुश्ती के खिलाड़ियों के भोजन में प्रोटीन व वसा की मात्रा अपेक्षाकृत ज्यादा होती है। तेज दौड़ के प्रतियोगियों को पर्याप्त पानी और ग्लूकोज देना चाहिए।

खिलाड़ियों को नशा, अल्कोहल व मादक द्रव्यों से बचना चाहिए। ये सेहत ही नहीं खिलाड़ियों की कार्यक्षमता को भी नुकसान पहुंचाते हैं।

खेल चिकित्सा में अब बड़ी संभावनाएं देखी जा रही हैं। खेलों की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ी मान्यता के बाद खेल चिकित्सकों की मांग भी बढ़ी है। कई राज्यों में तो विशेषज्ञ खेल चिकित्सकों के अभाव की वजह से उनके पद खाली हैं। दुनिया के पैमाने पर बढ़ती खेल जागरूकता की वजह से भी खेल चिकित्सकों का भविष्य उज्ज्वल है। जैसे भी खेल चिकित्सा आज की एक महत्वपूर्ण जरूरत भी है। चिकित्सा विज्ञान के विभिन्न माध्यमों जैसे एलोपैथी, होमियोपैथी, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा आदि का समन्वय कर एक 'समन्वित खेल चिकित्सा' को विकसित किया जा सकता है। □

(लेखक राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त जनस्वास्थ्य वैज्ञानिक हैं।)

ई-मेल : docarun2@gmail.com)



भारत में खेल समस्याएं और संभावनाएं

● कौशल्या बाजपेयी

राष्ट्रमंडल खेलों की तारीख निकट आ गई है और इसकी आयोजन स्थली राजधानी दिल्ली में भारी पैमाने पर नवीकरण और पुनर्निर्माण का कार्य चल रहा है। भारतीय संदर्भ में खेलों के महत्व के बारे में विचार करने का यह एक अच्छा अवसर है।

भारत ने पिछले कुछ वर्षों में खेलों के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है और अंतरराष्ट्रीय प्रसिद्धि पाई है। हाल के दिनों में इसमें एक नया आयाम जुड़ा है। राष्ट्रीय खेल कहे जाने वाले हॉकी में आठ ओलंपिक स्वर्ण पदकों के साथ भारत का शानदार रिकॉर्ड रहा है। भारत ने पुरुष हॉकी में पहला स्वर्ण पदक सन् 1928 में एमस्टर्डम में जीता था, परंतु व्यक्तिगत स्पर्धा में उसे पहला स्वर्ण पदक वर्ष 2008 के पेईचिंग ओलंपिक में निशानेबाज अभिनव बिंद्रा ने दिलवाया। ओलंपिक खेलों में भारत ने सन् 1920 से भाग लेना शुरू किया और तब से लेकर अब तक उसने चार रजत और सात कांस्य पदक जीते हैं। विश्व हॉकी में आज भारत का नौवां स्थान है। जहां तक शीतकालीन ओलंपिक खेलों का प्रश्न है, भारत ने सन् 1964 से इसमें भाग लेना शुरू किया है और अब तक कोई पदकीय सफलता नहीं मिली है।

सायना नेहवाल के अद्भुत प्रदर्शन के कारण बैडमिंटन का खेल इन दिनों सुर्खियों में है। विश्व

बैडमिंटन रैंकिंग में सायना इस समय दूसरे स्थान पर हैं। विश्व बैडमिंटन फेडरेशन ने उन्हें 2008 का 'मोस्ट प्रॉमिज़िंग प्लेयर' (सबसे अधिक संभावनाओं वाला खिलाड़ी) घोषित किया था। यह प्रसिद्धि और उपलब्धि काफी अरसे बाद प्राप्त हुई है। इससे पूर्व प्रकाश पाडुकोण ने 1980 में और पुलेला गोपीचंद ने 2001 में ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप जीतकर भारत को गौरवान्वित किया था। एक और खेल है शतरंज, जिसने हाल ही में भारत का गौरव बढ़ाया है। कहा जाता है कि शतरंज की शुरुआत भारत से ही हुई है, परंतु लोकप्रियता इसे पिछले कुछ दशकों में ही मिली है। वर्तमान विश्व चैंपियन विश्वनाथन आनंद के लगातार विश्वस्तरीय प्रदर्शन के कारण भारत को शतरंज में अच्छी प्रसिद्धि मिली है। परंतु शतरंज के उलट फुटबॉल का भारत में लंबा इतिहास रहा है। साठ के दशक तक भारत फुटबॉल में एशिया का 'पावर हाउस' माना जाता था। परंतु धीरे-धीरे, अन्य देशों के मुक़ाबले भारत में फुटबॉल का स्तर गिरता गया और इस समय भारत फीका रैंकिंग में 146वें स्थान पर है। वॉलीबॉल में स्थिति में कुछ सुधार हो रहा है। एशिया में भारत का पांचवां स्थान है और विश्व में 27वां। सन् 2003 में भारत विश्व युवा चैंपियनशिप में दूसरे स्थान पर था।

एक खेल जिसमें भारत ने अच्छा नाम कमाया वह है लॉन टेनिस। विजय अमृतराज ने भारतीय टेनिस को नयी ऊंचाइयों तक ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई वह सन् 1973 में दो ग्रांड स्लैम प्रतियोगिताओं के क्वार्टर फाइनल तक पहुंचे। लिण्डर पेस और महेश भूपति ने 1999 और 2001 में फ्रेंच ओपन का युगल खिताब जीता और 1999 में विबलडन का। पेस ने 1999 और 2003 में मिश्रित युगल का भी ग्रांड स्लैम जीता। सानिया मिर्जा जब 2005 की यूएस ओपन के चौथे दौर में पहुंची तो किसी ग्रांड स्लैम प्रतियोगिता में यह स्थान प्राप्त करने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी बनीं। लिण्डर पेस और महेश भूपति ने जोड़ी के रूप में, और अलग-अलग महिला-पुरुष जोड़ियां बनाकर विभिन्न ग्रांड स्लैम प्रतियोगिताओं में भारत को शीर्ष/दूसरा स्थान दिलाया है।

क्रिकेट में भारत ने एक टीम के रूप में और खिलाड़ियों की व्यक्तिगत उपलब्धियों के रूप में भी, एक नयी ऊंचाई हासिल की है। भारतीय क्रिकेट टीम इस समय टेस्ट रैंकिंग में प्रथम स्थान पर है और एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में दूसरे स्थान पर। सचिन तेंदुलकर, क्रिकेट इतिहास में अनेक रिकॉर्ड स्थापित कर चुके हैं। हाल ही में श्रीलंका में अपना 169वां टेस्ट खेल कर विश्व के सर्वाधिक टेस्ट मैच खेलने वाले खिलाड़ियों में

सबसे आगे खड़े हो गए हैं। उनकी उपलब्धियां क्रिकेट की समूची नयी पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। इसमें लेशमात्र का भी संदेह नहीं कि उनके उत्कृष्ट खेल ने क्रिकेट को भारत में सर्वाधिक लोकप्रिय खेल बना दिया है। उनके अलावा, सुनील गावस्कर और कपिल देव जैसे अन्य महान खिलाड़ी भी हुए हैं जिनके शानदार खेल के कारण भारतीय क्रिकेट का दबदबा विश्व क्रिकेट में बना रहा है।

परंतु ये इक्का-दुक्का और गुमनाम उपलब्धियां प्रदर्शन में निरंतरता के अभाव के कारण इस तथ्य की ओर इशारा करती हैं कि खेलों के क्षेत्र में वृहद और समर्थ मानव संसाधनों को सही मार्ग पर ले जाने की आवश्यकता है।

भारत में खेलों के सामने जो आधारभूत चुनौती है, वह यह कि यहां यह पाठ्यक्रम से इतर एक अतिरिक्त गतिविधि के रूप में देखा जाता है। प्रायः यह पाठ्यक्रम से अलग ही रहता है। विद्यालयों में शिक्षा के दबाव के कारण प्रायः खेलकूद के घंटे को दैनिक समय सारणी से बाहर कर दिया जाता है। इसके अलावा विद्यालयों का समय और उसके बाद ट्यूशन कक्षाओं के कारण बच्चों के पास मनोरंजन के लिए खेलने का कोई वक्त बचता ही नहीं तो उसे पेशे के रूप में अपनाने की बात तो काफी दूर की कौड़ी है। इस तरह प्रारंभिक अवस्था में ही खेलों में रुचि की बलि चढ़ जाती है।

दूसरे, आमतौर पर यह माना जाता है कि खेलों में करियर बड़ा अनिश्चित होता है और उनमें अच्छे अवसर नहीं मिलते। इसलिए बच्चों को पढ़ाई पर ध्यान देने का दबाव डाला जाता है, भले ही खेलों में उसकी रुचि हो या उसमें जन्मजात प्रतिभा हो, ताकि उसके जीवन में स्थायित्व सुनिश्चित किया जा सके।

तीसरे, खेलों में भेदभाव काफ़ी है और सीढ़ियां बहुत चढ़नी पड़ती हैं। बच्चे शुरू से ही क्रिकेट, फुटबॉल और टेनिस जैसे खेलों के प्रचार और शानोशौकत से अभिभूत होते हैं। इन खेलों का मीडिया में व्यापक कवरेज और उनके साथ जुड़े नाम और प्रसिद्धि, ताइक्वांडो, खो-खो या तीरंदाजी जैसे अन्य खेलों को पीछे छोड़ देते हैं। दरअसल, समस्या मीडिया में कुछ खेलों को आवश्यकता से अधिक प्रचारित करने और उनसे

जुड़े पैसों में निहित है।

यह सोचने की बात है कि हम क्रिकेट और फुटबॉल के अलावा शायद ही अन्य किसी खेल का सीधा प्रसारण रेडियो पर सुनते हों। हर्षा भोगले और मंदिरा बेदी जैसी नयी परंपरा शुरू करने वाले व्यक्तियों के मैदान में उतरने के बाद खेलों का सीधा प्रसारण भी एक लाभप्रद व्यवसाय के रूप में उभरकर सामने आया है। परंतु यह भी क्रिकेट के खेल तक ही सीमित है। इसके अतिरिक्त, इंडियन प्रीमियर लोग की जो नयी प्रवृत्ति शुरू हुई है उसके कारण अनेक बड़े-बड़े उद्योग घराने भारी निवेश के साथ मैदान में उतरे हैं। इस भारी-भरकम पैसे के कारण क्रिकेट के मौजूदा शान में और चार चांद लग गए हैं। इस तरह का निवेश अन्य खेलों में नहीं हो रहा है। इसीलिए वे युवाओं का ध्यान अपनी ओर नहीं खींच पा रहे हैं कि वे उसमें भाग ले सकें।

चौथे, जिलों और उपनगरीय क्षेत्रों में खेल परिसरों और अकादमियों की कमी के कारण बच्चों के लिए आगे बढ़ने में की समस्या पैदा हो जाती है। खेल क्लब और अकादमियां मुख्यतः महानगरों में ही होती हैं। मोहम्मद अज़हरुद्दीन, सानिया मिर्जा और सायना नेहवाल को पैदा करने वाला हैदराबाद है या फिर दिल्ली तानिया सचदेव को पैदा किया या मुंबई सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर, विनोद कांबली और अन्य को पैदा किया। ये सब महानगर हैं। परंतु इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि उपनगरीय कस्बों में रह रहे अभिभावक अपने बच्चों को पर्याप्त सुविधाएं और मार्गदर्शन नहीं दिला पाते।

पांचवें, खेलों में प्रशिक्षण के लिए भारी निवेश की आवश्यकता होती है। न केवल अकादमी में प्रवेश पाने के लिए भारी खर्च करना होता है, वर्न् खेल सामग्री, पोशाक और यहां तक कि पौष्टिक आहार के लिए भी भारी खर्च की ज़रूरत होती है। इसीलिए मध्यमवर्गीय परिवारों के बच्चों के लिए प्रायः यह प्रतिबंधित क्षेत्र होता है। गोल्फ, पोलो, बिलियर्ड्स जैसे खेल, इसीलिए अभिजात्य वर्ग के खेल माने जाते हैं।

छठे, बच्चों को प्रायः उचित मार्गदर्शन और कोचिंग नहीं मिल पाती। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी तैयार करने के लिए समुचित

रूप से सुसज्जित प्रशिक्षण केंद्रों और प्रशिक्षकों (कोच) की कमी आमतौर पर महसूस की जाती है।

प्रायः भारत में खेलों की उपेक्षा की जाती है और इसे शायद ही कभी पेशे के रूप में अपनाने के बारे में गंभीरता से विचार किया जाता हो। संभवतः यही उचित समय और प्रसंग है जब खेलों के प्रति रवैये की समीक्षा की जाए। जैसी स्थिति सामने है, वर्तमान में बुनियादी ढांचे को खास प्रोत्साहन दिया जा रहा है। दिल्ली में खेल परिसरों और स्टेडियमों का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है। परंतु सरकार को वास्तव में अपनी नीतियों की समीक्षा करने की ज़रूरत है और उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि राष्ट्रमंडल खेलों के बाद भी इन बुनियादी सुविधाओं का समुचित उपयोग होता रहे। इस संदर्भ में, भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) का उत्तरदायित्व काफ़ी बढ़ जाता है। दिल्ली में 1982 में हुए एशियाई खेलों के बाद बुनियादी ढांचों के कुशल संचालन, संधारण और सदुपयोग के लिए वर्ष 1984 में साई का गठन किया गया था। कोलकाता, बंगलुरु, गांधीनगर, चंडीगढ़, भोपाल और इंफाल में इसके 6 क्षेत्रीय केंद्र हैं। परंतु, भारत जैसे विशाल देश के लिए, साई के पास ढेर सारे उपक्षेत्रीय केंद्र होने चाहिए ताकि देश के विभिन्न कोनों से श्रेष्ठतम प्रतिभाओं को खोजा जा सके। इसके अतिरिक्त राज्य सरकारों को भी राज्य स्तर पर इस तरह की एजेंसियां गठित करने के लिए आगे आना चाहिए ताकि जिला स्तर पर बेहतर प्रतिभाओं की खोज की जा सके। उन्हें समुचित प्रशिक्षण और मार्गदर्शन के जरिये आगे बढ़ाया जा सकता है।

इस दिशा में महत्वपूर्ण क़दम उठाते हुए, वर्ष 2001 में राष्ट्रीय खेल नीति की घोषणा की गई। खेलों को और व्यापक स्वरूप देने तथा उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के इरादे से इस नीति की योजना बनाई गई थी। परंतु, इस नीति पर उचित रूप से अमल नहीं हो रहा है। केंद्र सरकार ने सरकारी और गैर-सरकारी स्रोतों से संसाधन जुटाने के लिए राष्ट्रीय खेल विकास कोष की स्थापना की है। निजी, कार्पोरेट क्षेत्र और प्रवासी भारतीय भी खेलों को बढ़ावा देने के लिए इसमें योगदान कर सकते हैं। इसे आकर्षक

बनाने के लिए सरकार इसमें दी गई राशि को आयकर में शत-प्रतिशत की छूट देती है। राष्ट्रीय चैंपियनशिप और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताएं आयोजित करने तथा विदेशों में अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने, कोचिंग कैंप आयोजित करने, खेल उपकरण आदि मंगाने के लिए भी सरकार राष्ट्रीय खेल संघों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है।

खेल और युवा मामलों के मंत्रालय की योजनाएं अधिकतर राष्ट्रीय स्तर तक सीमित रहती हैं और वे राज्य स्तर पर खेलों के प्रति उत्साह जगाने में असमर्थ होती हैं। इस दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है महिलाओं के लिए राष्ट्रीय खेल चैंपियनशिप का आयोजन। इस योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिताओं के पूर्व ब्लॉक और जिला स्तर पर प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं, जिसके लिए राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को वित्तीय सहायता दी जाती है। परंतु दी जाने वाली राशि बहुत कम होती है। इस योजना के अंतर्गत दी जाने वाली सहायता राशि निम्न प्रकारेण हैं :

- ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिता : 1,000 रुपये प्रति ब्लॉक।
 - जिला स्तरीय प्रतियोगिता : 3,000 रुपये प्रति जिला।
 - राज्य स्तरीय प्रतियोगिता: 10,000 रुपये प्रति राज्य।
 - छोटे राज्यों और केंद्रशासित प्रदेश : 5,000 रुपये प्रति राज्य अथवा केंद्रशासित प्रदेश।
- सरकार ने पीवाईकेकेए योजना के अंतर्गत पूर्वोत्तर राज्यों में खेलों को बढ़ावा देने की योजना शुरू कर एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इस योजना के तहत जिलास्तरीय प्रतियोगिता के लिए प्रति जिले 50,000 रुपये दिए जाते हैं और राज्यस्तरीय प्रतियोगिता के लिए प्रत्येक खेल के लिए 75,000 रुपये दिए जाते हैं। राष्ट्रमंडल देशों में युवाओं के विकास को प्रोत्साहन देने के लिए 1974 में राष्ट्रमंडल युवा कार्यक्रम अस्तित्व में आया। अंतरराष्ट्रीय चैंपियनशिप के साथ-साथ खेल उत्सव के लिए और अधिक प्रयासों की आवश्यकता है। इससे स्थानीय और क्षेत्रीय सद्भाव को बढ़ावा मिलेगा।

भारत में सरकार को नौकायन या केरल के वल्लमकली जैसे क्षेत्रीय खेलों को प्रोत्साहित करना चाहिए। यह अचरज की बात है कि भारत के विभिन्न भागों में फ्लोरबॉल, रग्बी, बैडी,

नेटबॉल, कोर्फबॉल, लैक्रोस जैसे अनेक प्रकार के खेल खेले जाते हैं, परंतु उनके बारे में लोगों को मुश्किल से ही कोई जानकारी होती है या वे उनमें भाग लेते हैं। प्रायः वे स्थानीय स्तर पर ही सीमित होते हैं; जैसे- आइस हॉकी अधिकतर जम्मू-कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में ही खेली जाती है। इसी प्रकार बैडी हिमाचल प्रदेश और उत्तर भारत के अन्य क्षेत्रों में खेला जाता है। लैक्रोस पूर्वोत्तर के मेघालय राज्य में खेला जाता है और देश के अन्य भागों में यह लोकप्रिय नहीं हो पाया है। खेल संवर्धन कार्यक्रम के तहत इन खेलों में लोगों की दिलचस्पी पैदा करने के लिए कृत्रिम ढांचे स्थापित किए जाएंगे और अन्य क्षेत्रों से लोगों को आकर्षित किया जाएगा।

इसके अलावा, जिम्नास्टिक, टेबल टेनिस, कैरम, भारोत्तोलन, पावर लिफ्टिंग, बिलियर्ड्स और स्नूकर जैसे इंडोर खेलों को भी प्रोत्साहित करना होगा। कुछ घर के अंदर खेले जाने वाले खेल तो विकलांग व्यक्तियों के लिए प्रोत्साहन का काम कर सकते हैं। वे उनमें भाग लेकर अपनी प्रतिभाओं को सही दिशा दे सकते हैं। सरकार को ऐसी योजनाएं शुरू करनी चाहिए जो अधिकांश जनसंख्या का मनोबल बढ़ाने के साथ-साथ आर्थिक रूप से भी उपयोगी हों।

इस तरह की योजनाएं चलाने के लिए पैसे की जरूरत होती है और यह सरकारी तथा निजी क्षेत्र की भागीदारी से जुटाया जा सकता है। उद्योग घराने आगे आकर इन खेलों के साथ-साथ स्कुबा डाइविंग, रॉक क्लाइंबिंग (शिलारोहण), माउंटन बाइकिंग (पर्वतों पर साइकिल चालन) आदि जैसे साहसिक खेलों के लिए भी निवेश कर सकते हैं। इन खेलों की ओर देसी और विदेशी युवा बड़े पैमाने पर आकर्षित हो रहे हैं। लाभकारी व्यावसायिक संभावनाएं और सरकार की ओर से दी जाने वाली वित्तीय सुविधाओं से अनेक लोग लाभावित होंगे।

इस संदर्भ में मीडिया को नये जोश और उत्साह के साथ मदद करने के लिए आगे आना होगा। उसे अपनी भूमिका फिर से परिभाषित करनी होगी; विशेषकर उसे केवल क्रिकेट और फुटबॉल जैसे खेलों के प्रसारण तक सीमित नहीं रहना होगा, बल्कि अलग प्रकार के खेलों को भी प्रोत्साहित करना होगा। खेल चैनलों को विभिन्न कार्यक्रमों को और अधिक चित्ताकर्षक ढंग से प्रस्तुत करना होगा ताकि अधिक से अधिक लोग इन खेलों को देखें। इससे देश के दूरस्थ क्षेत्रों में

भी खेलों के प्रति रुचि बढ़ेगी। बदले में इसमें और अधिक निवेश बढ़ेगा। ज्यादा पैसा आने से अधिक से अधिक लोग इन खेलों में भाग लेने के लिए आगे आएंगे।

परंतु, इस संदर्भ में कोचों और अभिभावकों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। और अधिक पैसे आने से उनका वित्तीय भार कम हो जाएगा और इससे उन्हें अपने बच्चों में खेलों के प्रति रुचि को आगे बढ़ाने में कोई एतराज नहीं होगा। इसके साथ ही, सरकारी सहायता प्राप्त अकादमियां उन स्थानों पर खोली जा सकती हैं जहां पुराने खिलाड़ी कोचिंग के लिए उपलब्ध हों। इससे युवा प्रतिभाओं को अपने मार्गदर्शक का अनुसरण करने की प्रेरणा मिलेगी और वे अपने गुरुओं की सफलता को दोहरा सकेंगे।

खेलों में युवाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने में पुरस्कारों का प्रायोजन काम आ सकता है। ये पुरस्कार न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि जिला एवं ब्लॉक स्तर पर भी प्रायोजित कराए जाने चाहिए। इससे छात्रों को खेलों को अपनाने के लिए नैतिक और आर्थिक प्रोत्साहन मिलेगा।

भारत की जनसंख्या के 35.4 प्रतिशत लोग शून्य से 14 वर्ष तक की आयु वर्ग के हैं। उपर्युक्त वर्णित उपायों से युवाओं को बड़े पैमाने पर खेलों की ओर आकर्षित किया जा सकता है। उनकी खेल प्रतिभा को उचित दिशा दी जा सकती है। इस प्रकार, भारत न केवल मानव संसाधन के मान से संपन्न है बल्कि जनसंख्या के मान से भी यह लाभप्रद स्थिति में है। चीन, अमरीका, रूस, कोरिया, जापान और अन्य अनेक अग्रणी देशों से मुक्काबला करने में भारत पूरी तरह सक्षम है। भारत इस समय राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करते हुए एक महती जिम्मेदारी को निभा रहा है। परंतु असली चुनौती प्रदर्शन में उच्च स्तर हासिल करने की है। इससे न केवल हमारे मानव संसाधन की प्रचुर संभावनाओं को उचित दिशा मिल सकेगी, बल्कि खेलों में योगदान हमें विश्व मंच पर स्थापित कर देगा। इन खेलों का सफल आयोजन भारत को एक ऐसी शक्ति बना देगा जिसकी अनदेखी नहीं की जा सकती। □

(लेखिका नयी दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में शोध छात्रा हैं।
ई-मेल : kaushalya.bajpayee@gmail.com)

प्रशिक्षण भावी खेल प्रबंधकों का

● आदित्य कुमार

परामर्शदात्री फर्म प्राइसवाटरहाउस कूपर्स ने हाल ही में यह भविष्यवाणी की थी कि वैश्विक खेल बाजार वर्ष 2012 तक वर्तमान मूल्यानुसार 37 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 1 खरब 41 अरब अमरीकी डॉलर के बराबर पहुंच जाएगा। खेल हमारे शरीर और मन के समग्र विकास में अद्भुत अहम भूमिका अदा करते हैं। इस पुरानी अवधारणा में पिछले दशकों में भारी बदलाव आया है। इक्कीसवीं शताब्दी के इस शुरुआती दौर में स्पष्ट हो गया है कि ढेरों पैसा, लैमर, नाम, प्रसिद्धि, मीडिया में स्थान बनाना और प्रशंसकों की भीड़ आज के खेल के अभिन्न अंग बन गए हैं।

खेल उद्योग में इस अभूतपूर्व तेजी से आए परिवर्तन ने एक नयी वैश्विक प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया है। खेल प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिग्री के अलावा खेल के व्यापार से जुड़े अन्य अनेक विषयों में विशेषज्ञता हासिल करने की प्रवृत्ति बढ़ी है। अमरीका और पश्चिमी यूरोप के अनेक देशों में खेल बिरादरी ने बड़ी गर्मजोशी से इसे अपनाया है। खेल प्रबंधन में खेल के मैदान और उसके बाहर की वे सभी गतिविधियां शामिल हैं जो किसी भी खेल स्पर्धा को सफल बनाने के लिए की जाती हैं। इन देशों में खेल और खिलाड़ियों के हितों की देखभाल के लिए अनेक पेशेवर खेल प्रबंधन कंपनियां उभरकर सामने आई हैं।

भारत में खेल प्रबंधन एक सर्वथा नयी धारणा के रूप में उभरा है और इसकी शुरुआत भी अच्छी हुई है। पिछले कई वर्षों से भारतीय खेल वृत्तिजीवी रवैये की कमी, अधिकारों और राजनीतिक प्रभाव के दुरुपयोग के शिकार रहे हैं।

परंतु भारतीय खेलों में व्यावसायिक रवैये के पदार्पण से अब धीरे-धीरे इनमें बदलाव आ रहा है। विश्व की सबसे संपन्न खेल संस्था— भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड ने पिछले वर्ष एक पूर्णकालिक सीईओ की नियुक्ति कर इस दिशा में एक कदम रखा है। अखिल भारतीय फुटबॉल संघ भी राष्ट्रीय फुटबॉल लीग में खेलने वाले सभी क्लबों के लिए पूर्णकालिक वैतनिक मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) की नियुक्ति अनिवार्य कर रहा है ताकि इन क्लबों का प्रबंधन बेहतर ढंग से हो सके।

खेलों की दुनिया भी बाजार के रूप में भारत की महती संभावनाओं को पहचानने लगी है। यूरोप और उत्तरी अमरीका के संतृप्त बाजारों से परे भारत में ही सबसे अधिक संभावनाएं दिखाई देती हैं। भारत में बढ़ते आकर्षण के कारण यहां के मध्यवर्गीय लोगों की संख्या में वृद्धि से जुड़ा बाजार, खर्च के लिए अतिरिक्त पैसा और समय, खेल के बारे में रुचि पैदा करने वाले टेलीविजन से युक्त परिवारों की संख्या में त्वरित वृद्धि और विज्ञापनों की दुनिया में तीव्र विकास से अविकसित और लाभप्रद बाजार हैं जो स्थानीय और अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के निशाने पर हैं। भारत में प्रायोजन का बाजार अनुमानतः प्रतिवर्ष 25 करोड़ अमरीकी डॉलर का और टेलीविजन अधिकार 35 करोड़ अमरीकी डॉलर का है और दोनों में तेजी से वृद्धि हो रही है।

जहां तक हॉकी, टेनिस और एथलेटिक्स आदि खेलों का प्रश्न है उनसे संबंधित शीर्ष संस्थाएं भी खेलों में पेशेवर अंदाज लाने की कोशिश कर रही हैं। वर्तमान परिस्थिति से तो ऐसा स्पष्ट है कि विभिन्न खेल संघों के सुचारू

संचालन के लिए पेशेवर दृष्टिकोण वाले खेल प्रबंधकों की सेवाओं और विशेषज्ञता की आवश्यकता शिद्दत से महसूस की जाएगी। खेल प्रबंधन कंपनियां भी इसी प्रकार के पेशेवर नज़रिये वाले विशेषज्ञों की तलाश में रहती हैं ताकि भविष्य में खेलों का समग्र विकास और उनका बेहतर प्रबंधन हो सके। राष्ट्रमंडल खेल 2010 की आयोजन समिति आज जिस अव्यवस्था से गुजर रही है उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि यदि भारत को अंतरराष्ट्रीय मंच पर प्रतिस्पर्धा में बने रहना है तो इसके लिए पेशेवर विशेषज्ञ व्यवस्था अपनाना ज़रूरी है।

भावी खेल सितारों को प्रशिक्षित करने से ही उस स्तर तक पहुंचा जा सकता है। विश्व के अनेक देशों में खेल प्रबंधन शिक्षा को सफलतापूर्वक अपनाया जा चुका है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस तरह की शिक्षा 50 से भी अधिक वर्षों पहले अपनाई जा चुकी है और जो लोग खेल को ही अपना करियर बनाने का स्वप्न देखते हैं उनकी संख्या दिनोदिन बढ़ती जा रही है। खेल प्रबंधन की शिक्षा अमरीका के शीर्ष विश्वविद्यालयों में दी जाती है। न्यूयार्क और कोलंबिया विश्वविद्यालय इनमें प्रमुख हैं। सामान्यतः इनमें अमरीकी खेल उद्योग से संबंधित पाठ्यक्रम पर जोर दिया जाता है। एनबीए, एनएफएल और एमएलबी जैसे शीर्षस्थ अमरीकी खेल लीगों में इन पाठ्यक्रमों की पृष्ठभूमि वाले प्रबंधकों को ही लिया जाता रहा है। ऑस्ट्रेलिया में भी अनेक प्रकार के पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं जो अधिकतर मेलबर्न में ही केंद्रित हैं। डीकिन विश्वविद्यालय के खेल प्रबंधन पाठ्यक्रम में राजनीतिक प्रबंधन, विपणन, वित्त और कानून की शिक्षा दी जाती है। अंतरराष्ट्रीय

खेल संघों और एजेंसियों के प्रमुख केंद्र स्विट्जरलैंड में खेल प्रबंधन में जो दो स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं उनकी विश्व में बड़ी प्रतिष्ठा है। लुसान स्थित अंतरराष्ट्रीय खेल विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अकादमी में मास्टर ऑफ स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन का पाठ्यक्रम अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आईओसी) की सहायता से चलाया जाता है। इसके अतिरिक्त, फीफा मास्टर प्रोग्राम को भी अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा प्राप्त है। फीफा मास्टर अर्थात 'इंटरनेशनल मास्टर इन मैनेजमेंट, लॉ एंड ह्यूमैनिटीज़ ऑफ स्पोर्ट्स' पाठ्यक्रम तीन यूरोपीय विश्वविद्यालयों की सहभागिता में चलाया जाता है। प्रत्येक विश्वविद्यालय अलग-अलग विधाओं में शिक्षा प्रदान करता है। ब्रिटेन के मॉफोर्ट विश्वविद्यालय में मानविकी की, इटली के एसडीए बोकोनी विश्वविद्यालय में प्रबंधन की और स्विट्जरलैंड के न्यूचैटेल विश्वविद्यालय में कानून की शिक्षा दी जाती है।

अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक परिषद के खेल निदेशक क्रिस्टोफर ड्यूबी का कहना है कि विश्व के उभरते खेल उद्योग को अपने-अपने विषयों में पारंगत लोगों की आवश्यकता है। आने वाले समय में इनकी मांग बढ़ती ही जाएगी। उनके शब्दों में कहें तो अनेक वर्षों से हम आईओसी के विभिन्न विभागों में प्रशिक्षणार्थियों को आमंत्रित करने की नीति अपना रहे हैं। हमें लगता है कि आईओसी जहां युवाओं को अपना करियर शुरू करने का शानदार अवसर देती है, वहीं उनकी नयी ऊर्जा और नये विचारों से लाभ भी उठाती है। फीफा मास्टर और एआईएसटीएस के बीच जो संबंध है वह हमारे लिए बहुत उपयोगी रहा है क्योंकि इस व्यवस्था के फलस्वरूप प्रतिवर्ष समर्पित और सुयोग्य खेल प्रबंधकों का एक नया स्नातक वर्ग निकलकर सामने आ रहा है। ये खेल स्नातक अनेक अंतरराष्ट्रीय खेल संघों के अलावा अपने यहां की राष्ट्रीय खेल संस्थाओं की सेवा कर रहे हैं। खेल आज का उभरता उद्योग है और निश्चय ही प्रत्येक स्तर पर अधिक-से-अधिक कुशल लोगों की आवश्यकता है।

फ्रांस में खेल प्रबंधन में अनेक उच्चस्तरीय पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं। यूरोमेड मारसाई द्वारा अंतरराष्ट्रीय खेल एवं स्पर्धा प्रबंधन में दी जाने वाली एमएस की मास्टर डिग्री में खेल कानून, खेल स्पर्धाओं की मार्केटिंग और ब्रांडिंग तथा

स्पर्धा रणनीति की शिक्षा दी जाती है। इस द्विभाषी (अंग्रेजी और फ्रेंच) पाठ्यक्रम में 6 महीने तक कक्षाओं में शिक्षा दी जाती है और 6 महीने व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाता है।

यूरोपीय विश्वविद्यालय के परिसर अनेक देशों में हैं। बार्सीलोना स्थित इसके स्पेनी परिसर में खेल प्रबंधन में एमबीए की डिग्री दी जाती है। इस पाठ्यक्रम में मुख्यतः खेलों की मार्केटिंग, वित्तीय प्रबंधन, नैतिकता और सामाजिक विषय, मीडिया के साथ संबंध और खेल प्रसारण के विषय शामिल हैं। यूरोप में यूनाइटेड किंगडम (ब्रिटेन) खेल संबंधी विषयों का प्रमुख अध्ययन केंद्र है। यहां के अनेक विश्वविद्यालयों में खेलों के विभिन्न पहलुओं में प्रबंधन की विशेषज्ञता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। लॉफब्रो विश्वविद्यालय इस क्षेत्र में अग्रणी है। जर्मनी, दक्षिणी अमरीका, एशिया और अन्यत्र भी इसी प्रकार के पाठ्यक्रमों के अनेक विकल्प उपलब्ध हैं। अनेक अल्पकालिक पाठ्यक्रमों के अलावा सुदूर शिक्षा के कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं। खेल कंपनियों और अंतरराष्ट्रीय खेल संघ इन विश्वविद्यालयों से डिग्री प्राप्त करने वालों को अपने यहां भर्ती कर रहे हैं। खेल संघों के अलावा, खेल उद्योग के सभी क्षेत्रों की कंपनियों (एजेंसियां, परामर्शदात्री, परिधान निर्माता, लीग, क्लब आदि) भी विविध पाठ्यक्रमों के स्नातकों को अपने यहां काम पर रख रहे हैं। इन पाठ्यक्रमों में उन प्रत्याशियों को वरीयता दी जाती है जिन्हें खेल उद्योग में थोड़ा-बहुत कार्यानुभव हो, परंतु यह अनिवार्य नहीं है। इन संस्थाओं का दावा है कि उनके औसतन 70 प्रतिशत छात्रों को खेलों में रोजगार मिला हुआ है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अनेक प्रकार के पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं एवं अनेक तरह की डिग्रियां दी जाती हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संपर्क के अवसर मुहैया कराए जाते हैं तथा छात्रवृत्तियां और फ्रीस की पेशकश की जाती है। हाल ही में अहमदाबाद के भारतीय प्रबंधन संस्थान आईआईएमए ने भी घोषणा की है कि वह वर्ष 2010-11 के शिक्षा सत्र से खेल संगठनों के व्यावसायिक प्रबंधन का पाठ्यक्रम पीएमएसओ शुरू करने की योजना बना रहा है। पीएमएसओ पाठ्यक्रम के बारे में (आईआईएमए) के निदेशक समीर बरुआ का कहना है कि खेलों के प्रबंधन में उत्तम प्रतिभाओं की अच्छी मांग है और विश्वभर में यह अपने

आप में एक उद्योग बन गया है। भारत में इस नये प्रकार के कौशल के बारे में अब जागृति पैदा हो रही है। हमारी ओर से खेलों के प्रबंधन को पेशेवर अंदाज़ देने की दिशा में यह पहला प्रयास है। पीएमओ पाठ्यक्रम संस्थान के प्रबंधन विकास कार्यक्रम (एमडीपी) 2010-11 का एक अंग है।

खेल प्रबंधन में स्नातकोत्तर (डिप्लोमा पीजीडीएसएम) भारत के कुल दो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों में दिया जाता है। तमिलनाडु के कराईकुडी स्थित अलगप्पा विश्वविद्यालय में एकवर्षीय पीजीडीएसएम चलाया जाता है। नयी दिल्ली के इंदिरा गांधी शारीरिक शिक्षा खेल विज्ञान संस्थान में भी यही डिप्लोमा पाठ्यक्रम चलाया जाता है। निजी क्षेत्र के अनेक कॉलेज और संस्थाएं भी आज खेल प्रबंधन में डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू कर रही हैं।

कोलकाता स्थित भारतीय समाज कल्याण एवं व्यापार प्रबंधन के नवल टाटा खेल प्रबंधन उत्कृष्टता केंद्र में खेल प्रबंधन में एकवर्षीय पूर्णकालिक स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम चलाया जाता है। संस्थान द्वारा दिए जाने वाले इस डिप्लोमा को कलकत्ता विश्वविद्यालय द्वारा वर्ष 2010-11 के सत्र में एक पाठ्यक्रम के रूप में संबद्ध किए जाने की संभावना है। इस कार्यक्रम में खेल उद्योग की संरचना, आर्थिक प्रभाव, संगठन, विपणन, वित्त पोषण के साथ-साथ खेलों में वर्तमान प्रवृत्तियों और खेलों तथा मीडिया के बीच संबंधों के बारे में पेशेवर अनुभव मुहैया कराने का प्रयास किया जाता है। पाठ्यक्रम की संरचना में कानून और नियमों की शिक्षा भी निहित है जिसे सभी मनोरंजन और खेल संगठनों को मानना पड़ता है ताकि खेल उद्योग के बहुमुखी परिप्रेक्ष्य का ज्ञान हो सके।

स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए दृढ़ संकल्प, समय और पर्याप्त धन के निवेश की इच्छा की आवश्यकता होती है। शिक्षा पर भारी व्यय के अलावा एक वर्ष या उससे भी अधिक समय के लिए कार्य और कमाई को छोड़ना पड़ता है। प्रत्याशी को कड़ी स्पर्धा का सामना करना पड़ता है। तमाम पाठ्यक्रमों में आवेदनकर्ताओं में से औसतन केवल 25 या 30 प्रतिशत लोगों के आवेदन ही स्वीकार किए जाते हैं। □

खेल नीति, विकास और शिक्षा

● कौशलेन्द्र प्रपन्न

राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा, 2005 में खेल के महत्व को स्वीकार करते हुए 'स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा' शीर्षक तीसरा अध्याय शामिल किया गया है। इस अध्याय में जो भी सुझाव दिए गए हैं वे खेल स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा को ध्यान में रखकर हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या खेल, स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा में कोई अंतर हमारे शैक्षिक नियामकों को नहीं दिखता?

प्रेमचंद की कहानी 'गिल्ली डंडा' में खेल के अंदरूनी भावनात्मक रेशे को उधेड़ा गया है। इस कहानी में खेल की सच्ची भावना क्या हो, हार या जीत के बाद खिलाड़ी का बर्ताव कैसा हो आदि पर प्रेमचंद ने बड़ी ही गंभीरता से चर्चा की है। प्रेमचंद लिखते हैं, जीत की भावना में खिलाड़ी भूल जाता है कि हारने वाला भी उस खेल में सहभागी था। खेल में एक की जीत और दूसरे की हार तो तय है। जब तक एक हारेगा नहीं तब तक दूसरे की जीत कैसे हो सकती है? प्रेमचंद आगाह करते हैं कि खेल में जो जीत के बाद लापरवाह हो जाते हैं, इस गुमान में कि मैं तो विजेता हूँ, मुझे कोई पछाड़ नहीं सकता और अभ्यास छोड़ देते हैं ऐसे दंभी खिलाड़ी को धोबी पाट देने वाले बहुत जल्द पैदा हो जाते हैं। खासकर जिसने हार का सामना किया हो हार का मुंह देखने वाले खिलाड़ी अपने जान-प्राण झोंक कर अभ्यास में लग जाते हैं ताकि अगली बार मजबूत टक्कर दे सकें। दिल में हार से उपजी प्रतिशोध की भावना सुलग रही होती है, यही आग जीत के जश्न में डूबे एक खिलाड़ी को औंधे मुंह पटकती है तो दूसरे को जीत का श्रीमाल पहनाती है।

बहरहाल, भारत में खेल को लेकर न केवल पारिवारिक स्तर पर बल्कि स्कूल, कॉलेज एवं सरकारी स्तर पर भी भेदभावपूर्ण रवैया देखा जा

सकता है। आज की तारीख में हमारे पास तक्ररीबन हर क्षेत्र के लिए एक नीति, योजना, दर्शन एवं कार्यान्वयन और सहायता राशि का प्रावधान है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण की बात यह है कि भारत में खेलों के विकास, उनकी भविष्योमुख योजना के लिए कोई गंभीर दृष्टि नजर नहीं आती। यों तो राष्ट्रीय खेल नीति का आरंभ 1984 में ही हुआ, लेकिन लक्ष्य प्राप्त करने में सफल न होने के कारण इसके पुनर्गठन की आवश्यकता महसूस की गई। इस लिहाज से राष्ट्रीय स्तर की खेल नीति में यह स्वीकारा गया कि खेलों को बढ़ावा देना तथा प्रतिभाशाली युवाओं को प्रोत्साहन देना हमारा लक्ष्य है। इसलिए सरकार ने वर्ष 2001 में एक नयी राष्ट्रीय खेल नीति लागू की जिसके तहत यह लक्ष्य तय किया गया कि खेलों का आधार व्यापक किया जाए तथा उपलब्धियों में श्रेष्ठता लाई जाए। खेलों को वैज्ञानिक तथा प्रशिक्षण संबंधी मजबूती प्रदान करना एवं जनता में खेलों के प्रति रुझान बढ़ाना आदि इस नीति में शामिल किया गया।

गौरतलब है कि खेल को अब तक शिक्षा के साथ जोड़ कर देखे जाने की प्रवृत्ति गई नहीं है। इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में खेल के लिए कोई खास सुझाव नहीं दिए गए। इतना ही नहीं, 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति से पूर्व 1964-66 एवं 1968 की शिक्षा नीति में भी खेल को लेकर

गंभीर विमर्श देखने को नहीं मिलता जबकि शिक्षा के साथ खेल का रिश्ता बेहद पुराना है। दोनों को विलगा कर नहीं देखा जा सकता। शिक्षा के महत्वपूर्ण उद्देश्यों में शामिल समता, समानता, बच्चे के सर्वांगीण विकास, लिंगानुपात, लिंगभेद मुक्त शिक्षा की गुणवत्ता पर तो जोर दिया गया लेकिन साथ ही खेल को हाशिये पर धकेलने का काम भी जारी रहा। खेल के सम्यक विकास के लिए पर्याप्त पहलकदमी की कमी साफ़तौर पर इस ओर इशारा करती है कि हम खेल को किस क्रम में कम अहमियत देते हैं। आम बजट में इसकी एक बानगी देख सकते हैं। शिक्षा में गुणात्मक सुधार को लेकर गठित (नेशनल कमीशन फॉर हायर एजुकेशन एंड रिसर्च) एनसीएचईआर या विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा में बहुआयामी सुधार के साथ ही तकनीकी शिक्षा विकास संबंधी गठित समितियों की सिफ़ारिशें हाल के दिनों में मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से जारी की गईं। इसमें विश्वविद्यालय स्तर पर सुधार के लिए गठित एनसीएचईआर के तय उद्देश्यों में तकनीक, पुस्तकालय, अध्यापन एवं शोध की स्थिति बेहतर करने को तो शामिल किया गया, लेकिन इस समिति को खेल को प्रोत्साहित करना वाजिब नहीं लगा। प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में गठित इस समिति से खेल को निकाला तो मिला



ही साथ ही सन् 1964, 1968 एवं 1986 की शिक्षा नीति में भी खेल को जगह नहीं दी गई। इनमें भी खेल को तवज्जो नहीं मिलना कम से कम हमारी प्राथमिकता की ओर ध्यान खींचता है।

भारत में खेलों के विकास के लिए खेल मंत्रालय तो है, लेकिन वर्ष 2001 की खेल नीति पर चल कर खेल को स्कूल से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक विकास करना है तो इसके लिए अहम क़दम उठाए जाने की ज़रूरत है। खेल के विकास को लेकर एक अलग ही खेल जारी है। स्कूल से लेकर कॉलेज एवं विश्वविद्यालय स्तर पर खेल को किस तरह से बच्चों से जोड़ा जाए, इसके प्रति कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई देती। एक बच्चे में खेल के प्रति रुझान पैदा करने वाली परिस्थितियां पैदा करने की बात तो दूर जो बच्चे खेल को अपनी पहली पसंद बनाना चाहते हैं उन्हें भी पहली लड़ाई घर में ही लड़नी पड़ती है। परीक्षा से ठीक पहले यदि किसी चीज़ पर पाबंदी लगती है तो वह खेल ही है। बच्चों को खेल से महरूम करने का तात्पर्य 'स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क के वास', की मान्यता को नकारना है। प्रयोगों एवं अनुसंधानों से साबित हो चुका है कि खेलने से न केवल बच्चों का शारीरिक, मानसिक एवं संवेगात्मक विकास होता है, बल्कि खेल के जरिये बच्चे समूह में काम करने, साझा योगदान एवं संवाद करने की कला भी सीखते हैं। बच्चों में आपसी निर्णय लेने से लेकर समूह में काम करने की समझ भी विकसित होती है। लेकिन दुर्भाग्य से आज बच्चों के खेल, खेल का समय तकनीक आधारित खेलों तक सिमट कर रह गए हैं। बच्चों में सहनशीलता का क्षरण इस क़दर हो चुका है कि ज़रा-सी बात पर हिंसक हो जाने,

अध्यापक/अध्यापिका की डांट पर आत्महत्या तक के प्रयास की ख़बरें अब आम हो चुकी हैं।

बच्चों को खेल से किस तरह काटा जाय इसकी भी एक अपनी नीति होती है। खेल से बच्चों को विलगाने की शुरुआत पहले पहल घर से होती है जो आगे चल कर समाज में दिखाई देती है। इस पूरी प्रक्रिया में अंततः बच्चों को हार कर खेल की इच्छा का न केवल गला घोटना पड़ता है बल्कि घर या वीडियो गेम खेलने का सुख उठाना पड़ता है।

यह अलग बात है कि आज शिक्षा जगत में 'बाल केंद्रित शिक्षा-शिक्षण' की बात खूब हो रही है लेकिन हकीकत देखकर पता चलेगा कि बहुत कम अभिभावक ऐसे हैं जो अपने बच्चे को खेल को बतौर करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित करते हों। ऐसे में बिन खेल योजना, उत्साह, आधे-अधूरे मन से खेल को स्कूल में टुंस देने से क्या खेल के सम्यक विकास और संवर्धन की उम्मीद की जा सकती है?

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या, 2005 में खेल के महत्व को स्वीकार करते हुए दस्तावेज़ के तीसरे अध्याय में 'स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा' के तहत ध्यान दिलाया गया है। यह मानी हुई बात है कि स्वास्थ्य बहुआयामी सिद्धांत है और वह जैविक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक तत्वों से निर्धारित होता है। स्वास्थ्य बच्चे के समस्त विकास का सूचक होता है और वह महत्वपूर्ण ढंग से नामांकन, स्कूल में उपस्थिति और पढ़ाई पूरी करने को प्रभावित करता है। इस संबंध में पाठ्यचर्या में स्वास्थ्य को लेकर एक संपूर्ण दृष्टिकोण अपनाया जा सकता है जिसमें योग और शारीरिक शिक्षा बच्चे के शारीरिक, सामाजिक, भावनात्मक और मानसिक विकास में अपना योगदान कर सकता है। गौरतलब है

कि इस उपशीर्षक के तहत जो भी सुझाव दिए गए हैं वे खेल तथा स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा को ध्यान में रखते हुए हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो कुल मिला कर जो छवि बनती है वह यही कि खेल के नाम पर स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा की बात की जा रही है। केंद्र एवं राज्य सरकारें भी खेल के बजाय शारीरिक शिक्षा को बढ़ावा देने के प्रति ज़्यादा गंभीर दिखती हैं।

सवाल यह उठता है कि क्या खेल और स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा में कोई अंतर सरकार की नज़र में नहीं है? यदि ऐसा है तो एक बात साफ़ है कि स्वास्थ्य के नाम पर चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रम और खेल में एक बड़े स्तर पर घालमेल का खेल जारी है। क्योंकि शारीरिक शिक्षा बतौर विषय के रूप में 10वीं एवं 11वीं में बच्चे को उपलब्ध कराने की बात सरकार मान चुकी है जिसके तहत शारीरिक शिक्षा पढ़ाने वाले अध्यापकों की नियुक्ति की बात भी चल रही है। स्कूलों में, खासकर निजी स्कूलों को छोड़ दे तो पाएंगे कि सरकारी स्कूलों में खेल के नाम पर छुट्टी की अवधारणा ज़्यादा मिलती है। खेल का पीरियड यानी छुट्टी या मैदान में बैठकर या फिर फुटबॉल या ज़्यादा हुआ तो बॉस्केट बॉल खेल कर बिताया जाने वाला समय। प्रायः स्कूलों की व्यवस्था ऐसी होती है कि नेट है तो गेंद नहीं और यदि गेंद उपलब्ध हुआ तो नेट नदारद होता है। खेल के लिए स्कूलों में नामांकन के समय शुल्क चुकाने पड़ते हैं लेकिन वास्तव में बच्चों को खेल के सामान नहीं मिलते। स्कूल स्तर पर खेल की स्थिति को देखे जाने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि आज के मशहूर खिलाड़ी यदि अपने समय में स्कूल स्तर पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते तो आज उनकी स्थिति क्या यही होती जो आज है? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या, 2005 इस बात पर जोर देता नज़र आता है कि कम से कम ब्लॉक स्तर पर क्रीड़ा स्कूल के स्थल का उपयोग करते हुए प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के लिए स्कूल से पहले और बाद में विशेषतौर पर खेल और प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध करवाने की योजना को सफल बनाया जाए। यह भी संभव है कि वहां खेल संबंधी सुविधाओं का विकास हो ताकि खाली समय में बच्चे वहां बास्केट बॉल, वॉलीबॉल, थ्रो बॉल और स्थानीय खेलों का आनंद उठा सकें। □

(लेखक एक आर्थिक समाचारपत्र से संबद्ध हैं।
ई-मेल : k.prapanna@gmail.com)

शिक्षा में खेलों का समागम

● रचना शर्मा

हमने विकास की परिभाषा को किताबी पढ़ाई, अच्छी नौकरी और भौतिक वस्तुओं के भंडारण तक सीमित कर दिया और हम यह भूल गए कि खेलों का सरोकार केवल शरीर से ही नहीं बल्कि मन और मस्तिष्क से भी है। विडंबना यह है कि हरियाणा का भिवानी जैसा क्षेत्र जो देश को बॉक्सिंग के महारथी देता है, वहां से एक भी लड़की खेलों का हिस्सा नहीं बनती

हमारे देश की 70 प्रतिशत जनसंख्या 35 वर्ष से कम आयु की है और 24 करोड़ से अधिक आबादी 10 से 19 वर्ष के आयुवर्ग में आती है। यह 'युवा' देश हर क्षेत्र में अपनी इस 'जन' संपत्ति का जिक्र करता है किंतु बात जब खेलों में पदक जीतने की हो, तो हम दुनिया के दस देशों में अपना नाम देखना तो दूर, बीस देशों में भी कहीं खड़े नजर नहीं आते। देश में ज्यादातर लोग खेलों के नाम पर केवल क्रिकेट को ही जानते हैं। ऐसे में अन्य खेलों को लेकर उदासीनता है। खेल प्रतियोगिताओं में इस उदासीनता का नतीजा सिर्फ के रूप में दिखना लाजिमी ही है। हालांकि पिछले दो-तीन वर्षों से लगातार विश्वस्तरीय खेल आयोजनों की मेजबानी से थोड़ी सुगबुगाहट दिखाई देने लगी है। राष्ट्रमंडल खेल इसका ताजा उदाहरण हैं। राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी से एक फायदा जो प्रत्यक्ष नजर आ रहा है वह यह है कि हम क्रिकेट के इतर अन्य खेलों को लेकर कम से कम चर्चा तो जरूर करने लगे हैं। लेकिन, विश्व पटल पर अपनी पहचान बनाने के लिए केवल चर्चा से कुछ खास हासिल नहीं होगा बल्कि इसके लिए कुछ

ठोस उपाय करने होंगे। इसकी शुरुआत शिक्षा व खेलों में समन्वय स्थापित करके ही होगी। जिस तरह शिक्षा बाल्यावस्था से बड़े होने तक व्यक्ति को निरंतर परिपक्वता की ओर ले जाती है, उसी प्रकार, छोटी उम्र से और निरंतर मिलने वाला प्रशिक्षण ही किसी खिलाड़ी को बड़े मुकाम तक पहुंचाने की सीढ़ी बन सकता है।

पिछली पंचवर्षीय योजनाओं का विश्लेषण करते हुए, संसदीय स्थायी समिति ने खेलों को लेकर जो कुछ समस्याएं व मुद्दे उठाए थे उनमें शिक्षा के साथ खेलों का समाहित न हो पाना एक अहम मुद्दा था। हालांकि समिति ने सबसे पहले देश में खेलों को लेकर संस्कृति व जागरूकता के अभाव का प्रश्न उठाया था, किंतु यह प्रश्न भी कहीं न कहीं शिक्षा में खेलों को लेकर बेरुखी का नतीजा ही है। यही वजह है कि ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के उद्देश्यों में ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में ज़मीनी स्तर पर खेल संबंधी बुनियादी सुविधाओं को प्रोत्साहित करने व शैक्षणिक संस्थानों की भागीदारी को बढ़ाए जाने पर खासा जोर दिया गया है। लेकिन इस योजना का आधा समय बीत जाने के बाद भी कोई खास असर

दिखाई नहीं दे रहा। यदि भारतीय खेल प्राधिकरण के आंकड़ों पर गौर फरमाएं, तो वर्ष 2009-2010 में विशेष क्षेत्र खेल कार्यक्रम में कुल 2019 खिलाड़ी, भारतीय खेल प्राधिकरण प्रशिक्षण केंद्र कार्यक्रम में कुल 7,658 खिलाड़ी और सेंटर ऑफ एक्सिलेंस स्कीम के तहत कुल 325 खिलाड़ियों ने प्रशिक्षण लिया। यानी एक अरब से अधिक जनसंख्या वाले देश में 10 हजार के करीब खिलाड़ी ही उच्चस्तरीय प्रशिक्षण के योग्य पाए जाते हैं। इसमें भी विडंबना यह है कि हरियाणा का भिवानी जैसा क्षेत्र जो देश को बॉक्सिंग के महारथी देता है, वहां से एक भी लड़की खेलों का हिस्सा नहीं बनती। वहीं, खेल विशेष की बात करें, तो कुश्ती, भारोत्तोलन, दौड़, जिमनेजियम जैसे खेलों में प्रशिक्षित खिलाड़ियों की संख्या तो दहाई के आंकड़ों को किसी तरह पार कर पाती है वहीं साइकिल चालन व तैराकी जैसे खेलों में भी हमारे पास खिलाड़ियों की कमी है।

ऐसा नहीं है कि हमारे देश में खेलों की संस्कृति न रही हो। पौराणिक कथाओं का जिक्र करें तो कृष्ण की लीलाओं में नृत्य से लेकर

वॉलीबॉल तक के उद्गम के संकेत मिलते हैं और ऐसा भी नहीं है कि यहां प्रतियोगिताओं को लेकर भी कुछ अनमना भाव दिखा हो, कुश्ती से लेकर तमाम खेल जो प्राचीन समय से चले आ रहे थे, उनमें हमने प्रतियोगिताओं का खूब बखान सुना है। फिर ऐसा क्या हुआ कि हम खेलों के क्षेत्र में विश्व में अपनी पताका लहराने के बजाय पिछड़ते ही नज़र आए? ओलंपिक खेलों में हम बौने ही बने रहे, हालांकि बीजिंग ओलंपिक में एक स्वर्ण व दो कांस्य पदकों ने किसी तरह देश की लाज बचा ली, लेकिन कुल मिलाकर इतने बड़े देश की इतनी जनसंख्या, दुनियाभर में अपनी खास पहचान नहीं बना पा रही है। दरअसल, हमने धीरे-धीरे संपूर्ण विकास की परिभाषा को क्रिस्तावी पढ़ाई, अच्छी नौकरी और भौतिक वस्तुओं के भंडारण तक सीमित कर दिया और हम यह भूल गए कि खेलों का सरोकार केवल शरीर से ही नहीं बल्कि मन और मस्तिष्क से भी है। सर्वांगीण विकास के लिए खेलों का अपना ही महत्व है और अन्य कई देश इसे बखूबी समझते हैं। मसलन, फ्रांस व स्पेन जैसे कई देश शिक्षा के हर स्तर से लेकर रोजगार तक के क्षेत्र में खेलों को तवज्जो देते हैं। उनका मानना है कि जो व्यक्ति खेल में अच्छे हैं, उनमें टीम में काम करने, नेतृत्व व चुनौतियों से लड़ने की क्षमता अन्य लोगों के मुक़ाबले अधिक होती है। यही वजह है कि ऐसे देशों के खिलाड़ी अपने जीवन में तो संतुष्ट हैं ही, विश्व प्रतियोगिता के स्तर पर भी वे आगे नज़र आते हैं। सनद रहे कि बीजिंग ओलंपिक खेलों में फ्रांस 40 पदकों के साथ, दुनिया के दस श्रेष्ठ देशों में शुमार था, वहीं स्पेन फुटबॉल में विश्व चैंपियन का खिताब हासिल कर चुका है।

देश में खेलों को लेकर बेरुखी का एक बड़ा कारण लोगों में इस क्षेत्र की जानकारी और जागरूकता का अभाव है। दुर्भाग्य यह है कि यह अभाव केवल अशिक्षितों व ग्रामीण इलाकों में ही नहीं बल्कि शहरी व शिक्षित वर्ग में भी व्याप्त है। अब भी हमारी शिक्षा व्यवस्था में न तो खेल प्रशिक्षण पर कुछ खास ध्यान दिया जा रहा है और न ही प्रशिक्षकों व खेल संबंधी ढांचागत ज़रूरतों को पूरा करने पर। यदि दसवीं पंचवर्षीय योजना के आंकड़ों पर नज़र डालें तो वर्षभर में, राज्य स्तर पर प्रतिव्यक्ति नियोजित खर्च औसतन

केवल 8.94 रुपये और केंद्र स्तर पर केवल 12.92 रुपये ही प्रत्येक युवा पर खर्च हो पाया। जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह औसतन 21.86 रुपये रहा। यह भी पाया गया कि नियोजित खर्च के ढांचे में राज्यों की हिस्सेदारी आठवीं पंचवर्षीय योजना से भी कम हो गई थी। आठवीं पंचवर्षीय योजना के तहत 62 फीसदी खर्च की तुलना में दसवीं योजना के अंतर्गत, राज्य केवल 59 फीसदी खर्च कर पाए। इसमें गुजरात, राजस्थान व हिमाचल प्रदेश सरीखे राज्य निचले पायदानों पर नज़र आए।

यदि इन आंकड़ों को एकबारगी नज़रअंदाज कर भी दिया जाए, तो भी बुनियादी तौर पर हमारे पास खेलों को लेकर एक सुव्यवस्थित नज़रिये का अभाव खटकता है। उदाहरण के लिए, हम एक शैक्षणिक वर्ष के दौरान, त्रैमासिक व अर्द्धवार्षिक परीक्षा लेते हैं लेकिन स्कूल-कालेजों में दो साल में एक बार या ज्यादा से ज्यादा सालाना जलसे के रूप में खेल दिवस के दौरान प्रतियोगिताएं करा लेते हैं। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि विभिन्न खेलों की प्रतियोगिताएं जिला व राज्य स्तरों पर वर्षभर चलती हैं, लेकिन इन प्रतियोगिताओं का हिस्सा वही छात्र बन पाते हैं, जो व्यक्तिगत तौर पर इन खेलों में हिस्सा लेने में सक्षम होते हैं, अन्य छात्र इन अवसरों के अभाव में ही जीते हैं। उधर, विश्वस्तरीय प्रतियोगिताओं में भी यही सच्चाई व्यापक तस्वीर के रूप में दिखाई देती है।

बैडमिंटन में नाम कमाने वाली सायना नेहवाल हों या बीजिंग ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा, बॉक्सिंग में हुनर दिखाने वाले विजेंद्र सिंह हों या फिर मैरिक्वॉम या फिर शूटिंग में तेजस्विनी संधी में जो एक बात सामान्य रही वह यह कि ये सभी खिलाड़ी व्यक्तिगत तौर पर और अपने बूते प्रतियोगिता का हिस्सा बने। खिलाड़ियों को राज्य व समाज से जो मदद व प्रोत्साहन मिलना चाहिए, उसकी अब भी कमी नज़र आती है। दूसरे देशों में स्थिति इससे अलग है क्योंकि यहां शिक्षा के साथ खेलों को समन्वित करके राज्य अपने दायित्व का निर्वाह बखूबी कर पाते हैं। चीन इसकी मिसाल है, जहां राज्य स्वयं खेलों पर बहुत ध्यान देता है। यहां बचपन से ही खिलाड़ियों को उच्चस्तरीय प्रशिक्षण दिया जाता है। पुरुषों व महिलाओं को समान रूप से प्रशिक्षण का नतीजा दोनों ही वर्गों के बेहतर

प्रदर्शन में देखा जा सकता है। दशकों से यहां खेलों को शिक्षा प्रणाली का अभिन्न अंग माना जाता रहा है। खेल सुविधाएं, प्रशिक्षकों, खेलों के लिए विशेष आवास, भोजन और यात्रा संबंधी विशेषाधिकारों के योगदान से ही चीन के पास आज ओलंपिक में जीत दर्ज करा चुके सर्वाधिक स्वर्ण पदक विजेता हैं।

हाल में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) ने भी इस बात की सिफ़ारिश की थी कि शारीरिक शिक्षा को दसवीं कक्षा तक अनिवार्य विषय के रूप में और बारहवीं कक्षा तक के स्तर पर शिक्षा के विशेष विषय के रूप में शामिल किया जाए। अब इस मुहिम पर कुछ काम होता दिखाई दे रहा है और स्कूल भी इस दिशा में क्रम बढाते नज़र आ रहे हैं। यहां अभिभावकों की भूमिका भी बढ़ जाती है। दरअसल, शिक्षा की तरह खेलकूद का विकास भी तब तक संभव नहीं जब तक कि घर व स्कूल में तालमेल न हो। अभिभावकों को इस बात को समझना होगा कि खेलों का सीधा संबंध बच्चों के व्यक्तित्व से है। इस दिशा में अमरीका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से हम कुछ सीख ले सकते हैं। अमरीका में अभिभावकों, शिक्षकों, प्रशिक्षकों व 'प्रशिक्षकों के रूप में' अभिभावकों की लगातार प्रेरणा का असर पिछले तीन दशकों में, खेलों के द्वारा युवाओं के सर्वांगीण विकास के रूप में नज़र आता है। यही वजह है कि विश्व में लगभग हर क्षेत्र में सबसे आगे दिखाई देने वाला यह देश बीजिंग ओलंपिक के दौरान सर्वाधिक पदक लेने में भी अब्वल रहा और माइकल फेलप जैसे खिलाड़ियों ने विश्व रिकॉर्ड में ऐसे नंबर दर्ज करा लिए, जो आने वाले खिलाड़ियों के लिए किसी एवरेस्ट पर विजय पाने से कम नहीं। इसी तरह, ऑस्ट्रेलिया में स्कूली शिक्षा के दौरान, अभिभावक बच्चों को कई खेलों में भाग लेने के लिए प्रेरित करते हैं और न केवल स्कूलों में उन्हें प्रशिक्षित किया जाता है बल्कि छुट्टियों के समय का सदुपयोग करने के लिए बाकायदा वहां वीकेंड स्पोर्टिंग क्लबों की व्यवस्था की गई है।

अंततः यही कहा जा सकता है कि देश को विश्व पटल पर अपनी छाप छोड़ने के लिए हमारे पास प्रतिभा की कमी नहीं, लेकिन अवसरों का अभाव है, जिसे निम्नांकित कोशिशों के ज़रिये दूर किया जा सकता है :

● स्कूली शिक्षा में चार वर्ष से लेकर 16 वर्ष तक के लिए प्रतिदिन खेलों का अभ्यास व साप्ताहिक प्रदर्शन अनिवार्य किया जाए और इसे महज एक अतिरिक्त शैक्षणिक गतिविधि के रूप में देखने की प्रवृत्ति को खत्म किया जाए।

● शैक्षिक छात्रवृत्तियों की तर्ज पर खेल संबंधी छात्रवृत्ति, खासतौर पर आदिवासी व पिछड़े इलाकों के बच्चों के लिए शुरू की जाएं ताकि ऐसे बच्चों को आगे आने के अवसर प्राप्त हो सकें।

● कार्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के तहत, निजी कंपनियां कुछ बच्चों को गोद लेकर उन्हें प्रतियोगिताओं के लिए दक्ष कर सकती हैं और ऐसे खिलाड़ियों को विश्व रिकॉर्ड में अपनी जगह बनाने का मौका प्रदान कर सकती हैं (यह मौजूदा प्रायोजकों की व्यवस्था से अलग हो जिसमें खेलों से संबंधित उपभोक्ता वस्तुओं की निर्माता कंपनियां कुछ खेलों के लिए अपनी वस्तुएं अथवा धनराशि प्रदान करती हैं)।

हमारे ग्रामीण व दूर-दराज के इलाकों में ऐसी कितनी ही प्रतिभाएं छिपी हुई हैं जो तीरंदाजी, दौड़ और जिम्नेजियम जैसे कितने ही खेलों के क्षेत्र में विजय पताका लहरा सकते हैं। हाल में केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान इस दिशा में मील का पत्थर साबित हो सकता है। ऐसे कार्यक्रमों को प्रोत्साहित किया जाना आवश्यक है।

देश में नट व कई अन्य जनजातियां करतब दिखाकर अपना जीविकोपार्जन करती हैं। दुर्भाग्यवश ऐसी बेघर प्रतिभाएं अब शहरों व महानगरों में भिक्षावृत्ति के लिए मजबूर हैं। गैर-सरकारी संगठनों, व्यापारिक घरानों व संगठनों तथा सरकारी कार्यक्रमों की मदद से इन्हें प्रशिक्षित करके न केवल हम इनके जीवन को नयी दिशा प्रदान कर सकते हैं बल्कि देश को बेहतर जिमनास्ट भी दे सकते हैं।

जिस देश में अधिकतर गांव-कस्बे, यहां तक कि नगर-महानगर भी नदियों के किनारे बसे हैं, वहां तैराकी के धुरंधरों को दूढ़ना अधिक मुश्किल नहीं है। यदि एक समर्पित दल को इस कार्य के लिए लगा दिया जाए, तो तैराकी जैसे खेलों में भी हमारे पास पदक अर्जित करने वाले खिलाड़ी मौजूद होंगे।

यहां मीडिया की भूमिका भी अहम होगी। मसलन, केंद्रीय तथा राज्य सरकारें सामाजिक विज्ञापनों के द्वारा लोगों को खेलों व उनसे जुड़े सरकारी कार्यक्रमों व नीतियों से अवगत करा सकती हैं, जिससे लोगों को खेलों का हिस्सा बनने की प्रेरणा व अवसरों का पता चलने के साथ-साथ यह जानकारी भी मिल सके कि वे खेल में बेहतर प्रदर्शन दिखा कर भी भविष्य में रोजगार के बढ़िया अवसर पा सकते हैं। वहीं, समाचार व मनोरंजन से जुड़े निजी चैनल दूर-दराज के क्षेत्रों में छिपी प्रतिभाओं को उजागर कर सकते हैं। अन्य क्षेत्रों की तरह, यदि खेल-कूद के क्षेत्र को लेकर भी कोई 'रियलिटी शो' दिखाया जाए, तो वह न केवल लोकप्रियता बटोर सकता है, बल्कि देश को ऐसे खिलाड़ी भी मुहैया करा सकता है जो उसे विश्वस्तरीय जीत दिला सकें।

(लेखिका विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, नयी दिल्ली में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं।)

ई-मेल : rachna_130@yahoo.co.in)

SAROJ KUMAR'S IAS ERA

आई. ए. एस. 2009-10 के सफल अभ्यर्थी



NITISH KUMAR
RANK 78



SANJAY Kr. AGGARWAL
1 RANKINIAS2002-03
in हिंदी माध्यम



SONIKA (RAJ.)
RANK-215



Amil Bhaskar KOTA(RAJ.)
RANK-748



Virendra S. Yadav SHAHPURA(RAJ.)
RANK-697



Din Dayal Mangal AGRAJPUR
RANK-779



Budhi Prakash TONK(RAJ.)
RANK-707



Bishan Singh Lahori & Spiti (H.P.)
RANK-858



Nitin Tagade
RANK-802



Dr. Anil Choudhary
RANK-711

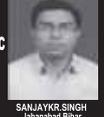


RAKESHKR VERMA HAATHRAS(U.P.)
RANK-495

एडमिशन जारी है

नौकरीपेशा अभ्यर्थियों के लिए विशेष कक्षाएँ प्रातः काल एवं सांयकाल को

ALSO BPSC



TOPPER 2010

भूगोल

सामान्य अध्ययन

इतिहास

निबंध और अनिवार्य अंग्रेजी

कोर्सेस उपलब्ध

टैस्ट सीरिज कार्यक्रम
1 महीना

विशेष कक्षाएँ मुख्य परीक्षा/निबंध के लिए
1 1/2 महीना

फाउण्डेशन कोर्स

6 महीने

(शून्य से प्रारम्भ)

हॉस्टल सुविधा लड़कों-लड़कियों के लिए अलग-अलग

Dr. Veena Sharma

MukherjeeNgr.Centre:- 14, M-1, Mezzanine Floor, Commercial Complex, Bhandari House, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-110009

Delhi University Centre:- /9, Roop Nagar, G. T. Karnal Rd., Near Shakti Ngr. Red Light, Above. P. N. B. Near Delhi University, North Campus Delhi- 110007

Email:-sarojkumarsiasera@gmail.com

Mob.:9910415305,9910360051

YH-9/10/2



राष्ट्रमंडल खेल

● राष्ट्रमंडल खेलों का क्या इतिहास है?

राष्ट्रमंडल खेल पहले ब्रिटिश एंपायर गेम्स (ब्रिटिश साम्राज्य खेल) के नाम से जाना जाता था और इसका पहला आयोजन 1930 में कनाडा के ओंटारियो प्रांत के हैमिल्टन शहर में हुआ था। 1954 में इसका नाम बदलकर ब्रिटिश एंपायर एंड कॉमनवेल्थ गेम्स कर दिया गया और फिर बाद में वर्ष 1970 में इसे ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम्स का नाम दिया गया। 1978 से यह कॉमनवेल्थ गेम्स (राष्ट्रमंडल खेल) के नाम से जाना जा रहा है। राष्ट्रमंडल खेल, ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा रहे देशों और क्षेत्रों का खेल है जो हर चौथे वर्ष आयोजित होता है। यह एक अनूठी स्पर्धा है जिसमें अनेक खेलों के विश्वस्तरीय मुक़ाबले देखने को मिलते हैं। राष्ट्रमंडल खेलों के तीन मूल्यवान सिद्धांत हैं— मानवता, समानता और नियति, जिन्हें इन खेलों ने 2001 में एक आंदोलन के रूप में अंगीकार किया था। ये जीवन मूल्य लाखों-करोड़ों लोगों को प्रेरित करते हैं और उन्हें पास लाते हैं और राष्ट्रमंडल के दायरे में खेलों के आयोजन के व्यापक जनादेश के प्रतीक माने जाते हैं। राष्ट्रमंडल खेल संघ (सीजीएफ) में 71 सदस्य राष्ट्र और क्षेत्र हैं, जिनमें भारत भी शामिल है।

● दिल्ली में 3 से 14 अक्टूबर, 2010 तक होने वाले 19वें राष्ट्रमंडल खेल की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं?

इस खेल उत्सव में 17+1 प्रकार के खेल होंगे। इनमें 17 खेल सामान्य एथलीटों के लिए होंगे, जबकि एक में विकलांग खिलाड़ी भाग लेंगे। इसमें लगभग 8,000 खिलाड़ी और उनके कोच आदि भाग लेंगे। मीडिया जगत के भी लगभग 2,000 लोग आएंगे। खेलों के लिए लगभग एक लाख लोगों के बाहर से आने की आशा है। इन खेलों का प्रसारण हाई डेफिनिशन टेलीविजन पद्धति से होगा। पूरे विश्व में करीब 2 अरब लोग 19वें राष्ट्रमंडल खेल का सीधा प्रसारण देखेंगे। संप्रेषण की नयी तकनीक जैसे पे टीवी, इंटरनेट और टेलीफोनी के प्रयोग से प्रसारण विश्व के कोने-कोने में फैल सकेगा। इन खेलों के दौरान अक्षय ऊर्जा के उपयोग, कार्बन उत्सर्जन में कमी और संपोषणीय विकास पर विशेष ध्यान दिया जाएगा; इसलिए ये

खेल हरित खेल कहे जा रहे हैं।

● दिल्ली राष्ट्रमंडल खेल में कौन कौन-सी खेल प्रतियोगिताएं होंगी?

सत्रह खेलों में प्रतियोगिताएं होंगी। ये हैं— तैराकी, तीरंदाजी, दौड़-कूद (एथलेटिक्स), बैडमिंटन, मुक्केबाजी, साइकिल चालन, जिम्नास्टिक्स, हॉकी, लॉन बोल्ल्स, नेटबॉल, रग्बी, सेवन्स, निशानेबाजी, टेनिस, टेबल टेनिस, भारोत्तोलन और कुश्ती आदि।

● क्वींस बेटन रिले का क्या महत्व है?

क्वींस बेटन रिले, राष्ट्रमंडल खेलों की एक अत्यंत महत्वपूर्ण परंपरा है। यह सन् 1958 में कार्डिफ खेलों (वेल्स) से शुरू हुई और तब से प्रत्येक राष्ट्रमंडल खेल के लिए पर्दा उठाने का काम करती आई है। खेल दर खेल इसके आकार और भव्यता में वृद्धि होती रही है और अब यह राष्ट्रमंडल देशों की एकता और विविधता को प्रतिबिंबित करती है। यह रिले ब्रिटेन के बकिंगहम पैलेस से प्रारंभ होती है जहां महारानी एलिजाबेथ द्वितीय एक समारोह में अपना संदेश प्रथम रिले धावक को देकर बेटन को रवाना करती हैं। रिले खेलों के उद्घाटन समारोह पर जाकर समाप्त होती है जहां महारानी का संदेश पढ़कर सुनाया जाता है। पहले रिले केवल इंग्लैंड और मेज़बान देश में ही हुआ करती थी, परंतु वर्ष 1998 के कुआलालंपुर खेलों से यह अन्य सदस्य देशों से भी होकर गुजरती है। वर्ष 2006 में मेलबर्न में हुए राष्ट्रमंडल खेल के लिए हुई क्वींस बेटन रिले, विश्व की सबसे लंबी और सर्व समावेशी रिले थी। इसने सभी 71 सदस्य देशों का भ्रमण किया और एक वर्ष तथा एक दिन में 1,80,000 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय की।

दिल्ली राष्ट्रमंडल खेल 2010 के लिए क्वींस बेटन रिले 29 अक्टूबर, 2009 को बकिंगहम पैलेस से शुरू हुई थी और 340 दिनों के बाद 3 अक्टूबर, 2010 को दिल्ली के 19वें राष्ट्रमंडल खेल के उद्घाटन समारोह में इसकी यात्रा समाप्त होगी। अपनी इस यात्रा के दौरान बेटन विश्व की एक तिहाई जनसंख्या के घरों से होकर गुजरेंगी और 1,90,000 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करेंगी। यह लंबी दौड़ तो 240 दिनों तक 70 अन्य

राष्ट्रमंडल देशों के बीच चलेगी जबकि शेष 100 दिन भारत के सभी 28 राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों की राजधानियों की यात्रा पर रहेगी।

क्वींस बेटन 2010 दिल्ली, हस्तशिल्प, अभियांत्रिकी और हाथ से बारीकी से जमाई हुई मिट्टी की पर्तों के सम्मिश्रण का अद्भुत नमूना है। बेटन को तैयार करने के लिए अल्युमिनियम का त्रिकोणीय खंड काटकर उसे सर्पिल कुंडली का आकार दिया गया है और फिर उस पर भारत के विभिन्न कोनों से एकत्रित विभिन्न प्रकार की रंग-बिरंगी मिट्टियों का लेप लगाया गया है। बेटन के शिखर भाग पर एक बहुमूल्य आभूषण पेटी लगाई गई है जिसमें खिलाड़ियों के लिए महारानी के संदेश को 18 कैरेट की स्वर्ण पट्टिका पर सूक्ष्म रूप से उकेरा गया है, जो प्राचीन भारत के स्वर्ण पत्रों का स्मरण कराता है। महारानी के संदेश को लिपिबद्ध करने के लिए आधुनिक लेसर तकनीक का प्रयोग किया गया है। बेटन में एलईडी प्रकाश और जीपीएस प्रणाली का प्रयोग किया गया है और यह ध्वनि एवं चित्र (संदेश) रिकॉर्ड कर सकता है।

● दिल्ली खेल के शुभंकर और प्रतीक चिह्न का क्या महत्व है?

दिल्ली राष्ट्रमंडल खेल का प्रतीक चिह्न स्वतंत्रता, एकता और शक्ति के प्रतीक चक्र से प्रेरित है। ऊपर उठती हुई सर्पिल रेखा, एक अरब लोगों के देश भारत की जीवंत संस्कृति और गौरवमयी प्रगति को दर्शाती है। टैगलाइन (नारा) 'आओ और खेलो' सभी लोगों को खेलों में भाग लेने और खेल भावना के साथ अपनी क्षमता और प्रतिभा के प्रदर्शन करने के लिए आमंत्रित करती है। यह चिह्न भारत के लोगों को भी श्रेष्ठतम अतिथि सत्कार के लिए संदेश देता है।

खेल का शुभंकर 'शेरा' आधुनिक भारत का प्रतिनिधित्व करता है। वह एक सार्थक दृष्टिकोण वाला परिश्रमी वैश्विक नागरिक है जो राष्ट्र की प्राचीन धरोहर के लिए सही तौर पर गर्व का अनुभव करता है। वह एक जुझारू प्रतियोगी है लेकिन ईमानदारी से भरा। 'शेरा एक बड़े दिलवाला सज्जनपुरुष' भी है जो मित्र बनाना पसंद करता है और लोगों को 'आकर खेलने' के लिए उत्साहित करता है। □



भारतीय खेलों के लिए एक यादगार क्षण

● हरपाल सिंह बेदी

यह भारत के खेलों के लिए एक अविस्मरणीय अवसर होगा। 3 से 14 अक्टूबर तक दिल्ली में भारत राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करेगा और खेल महाशक्तियों-ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, कनाडा और न्यूजीलैंड के मुक़ाबले उसके खिलाड़ियों के लिए 19वें राष्ट्रमंडल खेल महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करेंगे।

सरकार इन खेलों के आयोजन पर भरपूर पैसा खर्च कर रही है और इसमें कोई शक नहीं कि खिलाड़ियों के अच्छे प्रदर्शन और इन खेलों के निर्बाध आयोजन से दुनिया के देशों के बीच में भारत की अच्छी छवि बनेगी और उसकी उपलब्धियों का सकारात्मक प्रचार होगा।

वर्ष 1930 से शुरू होकर अब तक राष्ट्रमंडल

खेलों के 18 संस्करण हो चुके हैं और इनमें से 14 में भारत भाग ले चुका है। भारत ने इन खेलों में अब तक कुल 271 पदक जीते हैं, जिनमें से 102 स्वर्ण पदक रहे हैं। भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन वर्ष 2002 के मैनचेस्टर खेलों में हुआ जब उसके खिलाड़ियों ने 69 मेडल अपनी झोली में डाले। इनमें से 30 स्वर्ण, 22 रजत और 17 कांस्य पदक थे। इन खेलों में भारत ने अग्रणी माने जाने वाले अंग्रेज़ खिलाड़ियों को पछाड़ा और भारत की महिला हॉकी टीम ने प्रतिष्ठापूर्ण स्वर्ण पदक हासिल किया।

मेलबर्न में 2006 में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने 50 पदक जीते जिनमें 22 स्वर्ण, 17 रजत और 11 कांस्य पदक शामिल हैं।

वर्ष 2002 और 2006 के इन दोनों आयोजनों में कुल मिलाकर भारत चौथे नंबर पर रहा। हालांकि मेलबर्न में भारत ने अपेक्षाकृत कम पदक जीते। इसका एक कारण यह था कि वर्ष 2002 तक वेटलिपिंग में हर वर्ग में पदकों के तीन सेट होते थे, जबकि वर्ष 2006 में इनकी संख्या घटाकर एक सेट कर दी गई। वर्ष 2006 के खेलों में कुश्ती को शामिल ही नहीं किया गया। दिल्ली खेलों में कुश्ती की वापसी हो रही है जबकि इस बार की प्रतियोगिताओं में तीरंदाजी और टेनिस पहली बार शामिल किए गए हैं।

मेजबान देश के नाते भारत सभी प्रतियोगिताओं में शामिल होगा। ये हैं तैराकी, तीरंदाजी, एथलेटिक, बैडमिंटन, मुक्केबाजी, साइकिलिंग, जिम्नास्टिक,

हॉकी (महिला और पुरुष), लॉन बॉल्स, नेटबॉल, रग्बी सेवेंस, निशानेबाजी, स्क्वाॅश, टेबल टेनिस, टेनिस, वेटलिफ्टिंग और कुश्ती। खेल प्रेमियों को उम्मीद है कि हमारे खिलाड़ी इस बार बढ़िया प्रदर्शन करते हुए सिर्फ ज्यादा पदक ही नहीं जीतेगे बल्कि देश का नाम अंकतालिका में सबसे ऊपर ला सकेंगे।

अभी तक राष्ट्रमंडल खेलों में ऑस्ट्रेलिया का वर्चस्व रहा है। वह एक बार फिर अपना दबदबा कायम रखने की पूरी कोशिश करेगा। भारत को इंग्लैंड, कनाडा और न्यूजीलैंड से भी कड़ी चुनौती मिल सकती है। अब जबकि कुश्ती की वापसी हो रही है और तीरंदाजी और टेनिस खेलों में शामिल किए जा चुके हैं, भारत इस बार मेलबर्न के मुक्काबले अधिक स्वर्ण पदक जीतने की उम्मीद कर सकता है।

मेजबान देश को उम्मीद है कि उसके निशानेबाज बेहतर प्रदर्शन करते हुए ज्यादा स्वर्ण पदक जीतेगे। पिछली बार भारतीयों ने इन प्रतियोगिताओं में 27 मेडल जीते थे, जिनमें 16 स्वर्ण, 7 रजत और 3 कांस्य पदक शामिल हैं। गगन नारंग, अभिनव बिंद्रा, तेजस्विनी सावंत, रंजन सोढी, बीरेनदीप सोढी, आर.एस.राठौर के बेहतर प्रदर्शन करने और ज्यादा पदक जीतने की आशा है। भारत के खिलाड़ियों द्वारा मेलबर्न राष्ट्रमंडल खेलों में किया गया बेहतर प्रदर्शन प्रेरणा स्रोत है। लेकिन देखने की बात है कि इस बार की प्रतियोगिताओं में हमारे खिलाड़ी कितना बढ़िया प्रदर्शन कर पाते हैं। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि पिछली बार शूटर समरेश जंग ने अच्छा प्रदर्शन किया था। भारतीय महिलाओं ने भी हैरतअंगेज नतीजे दिखाए थे। उन्होंने मैनचेस्टर में हॉकी प्रतियोगिता जीती और वर्ष 2006 में दूसरे नंबर पर रहीं। लेकिन इस बार उन्हें स्वर्ण पदक जीतने या दूसरा नंबर हासिल करने के लिए जमकर कोशिश करनी होगी। ऑस्ट्रेलियाई भी बेहतर फ़ार्म में हैं और इंग्लैंड के खिलाड़ी बदला लेने के फ़िराक में हैं, जबकि कीवियों की पूरी कोशिश होगी कि वे पोटियम पर पहुंचें।

स्थानीय खेल प्रेमियों के लिए आकर्षण का केंद्र होगा भारत की पुरुष हॉकी टीम। भारतीय टीम इस बार पदक जीतने की पूरी कोशिश करेगी। वर्ष 1998 के कुआलालम्पुर खेलों में भारत ने चौथा नंबर हासिल किया था। वर्ष 2002 के खेलों में वह अंक तालिका में ऊपर नहीं दिखा, मेलबर्न में 5वें नंबर पर रहा जबकि

ऑस्ट्रेलिया इन तीनों खेलों में स्वर्ण पदक विजेता रहा।

भारत में हॉकी एक मुश्किल दौर से गुजर रही है और नयी दिल्ली में आयोजित 12 देशों के विश्व कप में भारत आठवें नंबर पर था। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की पुरुष टीम ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के साथ है, जबकि उसी पूल में तीन और टीमों हैं। भारत के लिए ये सचमुच एक कड़ा मुक्काबला होगा कि वह पहले नॉक आउट स्टेज में क्वालीफ़ाई करे और फिर पदक विजेता के रूप में सामने आए।

हॉकी के बाद दिल्ली खेलों में भारत के खेलप्रेमियों की नज़रें कुश्ती और टेनिस पर रहेंगी। बॉक्सिंग में भी इस बार भारतीयों को पदक मिलने की उम्मीद है। हाल ही में भारतीय मुक्केबाजों ने बेहतर प्रदर्शन किया है लेकिन अब देखना है कि राष्ट्रमंडल खेलों में कितना बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। 12वें राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय मुक्केबाज शामिल हुए थे लेकिन नतीजे काफ़ी कम जान पड़े। उन्होंने सिर्फ 13 पदक जीते जिनमें दो स्वर्ण दो रजत और नौ कांस्य थे। मुहम्मद अली क्रमर पहले मुक्केबाज हैं जिन्हें वर्ष 2002 के मैनचेस्टर राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने का सौभाग्य मिला। इसके बाद वर्ष 2006 में मेलबर्न में अखिल कुमार ने भी प्रथम स्थान प्राप्त किया।

लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि भारतीय मुक्केबाजों का सबसे ज्यादा गौरवमय दिन 20 अगस्त, 2008 को आया जब विजेंदर ने ओलंपिक खेलों के दौरान देश के लिए पहला पदक जीता। उन्होंने मिडिलवेट वर्ग में इक्वाडोर के कारलोस गोंगोरा पर 9-4 से ऐतिहासिक जीत दर्ज की। वर्ष 2009 में भी भारतीय मुक्केबाजों ने अनेक उपलब्धियां प्राप्त कीं। विश्व चैंपियनशिप में विजेंदर ने एक बार फिर कांस्य पदक जीतकर ख्याति पाई। ऑल इंडिया बॉक्सिंग फेडरेशन के सचिव पी.के. मुरलीधर राजा के अनुसार इन अच्छे प्रदर्शनों से संकेत मिलता है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं और अगर राष्ट्रमंडल खेलों में ड्रॉ ने हमारा साथ दिया तो हम निश्चय ही अनेक मेडल जीत सकेंगे। इन खेलों में 40 पदक उपलब्ध हैं जिनमें 10 स्वर्ण, 10 रजत और 20 कांस्य शामिल हैं। राजा ने उम्मीद जाहिर की कि इनमें से अधिकांश भारत की झोली में आ सकते हैं।

इसी तरह कुश्ती में कुल 64 पदक उपलब्ध

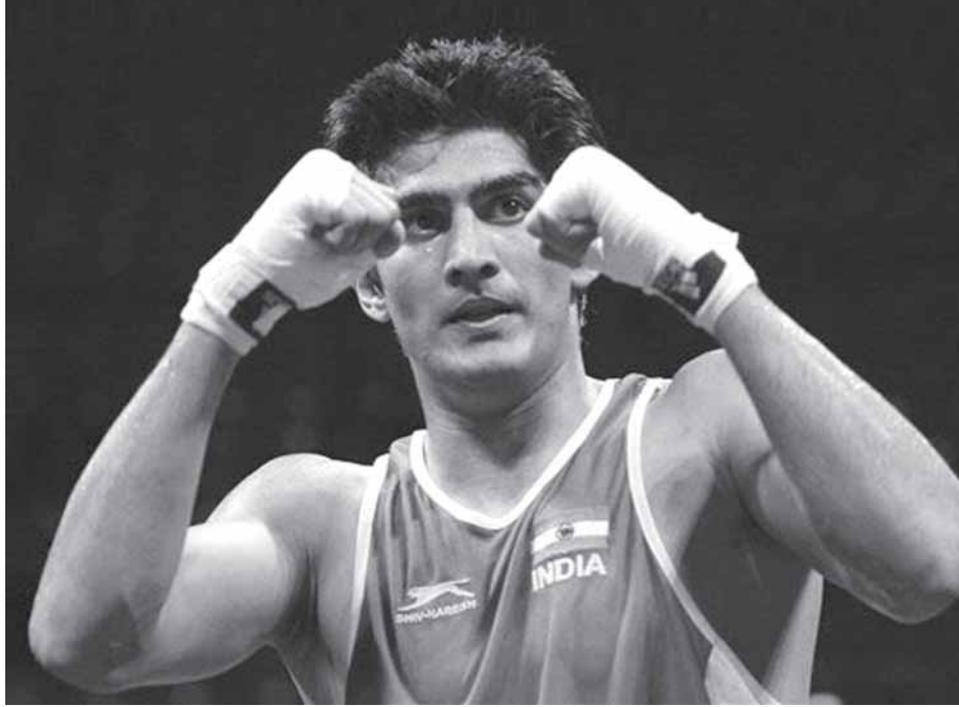
होंगे, जिनमें 21 स्वर्ण और 21 रजत शामिल हैं। आठ वर्षों के बाद अब इन खेलों में कुश्ती की वापसी हो रही है। वर्ष 2002 में मैनचेस्टर में भारतीय पहलवान मैट पर लड़ी जाने वाली कुश्ती पर हावी रहे थे। इससे पहले के राष्ट्रमंडल खेलों में कुश्ती सिर्फ फ्री स्टाइल प्रतियोगिताओं में शामिल की जाती थी। यह पहला मौका है जब कुश्ती में ग्रीको-रोमन और महिला पहलवान शामिल किए गए हैं। वर्ष 1982 के खेलों में स्वर्ण पदक जीत चुके राष्ट्रीय कोच जगमिंदर सिंह ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इन तीनों वर्गों में 7 वेट कैटेगरीज होंगी और मेजबान होने के नाते भारत इन सभी में भाग लेगा। जगमिंदर सिंह को उम्मीद है कि भारतीय प्रतिभागी 15 में से 14 स्वर्ण पदक जीत सकेंगे। भारतीय कुश्ती संघ के अन्य वरिष्ठ अधिकारी ने विश्वास प्रकट किया कि भारतीय खिलाड़ी 21 में से 10 से 18 पदक तक जीत सकेंगे। भारतीय कुश्ती संघ के अधिकारियों ने कहा कि भारत के सुशील कुमार द्वारा बीजिंग ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने से भारतीय पहलवानों का हौसला बहुत बढ़ा हुआ है। भारतीय पहलवानों को मुख्य रूप से कनाडा इंग्लैंड और पाकिस्तान के खिलाड़ियों से चुनौती मिलेगी।

तीरंदाजी को इन खेलों में दूसरी बार शामिल किया गया है। इससे पहले वर्ष 1982 में ब्रिस्बेन में भी तीरंदाजी प्रतियोगिताओं में शामिल थी। भारतीय खेल प्रेमियों की नज़रें उनके तीरंदाजों पर भी होंगी। इस वर्ग में 24 पदक उपलब्ध हैं, जिनमें चार स्वर्ण पुरुष वर्ग और चार महिला वर्ग के लिए होंगे। दोनों वर्गों में रजत और कांस्य पदकों की संख्या बराबर रखी गई है। भारत को उम्मीद है कि वह मुख्य प्रतिद्वंद्वी ऑस्ट्रेलिया और मलेशिया के मुक्काबले अधिकांश पदक जीत सकेगा। दिल्ली खेलों में तीरंदाजी के दो वर्ग रखे गए हैं। इन दोनों वर्गों में भारत के सीनियर तीरंदाज पहले अनेक पदक जीत चुके हैं। उन्होंने एशिया कप, जूनियर एशियाई चैंपियनशिप और कॉमनवेल्थ खेलों में पदक जीते हैं। व्यक्तिगत रूप से अच्छा प्रदर्शन करते हुए उन्होंने विश्व रिकॉर्ड की बराबरी की है। अन्य लोगों के अलावा तरुणदीप रॉय, राहुल बनर्जी, जयंत तालुकदार, सत्यदेव प्रसाद, मंगल सिंह चंपिया, डोला बनर्जी, चेक्रोगोलू स्वीरो, रीना कुमारी, सुमंगला, भाग्यवती चानू भारत की ओर से चुनौती पेश करेंगी।

टेनिस राष्ट्रमंडल खेलों में पहली बार शामिल किया जा रहा है। लेकिन पहली बार शामिल किए गए अन्य खेल तीरंदाजी की तरह मेजबान की यह पहली पसंद नहीं है। भारत चाहता था कि बिलियर्ड्स और स्नूकर को शामिल किया जाए।

राष्ट्रमंडल खेल संघ जहां तीरंदाजी को शामिल करने और कुश्ती की वापसी करने पर सहमत हुआ, वहीं उसने टेनिस के पक्ष में वोट डाले। इस वर्ग की प्रतियोगिताओं में पांच स्वर्ण पदक उपलब्ध हैं। यह हैं एकल (महिला और पुरुष), युगल (महिला और पुरुष) और मिला-जुला युगल। प्रतियोगिता में शामिल हर टीम के अधिकतम तीन एकल खिलाड़ी और अधिकतम दो टीमों युगल और युगल डबल्स में शामिल हो सकेंगी।

हालांकि राष्ट्रमंडल खेल संघ में 71 सदस्य हैं लेकिन यह कहना गलत नहीं होगा कि 10 देशों के टेनिस खिलाड़ियों का अच्छा रिकॉर्ड है। यह ध्यान देने की बात है कि राष्ट्रमंडल खेल में कुछ गिनी-चुनी प्रतियोगिताएं हैं जिनमें ब्रिटेन के खिलाड़ी व्यक्तिगत रूप से अपने देश का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं। इसीलिए दिल्ली में भी ब्रिटेन का प्रतिनिधित्व सात टीमों करेगी। इनके नाम हैं— इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, नार्थ आयरलैंड, आइल ऑफ मैन, जेर्सी और ग्वेर्नसी। राष्ट्रमंडल देशों में ऐसे खिलाड़ियों की संख्या पांच से ज्यादा नहीं है जो दुनिया के चोटी के 100 खिलाड़ियों में शामिल किए जाते हैं। इनमें सबसे ऊंचा स्थान का है स्कॉटलैंड के एंडी मरे। हालांकि ग्रैंड स्लैम आयोजनों में वे ब्रिटेन का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे दुनिया के चौथे नंबर के खिलाड़ी हैं जिसके बाद साइप्रस के मारकोस बगदातिस का नाम आता है, जो 30वें नंबर पर हैं। इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया के लेटन हेविट 33वें, डेनिस स्टोमिन 71वें और जर्मनी में रहने वाले जमैका के डस्टिन ब्राउन 99वें तथा भारत के सोमदेव देवबर्मन 111वें नंबर पर हैं। महिला वर्ग में ऑस्ट्रेलिया की समंथा स्टोसुर सबसे ऊंची रैंकिंग वाली हैं जिन्होंने फ्रेंच ओपन में वीनस विलियम्स को पराजित किया था। उनकी सातवीं रैंकिंग है। ब्रिटेन की एलीना बाल्टाचा 63वें, भारत की सानिया मिर्जा 91वें नंबर पर हैं जबकि ऑस्ट्रेलिया की अन्य खिलाड़ी अनस्तासिया रोडियोनोवा और एलीशिया मोलिक क्रमशः 92वें और 94वें स्थान पर हैं।



पुरुषों के युगल जोड़ी खिलाड़ियों में कनाडा के डेनियल नेस्टर एटीपी रैंकिंग में तीसरे नंबर पर हैं। लिण्डर पेस और महेश भूपति क्रमशः 6वें और 7वें नंबर पर हैं। भूपति के बहामास के जोड़ीदार मार्क नोल्स का आठवां नंबर है। इसके बाद पाकिस्तान के ऐसाम-उल-हक कुरैशी 46वें, रोहन बोपन्ना 54वें, ब्रिटेन के रॉस हचिंस 60वें, जोनाथन मैरे 74वें और ब्रिटेन के ही जेमी मरे 96वें स्थान पर हैं।

प्रतियोगिताओं में अगर टॉप रैंकिंग वाले खिलाड़ी न आए तो भारत कम-से-कम दो स्वर्ण जीतने की उम्मीद कर सकता है, जो पुरुषों के डबल्स और मिक्स्ट डबल्स में हो सकते हैं। अगर किस्मत कुछ साथ देती है तो भारत रजत पदकों की भी उम्मीद कर सकता है।

भारत के बैडमिंटन अभियान की अगुवाई सायना नेहवाल करेगी। दुनिया की दो नंबर की इस खिलाड़ी ने देश की उम्मीदें बढ़ा दी हैं। चेतन आनंद और पी. कश्यप पुरुष वर्ग में पदकों के दावेदार माने जा रहे हैं।

जहां तक वेटलिफ्टिंग का सवाल है, भारत की भागीदारी अभी स्पष्ट नहीं है। फेडरेशन ने अंतरराष्ट्रीय संस्था पर जुर्माना लगाया है और उसे क्लीन चिट देना अभी बाकी है। पांच से ज्यादा वेटलिफ्टर एक सीजन में पॉजिटिव साबित हुए हैं। संस्था को उम्मीद है कि भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन और सरकार उसे संकट से उबार लेगी।

एथलेटिक्स में मेजबान देश की ओर से विकास गौड़ा और हरवंत कौर भारत की चुनौती

पेश करेगी। भारत के युवा खिलाड़ी काफ़ी प्रतिभाशाली हैं और इसकी एक झलक पटियाला में आयोजित राष्ट्रीय स्पर्धाओं में मिल चुकी है। ध्यान देने की बात है कि इन खेलों में भारत ने सिर्फ़ एक बार स्वर्ण पदक तब जीता जब फ्लाइंग सिख कहे जाने वाले मिल्खा सिंह ने वर्ष 1958 में भारत का झंडा ऊंचा किया था। मेलबर्न में टेबल टेनिस में शरत कमल ने बड़ा धमाका किया था, जब वे चैंपियन बनकर उभरे थे। अधिकारियों को उम्मीद है कि इस खेल में भी भारत को अधिक पदक मिल सकेंगे।

स्क्वैश में भारत के अच्छे आसार हैं। एस. घोषाल अच्छे फ़ार्म में हैं जबकि युवा खिलाड़ी दीपिका महिला वर्ग में बेहतर प्रदर्शन करती रही हैं। लेकिन तैराकी की प्रतियोगिताएं काफ़ी मुश्किल हो सकती हैं और भारतीय तैराकों को कठिन मुक़ाबला करना पड़ सकता है। इसी तरह अगर साइकिलिंग, जिम्नास्टिक्स, लॉन बोल्ल्स, नेटबॉल, रग्बी सेवस आदि में भी भारत को कोई मेडल मिल जाता है तो यह उसके लिए बोनस माना जाएगा। इस बार की प्रतियोगिताएं कठिन हैं और भारतीय खिलाड़ियों को बहाना करने का कोई मौका नहीं है। सरकार ने प्रशिक्षण और कोचिंग पर जमकर पैसा खर्च किया है। खिलाड़ियों में जोश और प्रतिभा है और उम्मीद की जा सकती है कि वे भारत का नाम ऊंचा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। □

(लेखक समाचार एजेंसी यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया में खेल संपादक हैं।

ई-मेल : palbedi@hotmail.com)

भिवानी बना मिनी क्यूबा

हरियाणा का एक जिला मुक्केबाजी में रच रहा रोज नये इतिहास

● धर्मेन्द्र सिंह

खेलों में भारत को सिरमौर बनाने की बातें तो सालों से की जा रही हैं लेकिन हरियाणा के भिवानी जिले में मुक्केबाजी को लेकर रोज एक नयी इबारत लिखी जा रही है। न तो यहां करोड़ों का बजट है और न ही विश्वस्तरीय सुविधाएं फिर भी भिवानी के मुक्केबाज मेडल पर मेडल झटक रहे हैं। क्यूबा के मुक्केबाजों की दहशत को अपने सीने से निकाल हरियाणा की मरुभूमि के ये बांकुरे मुक्केबाजी में भारत को दुनिया का सिरमौर बनाने की जद्दोजहद में जुटे हैं। ओलंपिक कांस्य पदक विजेता विजेंद्र, दिनेश, परमजीत समौता और अखिल जैसे न जाने कितने ही नाम भिवानी की मिट्टी के नाम को रोशन करने में जुटे हैं। बॉक्सिंग में भिवानी के जुनून का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि भिवानी की करीब आधा दर्जन बॉक्सिंग अकादमियों सहित भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) में करीब 2,000 आगे बढ़ने के लिए दमखम लगा रहे हैं।

भिवानी को मिनी क्यूबा का दर्जा दिलाने में सन् 1986 में स्थापित भारतीय खेल प्राधिकरण के छात्रावास का अहम योगदान है। सुविधाओं के मामले में यह छात्रावास देश के दूसरे छात्रावासों से आगे नहीं है लेकिन यहां की मिट्टी में आगे बढ़ने का जुनून है। छात्रावास का माहौल इतना प्रतिस्पर्धी है कि खिलाड़ियों को रोज रात मुक्कों के ही सपने आते हैं। साई के मुक्केबाजों ने देश को अब तक दर्जनों अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाज दिए हैं और उन्होंने देश के लिए 115 अंतरराष्ट्रीय पदक जीते हैं। साई के बॉक्सिंग कोच व उत्कृष्ट खेल प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित जगदीश सिंह का नाम विशेष

उल्लेखनीय है क्योंकि इनके शिष्य विजेंद्र, जितेंद्र व दिनेश आदि के नाम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुंच चुके हैं। वर्ष 1990 में साई छात्रावास के मुक्केबाजी राजकुमार सांगवान, 1992 में संजय कुमार, मनबीर सिंह व संदीप गोलन, 1994 में रामेश्वर, 1995 में भूषण सैनी, राजीव जितेंद्र, भीमसिंह, 1998 में बृजेश शास्त्री, दिलबाग व देवेन्द्र ने भी अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार व मेडल जीते। अब तक भिवानी में कुल सात मुक्केबाजों को अर्जुन पुरस्कार मिला है। इनमें 6 खिलाड़ी कैप्टन हवासिंह, राजकुमार सांगवान, जितेंद्र सीसर, अखिल कुमार, विजेंद्र व दिनेश मुक्केबाज हैं।

भिवानी को मिनी क्यूबा के रूप में आगे बढ़ाने में मुक्केबाजी के मुख्यतः दो प्रशिक्षकों का योगदान अहम रहा है। कैप्टन हवासिंह व जगदीश सिंह भिवानी मुक्केबाजी के मील के पत्थर हैं। जगदीश सिंह द्वारा प्रशिक्षित मुक्केबाजों पर नजर डाली जाए तो विश्व कप मुक्केबाजी में प्रवीण, रेणु व मीना कांस्य पदक, एशियाई मुक्केबाजी में विजेंद्र सिंह ने कांस्य पदक जीते। राष्ट्रमंडल खेलों में अखिल ने स्वर्ण, बिजेंद्र ने रजत पदक हासिल किए। इसी तरह जूनियर एशियाई मुक्केबाजी प्रतियोगिता में बलजीत ने रजत, दिनेश व सुरेश ने कांस्य, सब जूनियर विश्व मुक्केबाजी में सुनील ने स्वर्ण, बलविंद्र ने रजत व मनजीत ने कांस्य पदक जीते।

जून 1996 से लेकर आज तक कोच जगदीश सिंह द्वारा तैयार किए गए मुक्केबाज सैकड़ों पदक अपनी झोली में डाल चुके हैं। जगदीश सिंह के शिष्य राजीव ने 1996 में कांस्य, लखविंद्र, विजेंद्र, विनोद व विक्रम गौतम ने अंतरराष्ट्रीय

स्तर पर रजत पदक हासिल किया। भिवानी के मुक्केबाजों की इस गौरवमयी यात्रा में इस तरह के अनेक नाम हैं। भिवानी के बॉक्सिंग इतिहास में मील का पत्थर वर्ष 2008 रहा। इस वर्ष मास्को में आयोजित विश्वकप मुक्केबाजी में बॉक्सर दिनेश ने जून 2009 में चीन में आयोजित सीनियर एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक हासिल किया। वर्ष 2010 मार्च में दिल्ली में आयोजित राष्ट्रमंडल मुक्केबाजी स्पर्धा में स्वर्ण पदक भी हासिल किया। विजेंद्र ने जून 2009 में चीन में आयोजित सीनियर एशियाई मुक्केबाजी में कांस्य पदक एवं मार्च 2010 में दिल्ली में आयोजित राष्ट्रमंडल मुक्केबाजी स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। वर्ष 2008 में साई छात्रावास के अखिल कुमार, विजेंद्र सिंह, जितेंद्र व दिनेश ने ओलंपिक के लिए क्वालीफाई किया। विजेंद्र ने बीजिंग ओलंपिक में मुक्केबाजी में पहला कांस्य पदक जीता।

भिवानी को मिनी क्यूबा के रूप में विख्यात करने में निस्संदेह कोच व खिलाड़ियों की मेहनत के साथ-साथ अभिभावकों का जुनून भी शामिल है जो अपने सितारों को अपने आंचल से निकालकर कोचों की झोली में डाल देते हैं। देश में अगर भारत को खेलों के शिखर पर पहुंचना है तो हर शहर में एक भिवानी गढ़ना होगा। एक मरु शहर के मिनी क्यूबा के रूप में विख्यात होने के पीछे की कहानी अगर अन्यत्र भी दुहराई जाए तो भारत की आने वाली पीढ़ियां अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेलों में काफ़ी आगे निकल सकती हैं। □

(लेखक दैनिक भास्कर के भिवानी स्थित ब्यूरो प्रमुख हैं)

भारत के स्वर्णिम कीर्ति स्तंभ

● देवेन्द्र भारद्वाज

आदर्श रूप में कहा जा सकता है कि प्रतिस्पर्द्धा में सफलता ही सब कुछ नहीं है, इसमें भाग लेकर अपनी चुनौती को यथा शक्ति प्रस्तुत करना भी महत्वपूर्ण है। पर वास्तविकता के धरातल पर स्थिति भिन्न है। सर्वत्र विजेताओं की जय जयकार होती है। खेल प्रेमी विजेताओं का ही अभिनंदन करते हैं और स्वयं खिलाड़ी भी विजय को ही लक्ष्य मान कर मैदान में उतरते हैं। वैसे तो हर पदक विजेता प्रशंसा का भागी होता है, पर स्वर्णिम सफलता की आभा ही अलग होती है। फलस्वरूप सर्वाधिक सम्मान, प्रशंसा, यश और प्रतिष्ठा स्वर्ण पदक विजेताओं की झोली में ही आती है।

कहने के लिए 1934 में लंदन में हुए दूसरे राष्ट्रमंडल खेलों में पहलवान रशीद अनवर ने पदक तालिका में भारत का नाम दर्ज कराया था, पर स्वर्णिम सफलता के द्वार भारत के लिए पहली बार 1958 में कार्डिफ (वेल्स) खेलों में खुले, जब 'उड़न सिख' मिल्खा सिंह और हेवीवेट मल्ल लीलाराम ने अपनी-अपनी स्पर्द्धाओं में सर्वजयी बनने का गौरव प्राप्त किया। भारत की स्वर्णिम सफलता के इन दोनों अग्रदूतों ने जो अलख जगाई, उसके परिणामस्वरूप भारत द्वारा अर्जित स्वर्ण पदकों की संख्या में निरंतर वृद्धि हुई। वर्ष 2002 के मैनचेस्टर (इंग्लैंड) और 2006 के मेलबर्न (ऑस्ट्रेलिया) खेलों में तो भारत को आशातीत स्वर्णिम सफलताएं मिलीं।

पहलवानों

इसे संयोग कहा जाए या विडंबना, 'उड़न सिख' मितखा सिंह द्वारा कार्डिफ खेलों की 440 गज दौड़ में नये राष्ट्रमंडल रिकॉर्ड के साथ अर्जित स्वर्ण पदक एथलेटिक्स में भारत का एकमात्र स्वर्ण पदक है। पांच दशक का लंबा समय बीतने के बावजूद कोई भी भारतीय धावक

या एथलीट स्वर्ण पदक नहीं हासिल कर सका। दूसरी ओर, कुश्ती में लीलाराम की उपलब्धि से प्रेरित हो किंगसटन (जमैका), एडिनबरा (स्कॉटलैंड), क्राइस्टचर्च, (न्यूजीलैंड), एडमंटन (कनाडा) और ब्रिस्बेन (ऑस्ट्रेलिया) में वर्ष 1966 से 1982 के बीच संपन्न पांच राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय पहलवानों ने 19 स्वर्ण पदक भारत के लिए अर्जित किए। स्मरणीय है कि जब-जब कुश्ती राष्ट्रमंडल खेलों के कार्यक्रम में शामिल रही, भारतीय पहलवानों ने निराशा नहीं किया। सुदेश कुमार, मुख्तियार सिंह और राजेंद्र सिंह ने अपनी-अपनी भार श्रेणी में लगातार दो खेलों में स्वर्ण पदक जीते।

भारोत्तोलन और निशानेबाजी

पहलवानों के बाद भारोत्तोलकों और निशानेबाजों ने अपना कमाल दिखाया। यद्यपि भारोत्तोलन में भारत को पहली बार स्वर्ण पदक ईगेत्तुर करुणाकरण ने सन् 1978 के एडमंटन खेलों में 52 किलोग्राम की श्रेणी में दिलाया था, पर स्वर्ण पदकों का वास्तविक सिलसिला सन् 1990 के आकलैंड (न्यूजीलैंड) खेलों से शुरू हुआ, जो निरंतर जारी है। सन् 2002 के मैनचेस्टर और सन् 2006 के मेलबर्न खेलों में महिला भारोत्तोलकों ने भारत का झंडा ऊंचा रखा। अपनी बढ़ती उम्र को झुठलाते हुए भारतीय भारोत्तोलन की अमरनायिका एन. कुंजुगानी देवी ने पिछले दो राष्ट्रमंडल खेलों में अपनी 48 किलोग्राम भार श्रेणी में 4 स्वर्ण पदक भारत के लिए अर्जित किए। भारोत्तोलन में भारत के लिए तीन-तीन स्वर्ण पद हासिल करने का श्रेय पांच भारोत्तोलकों को है। ये हैं— राघवन चंद्रशेखरन (52 किलोग्राम भार श्रेणी), पोन्नुसामी रंगास्वामी (56 किलोग्राम भार श्रेणी), परमजीत शर्मा (67.5 किलोग्राम भार श्रेणी), सानामाचा चानू

(महिलाओं की 53 किलोग्राम भार श्रेणी) और शैलजा पुजारी (महिलाओं की 75 किलोग्राम भार श्रेणी)।

जसपाल राणा और समरेश अद्वितीय

राष्ट्रमंडल खेलों में निशानेबाजी में भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाने का श्रेय अशोक पंडित को है, जिसने यह करिश्मा सन् 1990 के आकलैंड (न्यूजीलैंड) खेलों में दिखाया था। अशोक पंडित के स्वर्णिम प्रदर्शन का ऐसा जादुई प्रभाव पड़ा की भारतीय निशानेबाजी के लिए सफलता के द्वार खुलते चले गए। सन् 2002 के मैनचेस्टर और सन् 2006 के मेलबर्न खेलों में तो भारतीय लक्ष्यवेधियों का प्रदर्शन अत्यंत प्रभावशाली रहा, जहां उन्होंने क्रमशः 14 स्वर्ण और 16 रजत पदक अर्जित कर राष्ट्रीय गौरव में अभिवृद्धि की।

अशोक पंडित ने जसपाल राणा के साथ मिलकर सन् 1994 के विकटोरिया खेलों और सन् 1998 के कुआलालंपुर खेलों में सेंटर फायर पिस्टल पेअर्स स्पर्द्धा में स्वर्ण पदक जीते। उल्लेखनीय है कि अशोक पंडित के सुपुत्र रौनक पंडित ने भी यशस्वी पिता के पदचिह्नों पर चलते हुए सन् 2006 के मेलबर्न खेलों में समरेश जंग के साथ मिलकर 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल पेअर्स स्पर्द्धा में स्वर्ण पदक अर्जित किया।

वैसे तो अनेक भारतीय लक्ष्यवेधियों ने राष्ट्रमंडल खेलों में अपने स्वर्णिम प्रदर्शन से स्वयं को और राष्ट्र को गौरवमंडित किया, जिनमें महिलाओं ने रूपा उन्नीकृष्णन से लेकर अंजलि भागवत, अनुजा जंग, तेजस्विनी सावंत तक और पुरुषों में अभिनव बिंद्रा से लेकर राज्यवर्द्धन सिंह राठौर, मनशेर सिंह, मानवजीत सिंह, मुराद अली खान और गगन नारंग तक के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। पर सबसे ज्यादा प्रशंसा के

भागी हैं जसपाल राणा और समरेश जंग, जिनका प्रदर्शन अति विशिष्ट और विलक्षण रहा है। पिता द्वारा प्रशिक्षित नैसर्गिक प्रतिभा के धनी जसपाल राणा ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक नहीं अनेक बार अपनी प्रतिभा की अमिट छाप छोड़ी है, पर राष्ट्रमंडल खेलों में अचूक भारतीय लक्ष्यवेधी का प्रदर्शन विस्मयकारी रहा है। सन् 1994 से 2006 के बीच चार राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए जसपाल राणा ने कुल 9 स्वर्ण, 4 रजत और 2 कांस्य पदक अर्जित किए। निर्विवाद रूप से यह अति सराहनीय और उच्च कोटि का प्रदर्शन है।

जसपाल राणा के लिए सन् 2002 के मैनचेस्टर खेल विशेष रूप से आह्लादकारी थे, जहां उसने 4 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक अपने नाम दर्ज कराए थे। मेलबोर्न खेलों में निशानेबाजी की विभिन्न स्पर्द्धाओं में समरेश जंग ने 5 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक अर्जित कर न सिर्फ श्रेष्ठ प्रदर्शन किया, बल्कि इस विलक्षण प्रदर्शन के आधार पर वह 18वें राष्ट्रमंडल खेलों में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुने गए और इसके लिए 'डेविड डिकसन' पुरस्कार से सम्मानित हुए। स्मरणीय है कि मेलबोर्न राष्ट्रमंडल खेलों में समरेश जंग की पत्नी अनुजा जंग ने 50 मीटर राइफल श्री पोजीशंस स्पर्द्धा में स्वर्ण पदक और 50 मीटर राइफल श्री पोजीशंस पेअर्स स्पर्द्धा में रजत पदक अर्जित किया। इस प्रकार जंग दंपति के लिए मेलबोर्न खेल यादगार बन गया।

स्तुत्य प्रदर्शन अन्य विजेताओं का

यह सत्य है कि कुश्ती, भारोत्तोलन और निशानेबाजी ने भारत को राष्ट्रमंडल खेलों में अधिसंख्य स्वर्ण पदक दिलाए, पर इसका यह अर्थ नहीं कि अन्य खेल विधाओं में स्वर्ण पदक विजेताओं का महत्व किसी भी दृष्टि से कम है भले ही वे गिने-चुने हैं। इनमें से कई तो भारतीय खेलों के महिमामंडित नाम हैं। राष्ट्रमंडल खेलों

में एथलेटिक्स में भारत को एकमात्र स्वर्ण पदक दिलाने वाले मिल्खा सिंह किवदंती नायकों की तरह आज भी भारतीय एथलेटिक्स में वंदनीय हैं। सन् 1960 के रोम ओलंपिक खेलों की 400 मीटर दौड़ के फाइनल में इस महान भारतीय धावक का पदक से बाल-बाल चूकना एक निराशाजनक घटना के रूप में याद किया जाता है। मिल्खा सिंह अपने समय के एशिया के सर्वश्रेष्ठ धावकों में से एक थे।

सन् 1978 के एडमंटन (कनाडा) खेलों में पहली बार भारत को बैडमिंटन में स्वर्ण पदक दिलाने वाला प्रकाश पाडुकोण एक के बाद एक सफलता अर्जित करता हुआ उन ऊंचाइयों तक पहुंचा, जहां बिरले ही प्रतिष्ठित हो पाते हैं। यद्यपि भारतीय बैडमिंटन में त्रिलोक नाथ सेठ, नंदू नाटेकर आदि अनेक श्रेष्ठ खिलाड़ी उदित हुए, पर विश्व स्तर पर राष्ट्रीय गौरव में अभिवृद्धि प्रकाश पाडुकोण ने ही की, जो सही अर्थों में अपने काल में भारतीय बैडमिंटन का प्रकाश स्तंभ रहा। लंदन में मास्टर्स कप और ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन प्रतियोगिता के विजेता प्रकाश पाडुकोण ने अपने समय में चीनी बैडमिंटन जादूगरों सहित इंडोनेशिया और डेनमार्क के विश्व विख्यात खिलाड़ियों पर एक बार नहीं कई-कई बार अपनी प्रतिभा का सिक्का जमाया। सन् 1982 के ब्रिस्बेन खेलों में भारत को बैडमिंटन में स्वर्ण पदक दिलाने वाला सैयद मोदी भी उच्च कोटि का फ्रनकार रहा है। भले ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सैयद मोदी प्रकाश पाडुकोण की तरह स्वयं को प्रतिष्ठित नहीं कर सका, पर राष्ट्रीय स्तर पर वह प्रकाश का वास्तविक उत्तराधिकारी था।

मुक्केबाजी में कम वजन वाले दो मुक्केबाजों ने इतिहास रचते हुए स्वर्ण पदक अर्जित कर राष्ट्र का मस्तक ऊंचा किया। सन् 2002 के मैनचेस्टर खेलों में लाइट फ्लाइट मोहम्मद

अली कमर (48 किलोग्राम श्रेणी) ने और सन् 2006 के मेलबोर्न खेलों में बैटमवेट अखिल कुमार (54 किलोग्राम भार श्रेणी) ने कड़े मुकाबले में स्वर्णिम प्रदर्शन कर अपनी जुझारू क्षमता का परिचय दिया।

टेबल टेनिस में निरंतर प्रगति पर अग्रसर अर्चित शरद कमल ने वह कर दिखाया जो अब तक अकल्पनीय था। कौशल और जीवट के समन्वय का शानदार नमूना पेश करते हुए अर्चित शरद कमल ने मेलबोर्न खेलों में पुरुष एकल खिताब भी अपने नाम कर लिया और स्पर्द्धा का स्वर्ण पदक जीतने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

भारतीय महिला हॉकी टीम का प्रदर्शन भी प्रशंसनीय है जिसने पूर्वानुमानों को झुठलाते हुए विश्व रैंकिंग में अपने से कहीं श्रेष्ठ टीमों की उपस्थिति में सन् 2002 के मैनचेस्टर खेलों में स्वर्ण पदक अर्जित किया। मैनचेस्टर विजय मात्र संयोग नहीं था, इसका प्रमाण दिया महिला हॉकी टीम ने चार वर्ष बाद मेलबोर्न में जहां वह फाइनल में मेजबान ऑस्ट्रेलिया से जूझते हुए रजत पदक की हकदार बनी।

राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के स्वर्ण पदक विजेता

अब तक राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने आठ खेल विधाओं में कुल मिलाकर 102 स्वर्ण पदक जीते हैं। इनमें सर्वाधिक 38 स्वर्ण पदक निशानेबाजी में निशानेबाजों ने अर्जित किए हैं। इसके बाद महत्वपूर्ण योगदान रहा है भारोत्तोलकों और पहलवानों का जिन्होंने क्रमशः 33 स्वर्ण और 23 स्वर्ण पदक भारत को दिलाए हैं। बैडमिंटन, मुक्केबाजी और टेबल टेनिस में भारत को दो-दो स्वर्ण पदक मिले हैं। एथलेटिक्स और महिला हॉकी में एक-एक स्वर्ण पदक भारत की झोली में आया है। □

(लेखक वरिष्ठ खेल पत्रकार हैं।

साभार : राष्ट्रमंडल खेल शीर्षक पुस्तक)

अपने लेख हमें ई-मेल करें

आप हमें अपने लेख और पत्र ई-मेल भी कर सकते हैं। ई-मेल करने इसके लिए कृतिदेव फांट इस्तेमाल करें और वर्ड ओपन फाईल exeed.yojana@gmail.com अथवा yojanahindi@gmail.com पर भेजें। एक से अधिक लेखकों के नाम केवल विशेष शोध लेखों पर ही दें। जिन रचनाओं के साथ मौलिकता का प्रमाणपत्र संलग्न नहीं होगा वे स्वीकार नहीं की जा सकेंगी। रचना के प्रकाशन के संबंध में किसी प्रकार का पत्र-व्यवहार अथवा फोन न करें। विशेष अवसरों के लिए लेख तीन माह पूर्व प्राप्त हो जाने चाहिए। रचनाओं के साथ यथासंभव प्रासंगिक चित्र भी भेजें। डाक से भेजे जाने वाले लेखों की एक प्रति सीडी में भी भेजें। वापसी के लिए कृपया टिकट लगा और पता लिखा लिफाफा संलग्न करें।

- वरिष्ठ संपादक

राष्ट्रमंडल खेल : ऐसे हुआ जन्म

बात उन दिनों की है कि जब ओलंपिक खेल शुरू भी नहीं हुए थे। ब्रिटिश साम्राज्य अपनी समृद्धि, ऐश्वर्य और वैभव के चरम पर था। कनाडा से लेकर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड तथा भारतीय उपमहाद्वीप तक फैले इस शक्तिशाली साम्राज्य में कैरीबियन सागर के अनेक द्वीप और अफ्रीका के कतिपय भू-भाग शामिल थे। इसके बारे में उचित ही कहा जाता था कि यहां सूर्य अस्त नहीं होता। जब आर्थिक समृद्धि तथा सुख-शांति हो, सामरिक सामर्थ्य से उपजा आत्मविश्वास हो तो जीवन के उन पहलुओं को भी प्राथमिकता मिलने लगती है जिन पर सामान्यतः ध्यान नहीं जाता। ऐसे ही माहौल में एस्टली कूपर नामक इंग्लैंड के एक ईसाई धर्मगुरु ने लंदन के महत्वपूर्ण प्रकाशनों में अखिल ब्रितानी-अखिल आंग्ल खेल महोत्सव प्रारंभ करने की वकालत की, इस सुझाव की आमतौर पर सभी ने सराहना की। एस्टली कूपर का विचार था कि इससे ब्रिटिश साम्राज्य के अंग देशों के बीच मित्रता और सद्भाव बढ़ेगा। यह बात 1891 की है। एस्टली कूपर के इस युगांतकारी सुझाव को आमतौर पर राष्ट्रमंडल खेलों के बीजारोपण के रूप में देखा जाता है। स्मरणीय है कि प्रथम

आधुनिक ओलंपिक खेल 1896 में ग्रीस की राजधानी एथेंस में संपन्न हुए थे।

इसे संयोग कहिए या दूरदर्शी विचारक एस्टली कूपर से मिली प्रेरणा का प्रभाव, ग्रेट ब्रिटेन के सम्राट जार्ज पंचम के राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में सन् 1911 में लंदन के क्रिस्टल पैलेस में जो भव्य समारोह आयोजित हुए, उसी का एक अंग था यह खेल समारोह। इस खेल समारोह में मेजबान ग्रेट ब्रिटेन के अलावा ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और दक्षिण अफ्रीका के एथलीटों, मुक्केबाजों, तैराकों और पहलवानों ने हिस्सा लिया। इसमें विजेता रहा कनाडा, जिसे ब्रिटेन के खेल प्रेमी लॉर्ड लंसडेल की ओर से ढाई फुट ऊंचा और 340 औंस भारी चांदी का एक कप प्रदान किया गया। जॉर्ज पंचम के राज्याभिषेक के अवसर पर आयोजित इस खेल समारोह को कुछ लोग राष्ट्रमंडल खेलों के प्रथम लघु संस्करण के रूप में देखते हैं, जबकि अन्य उनके इस विचार से सहमत नहीं हैं। बहरहाल, इतना तो तय है कि एस्टली कूपर ने ब्रिटिश साम्राज्य के लिए जिस खेल समारोह की कल्पना की थी, वह 1911 में फलीभूत हुआ, भले ही संक्षिप्त रूप में।

सोच, विचार और सिद्धांत अजर-अमर होते हैं। इसी मान्यता को सार्थक करते हुए ऑस्ट्रेलिया के रिचर्ड कूमब्स जो 35 वर्ष तक अमेच्योर एथलेटिक यूनियन ऑफ ऑस्ट्रेलिया के अध्यक्ष थे और कनाडा के नोर्टन क्रो ने एस्टली कूपर की अखिल ब्रिटिश साम्राज्य खेलों की अवधारणा को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान किया। इस दिशा में ठोस काम हुआ 1928 के एम्स्टर्डम (हॉलैंड) ओलंपिक खेलों के दौरान, जहां ब्रिटिश साम्राज्य के अंग विभिन्न देशों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। मित्रता और सहयोग की भावना बलवती हुई और आम सहमति बनी कि क्यों न ब्रिटिश साम्राज्य के देशों के लिए अलग से खेल हो। इसमें सर्वाधिक सक्रिय भूमिका निभाने और पहल करने का श्रेय रहा कनाडा की एथलेटिक्स टीम के मैनेजर एम.एम. रॉबिनसन को। एम्स्टर्डम खेलों के समापन के बाद भी रॉबिनसन के प्रयास जारी रहे और यह उसके दृढ़संकल्प का ही परिणाम था जो सन् 1930 में राष्ट्रमंडल खेल अपने मूल नाम 'ब्रिटिश एंपायर गेम्स' के रूप में अस्तित्व में आए। अधिकृत रूप से यह फ़ैसला हुआ कि ये ओलंपिक खेलों की तर्ज पर होंगे और गैर-पेशेवर एथलीट की परिभाषा भी



योजना, सितंबर 2010



वही होगी जो ओलंपिक खेलों के लिए होती है। पर ये खेल जबरदस्त होड़ और सर्वोपरि विजय की भावना के बजाय हर्षोल्लास और सहयोग के वातावरण में आयोजित होंगे।

मेज़बानी कनाडा को

प्रथम 'ब्रिटिश एंपायर गेम्स' के आयोजन का श्रेय कनाडा को रहा, जिसने भारी आर्थिक मंदी के वातावरण के बावजूद अपना दायित्व बखूबी निभाया। अगस्त 1930 में हैमिल्टन (कनाडा) में संपन्न इन खेलों में वे चार-एथलेटिक्स, मुक्केबाजी, तैराकी और कुश्ती-खेल विधाएं थीं, जो 1911 में लंदन के क्रिस्टल पैलेस में आयोजित खेल समारोह में शामिल थीं। इसके अतिरिक्त दो अन्य खेल- लॉन बोल्लस और नौकायन (रोइंग) भी प्रथम 'ब्रिटिश एंपायर गेम्स' में सम्मिलित थे। हैमिल्टन में ही यह महत्वपूर्ण फैसला लिया गया कि अब ये खेल हर चार वर्ष बाद ओलंपिक चतुर्वर्षीय चक्र के मध्य में आयोजित हुआ करेंगे। तब से यह आयोजन क्रम अनवरत जारी है। दूसरा महत्वपूर्ण निर्णय था 'ब्रिटिश एंपायर गेम्स फेडरेशन' की स्थापना के बारे में। 1932 के लॉस एंजेलस ओलंपिक खेलों के दौरान फेडरेशन की स्थापना के मसले पर और विचार-विमर्श हुआ तथा फेडरेशन अस्तित्व में आया तथा कर्नल ईवान हंटर को इसका सर्वप्रथम सेक्रेटरी बनने का गौरव प्राप्त हुआ।

हैमिल्टन खेलों के दौरान दक्षिण अफ्रीका का अगले खेलों की मेज़बानी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया था, पर अश्वेतों के प्रति उसके रवैये को देखते हुए 1932 में लास एंजेलस में विचार-विमर्श के बाद ब्रिटिश एंपायर गेम्स फेडरेशन ने निर्णय किया कि 1934 के खेलों की मेज़बानी दक्षिण अफ्रीका के बजाय इंग्लैंड को सौंपी जाए। फलस्वरूप 1934 में दूसरे 'ब्रिटिश एंपायर गेम्स' लंदन में संपन्न हुए, जिसमें पहली बार महिला खिलाड़ियों ने भाग लिया।

नाम में परिवर्तन

1954 में वैनकूवर (कनाडा) में संपन्न पांचवें खेलों के दौरान निर्णय लिया गया कि इन्हें 'ब्रिटिश एंपायर एंड कामनवेल्थ गेम्स' नाम से संबोधित किया जाए। यही वे खेल थे, जिनके दौरान इंग्लैंड के विश्वविख्यात धावक रोजर बैनिस्टर ने अपने ऑस्ट्रेलियाई चिर प्रतिद्वंद्वी जॉन लैंडी को एक मील दौड़ की स्पर्द्धा में परास्त कर चार मिनट से कम समय निकालने का इतिहास रचा था।

1966 में किंग्सटन (जमैका) में आयोजित आठवें खेलों के दौरान नाम में फिर परिवर्तन हुआ। निर्णय लिया गया कि 'एंपायर' शब्द हटा कर इन्हें 'ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम्स' कहा जाए। आठ साल बाद 1974 में क्राइस्टचर्च (न्यूजीलैंड) में आयोजित दसवें खेलों में एक बार पुनः इसका नाम बदला गया, पर इस बार परिवर्तन निर्णायक सिद्ध हुआ। इस बार निर्णय हुआ कि 'ब्रिटिश' शब्द भी हटा दिया जाए। और, इस तरह इन खेलों को अपना वर्तमान नाम 'कॉमनवेल्थ गेम्स' यानी 'राष्ट्रमंडल खेल' मिला।

सर्वाधिक आयोजन

1930 से लेकर अब तक अठारह बार राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन हो चुका है।



कनाडा और ऑस्ट्रेलिया दो ऐसे देश हैं, जिन्हें इन खेलों को चार-चार बार आयोजित करने का श्रेय प्राप्त है। 1930 में कनाडा के हैमिल्टन में, 1954 में वैनकूवर में, 1978 में एडमंटन और 1994 में विक्टोरिया में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कर चुका है। ऑस्ट्रेलिया भी इन्हें 1938 में सिडनी, 1962 में पर्थ, 1982 में ब्रिस्बेन और 2000 में मेलबर्न में आयोजित कर चुका है।

ग्रेट ब्रिटेन में ये खेल पांच बार आयोजित हुए। इंग्लैंड में 1934 में लंदन में और मैनचेस्टर में 2002 में। स्कॉटलैंड भी दो बार इनका मेज़बान रहा और दोनों बार ये एडिनबरा में ही संपन्न हुए, पहली बार 1970 में और दूसरी बार 1986 में। वेल्स का आतिथेय एक बार रहा, जब 1958 में ये खेल कोर्डिफ में संपन्न हुए। न्यूजीलैंड ने राष्ट्रमंडल खेलों की तीन बार मेज़बानी की। न्यूजीलैंड के ऑकलैंड नगर को दो बार खेल आयोजित करने का श्रेय रहा, पहली बार 1950 में और दूसरी बार 1990 में जबकि क्राइस्टचर्च में ये 1974 में संपन्न हुए।

विकसित देशों के अलावा दो अन्य देशों को भी राष्ट्रमंडल खेलों के आयोजन का गौरव प्राप्त है। ये हैं— जमैका और मलेशिया। जमैका की राजधानी किंग्सटन में 1966 में और मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में ये 1998 में आयोजित हुए। अब 19वें राष्ट्रमंडल खेल इस साल भारत की राजधानी दिल्ली में आगामी 3 अक्टूबर से प्रारंभ हों रहे हैं यानी एशिया में केवल दूसरी बार इसका आयोजन होगा।

इसे संयोग ही कहा जाएगा कि जिस वर्ष राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन होता है, उसी वर्ष दो अन्य खेल महोत्सव संपन्न होते हैं। ये हैं फुटबॉल का विश्व कप और एशियाई खेल। उल्लेखनीय है कि फुटबॉल का विश्व कप 1930 में राष्ट्रमंडल खेलों से करीब एक महीने पहले शुरू हुआ था। जबकि एशियाई खेल दो दशक बाद अस्तित्व में आए।

राष्ट्रमंडल संघ

यहां पर राष्ट्रमंडल संघ की चर्चा करना भी तर्कसंगत है, क्योंकि इसके सदस्य देश ही राष्ट्रमंडल खेलों में भाग ले सकते हैं। यद्यपि राष्ट्रमंडल की स्थापना सिद्धांत रूप में 1926 की इंपीरियल कॉफ्रेंस में स्वीकार कर ली गई थी, किंतु यह अस्तित्व में तब आया जब युनाइटेड किंगडम यानी ग्रेट ब्रिटेन, उत्तरी आयरलैंड और कुछ छोटे द्वीपों के संयुक्त साम्राज्य ने तथा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने मिलकर 1931 में राष्ट्रमंडल की स्थापना की। इसके सदस्य देशों का कानूनी दर्जा क्या होगा, इसकी व्याख्या 1931 में ही राष्ट्रमंडल की स्थापना से पूर्व निर्मित वेस्टमिंस्टर संविधि में की गई है। मोटे तौर पर राष्ट्रमंडल उन स्वतंत्र देशों का संघ है, जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य के अंग थे। उदाहरणार्थ, एक गणराज्य के रूप में भारत 1947 में राष्ट्रमंडल का सदस्य बना। राजनीतिक दृष्टि से राष्ट्रमंडल के शासनाध्यक्षों का सम्मेलन एक विश्वस्तरीय महत्वपूर्ण घटना है। इस समय 53 प्रभुसत्ता संपन्न स्वतंत्र देश राष्ट्रमंडल संघ के सदस्य हैं। शेष ग्रेट ब्रिटेन के आश्रित प्रदेश या सदस्य देशों के अधीन प्रदेश हैं।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि आयरलैंड ने 1948 में राष्ट्रमंडल की सदस्यता छोड़ी, जबकि 1961 में दक्षिण अफ्रीका और 1972 में पाकिस्तान की सदस्यता रद्द हुई। 1989 में पाकिस्तान और 1994 में दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रमंडल में पुनः सम्मिलित कर लिए गए। □

(प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित पुस्तक राष्ट्रमंडल खेल से साभार)



उन्नीसवें राष्ट्रमंडल खेल दिल्ली में

निशानेबाजी, कुश्ती, भारोत्तोलन, मुक्केबाजी और तीरंदाजी में भारत को स्वर्णिम सफलताएं हासिल करने की उम्मीद है। बैडमिंटन, टेबल टेनिस, एथलेटिक्स और टेनिस में भी हमें सफलता की उम्मीद है

दो बार एशियाई खेलों का आयोजन कर चुका भारत इस साल 19वें राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कर रहा है। विश्वविख्यात राष्ट्रमंडल खेलों के 80 वर्ष के लंबे इतिहास में यह सिर्फ दूसरा अवसर होगा कि जब ये मैत्री खेल एशिया में हो रहे हैं। इससे पूर्व वर्ष 1998 में सोलहवें राष्ट्रमंडल खेल मलेशिया की राजधानी कुआलालम्पुर में संपन्न हुए थे।

ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत की मनोरम इंद्रधनुषी छवि के साथ दिल्ली महानगर पुरातन और आधुनिकता का दर्शनीय संगम है। 3 से 14 अक्टूबर, 2010 के दौरान आयोजित होने वाले उन्नीसवें राष्ट्रमंडल खेलों को अब तक हुए खेलों से भव्य और सफल बनाने के लिए दिल्ली कृतसंकल्प है और इसके लिए हर पहलू पर ध्यान दिया जा रहा है। प्रयास यही है कि भारत ने जिस ऊर्जा के साथ विश्व समुदाय में अपनी जो ऊंची साख बनाई है आगामी राष्ट्रमंडल खेल उसी के अनुरूप हों।

आज अंतरराष्ट्रीय समुदाय के समक्ष सबसे बड़ी समस्या है पर्यावरण को प्रभावित करने वाली विश्वव्यापी ऊष्णता के कुप्रभाव से बचने की, और इसे ध्यान में रखते हुए आगामी खेलों को हरित छवि प्रदान करने के लिए दिल्ली में भरसक प्रयास किए गए हैं। राजधानी को और ज्यादा सुंदर तथा विश्वस्तरीय सुविधासंपन्न महानगर बनाने के साथ-साथ विभिन्न खेलों के लिए आधुनिकतम बुनियादी सुविधाएं जुटाने के

लिए जो निर्माण कार्य किए गए हैं, उनमें इस बात का पूरा ध्यान रखा गया कि पर्यावरण पर इसका विपरीत प्रभाव न पड़े। यह भी कोशिश है कि आगामी खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों, अधिकारियों, मीडियाकर्मियों और पर्यटकों को हर संभव अपेक्षित सुविधा मिल सके। यह काम आसान नहीं है, पर प्रयास जारी हैं।

आज विश्व में हर खेल महोत्सव के पीछे एक बड़ा उद्देश्य यह भी रहता है कि इनसे व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा मिले, मेजबान नगर और राष्ट्र की छवि उज्वल हो। उन्नीसवां राष्ट्रमंडल खेल भी इसका अपवाद नहीं है। दिल्ली के राष्ट्रमंडल खेलों को सफलतम बनाने के पीछे एक मकसद यह भी है कि दिल्ली भविष्य में ओलंपिक खेलों के लिए अपना दावा मजबूती से पेश कर सके।

प्रतीक चिह्न

6 जनवरी, 2008 को राष्ट्रमंडल खेल संघ के अध्यक्ष माइक फेनेल ने दिल्ली राष्ट्रमंडल खेलों के लोगो (प्रतीक चिह्न) जारी किया। इसके साथ ही इन खेलों के समारंभ की उल्टी गिनती शुरू हो गई जिसका संदेश था कि अब खेलों के शुरू होने में सिर्फ 1,000 दिन रह गए हैं। इस अवसर पर दिल्ली के दो ऐतिहासिक स्थलों विजय चौक और इंडिया गेट के बीच एक सामूहिक दौड़ का आयोजन हुआ, जिसमें स्कूली बच्चों, युवाओं, प्रौढ़ों से लेकर देश के यशस्वी नये-पुराने खिलाड़ियों ने भाग लिया। दौड़ में भाग

लेने वालों के हरे ट्रैक सूट और हरी जर्सियां इस बात के परिचायक थे कि दिल्ली में आयोजित आगामी राष्ट्रमंडल खेल पर्यावरण के अनुकूल हरित होंगे। दिल्ली के उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री और उन्नीसवें राष्ट्रमंडल खेल आयोजन समिति के साथ-साथ समस्त देशवासी आश्वस्त हैं कि खेल संबंधी हर कार्य योजनानुसार समय पर संपन्न होगा और दिल्ली राष्ट्रमंडल खेल सफलतम और भव्यतम होंगे।

मेहमानों के स्वागत के लिए दिल्ली सज-संवर कर तैयार रहे और आगंतुकों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए दिल्ली सरकार कृतसंकल्प है। आने-जाने में किसी को दिक्कत न हो, इसके लिए फ्लाईओवर, अंडरपास, संपर्क मार्ग आदि ढांचागत बुनियादी सुविधाओं का दिल्ली में जाल-सा बिछा दिया गया है। भारत सरकार भी दिल्ली सरकार को हर तरह की सुविधा मुहैया करा रही है।

सत्रह खेल विधाएं

दिल्ली के उन्नीसवें राष्ट्रमंडल खेलों में सत्रह खेल विधाओं की प्रतियोगिताएं होंगी। ये खेल हैं— एथलेटिक्स, तैराकी एवं ड्राइविंग, बैडमिंटन, मुक्केबाजी, साइकिल चालन, तीरंदाजी, जिम्नास्टिक्स, हॉकी, लॉन बोल्लस, नेटबॉल, रग्बी सेवन, निशानेबाजी, स्कवैश, टेबल टेनिस, टेनिस, भारोत्तोलन और कुश्ती। इनमें से कुछ चुनी हुई खेल विधाओं में शारीरिक अक्षमता ग्रस्त खिलाड़ियों के लिए ईएडी (इलीट एथलीट्स

विद ए डिस्प्लिबिलिटी) स्पर्धाएं भी होंगी।

अलग-अलग प्रतियोगिता स्थल

दिल्ली राष्ट्रमंडल खेलों का एक महत्वपूर्ण केंद्र जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम होगा, जिसका छवि और उपयोगिता दोनों ही दृष्टि से विश्वस्तरीय बनाने के लिए आधुनिकीकरण किया गया है। उन्नीसवें राष्ट्रमंडल खेलों के उद्घाटन और समापन समारोह इसी स्टेडियम में होंगे। एथलेटिक्स प्रतियोगिता की विभिन्न स्पर्धाओं, भारोत्तोलन और लॉन बोलस प्रतियोगिताओं का आयोजन जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में ही होगा।

जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम की तरह इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम, मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम, तालकटोरा स्वीमिंग पूल और कर्णी सिंह शूटिंग रेंज का भी आधुनिकीकरण कर उन्हें नया रंग-रूप दिया गया है। इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में साइकिल चालन, जिम्नास्टिक्स और कुश्ती की स्पर्धाएं आयोजित होंगी। मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में हॉकी प्रतियोगिता और कर्णी सिंह शूटिंग रेंज में निशानेबाजी की स्पर्धाएं संपन्न होंगी।

तालकटोरा स्टेडियम भी नवीकरण के बाद एक नये, सुंदर और उपयोगी रूप में तरण ताल की स्पर्धाओं के बजाय मुक्केबाजी के मुक्काबले देखने को मिलेंगे। नयी दिल्ली नगर पालिका ने तालकटोरा स्टेडियम को एक विश्वस्तरीय मुक्केबाजी केंद्र के रूप में विकसित किया है।

सीरी फोर्ट खेल परिसर बैडमिंटन और स्क्वैश प्रतियोगिताओं का आयोजन स्थल रहेगा। यमुना खेल परिसर टेबल टेनिस प्रतियोगिता का केंद्र रहेगा। देश के प्रथम 'हरित' स्टेडियम के रूप में विकसित त्यागराज खेल परिसर में नेटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इस खेल परिसर में जल संरक्षण और सौर ऊर्जा का उपयोग मुख्य विशेषताएं हैं।

आर.के. खन्ना टेनिस परिसर में टेनिस प्रतियोगिता संपन्न होगी। यमुना खेल परिसर में तीरंदाजी की स्पर्धाएं भी होंगी, पर इनके फाइनल इंडिया गेट पर नेशनल स्टेडियम के सामने 'सी' हेक्सागन में आयोजित करने का प्रस्ताव है। दिल्ली विश्वविद्यालय ड्राइविंग सहित तैराकी की विभिन्न स्पर्धाओं और रग्बी सेवन प्रतियोगिता का आयोजन स्थल बना है।

उन्नीसवें राष्ट्रमंडल खेलों के आयोजन का एक महत्वपूर्ण और प्रतिष्ठित अंग है राष्ट्रमंडल खेल गांव, जिसे विश्वस्तरीय बनाने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी गई है। खेल गांव का निर्माण यमुना नदी क्षेत्र में अक्षरधाम मंदिर के समीप किया गया। खेल गांव के आवासीय परिसर में 1,160 फ्लैट हैं, जिनमें 8,000 खिलाड़ियों और अधिकारियों के ठहरने की व्यवस्था की गई है। प्रयास यही है कि सभी निर्माण कार्य समय पर पूरे हों और दिल्ली में आयोजित यह प्रतिष्ठित खेल महोत्सव राष्ट्र की गरिमा के अनुरूप सुचारू रूप से आयोजित हो सके।

पदकों की दौड़

कड़ी प्रतिस्पर्धा और निरंतर आगे बढ़ने के प्रयासों से अंतरराष्ट्रीय खेल परिदृश्य अत्यंत परिवर्तनशील बना रहता है, ठीक वैसे ही जैसे शीयर सूचकांक में अप्रत्याशित उतार-चढ़ाव आते रहते हैं। कब किस देश, टीम या खिलाड़ी का किस खेल में कैसा प्रदर्शन रहेगा, इसका पूर्वानुमान करना जोखिमभरा ही होगा, कब कौन खिलाड़ी फार्म खो देता है, कौन चोटग्रस्त हो मैदान से बाहर हो जाता है, किस को स्थानीय परिस्थितियों और स्थानीय समर्थन का लाभ मिलता है, ऐसे अनेक पहलू हैं जिनका अंतिम परिणाम पर प्रभाव पड़ता है। अक्टूबर 2010 में होने वाले दिल्ली के उन्नीसवें राष्ट्रमंडल खेलों की पदकीय स्थिति के बारे में पूर्वानुमान करना भी संभवतः ऐसा ही जोखिमभरा प्रयास होगा। ऑस्ट्रेलिया की बहुआयामी क्षमता, अंतरराष्ट्रीय मुक्काबलों के लिए गंभीरता से तैयारी करने की ऑस्ट्रेलियाई प्रवृत्ति और ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों का स्वभावजन्य जुझारूपन कुछ ऐसे पहलू हैं जो दिल्ली राष्ट्रमंडल खेलों के लिए ऑस्ट्रेलिया की पदकीय चुनौती को सबसे प्रबल बनाते हैं। संभावना यही है कि दिल्ली खेलों की अंतिम पदक तालिका में एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया ही चोटी पर आसीन रहेगा। अन्य प्रतियोगी देशों की तुलना में इंग्लैंड की खेल सामर्थ्य अधिक सबल होने के कारण पदक तालिका में दूसरे स्थान पर उसका ही मुख्य दावा प्रतीत होता है। वर्ष 2002 के मैनचेस्टर और 2006 के मेलबोर्न खेलों में तीसरे स्थान के लिए मुख्य होड़ भारत और कनाडा के बीच थी, जिसमें अंततः बाजी कनाडा ने मारी, जिसकी तैराकी, ड्राइविंग,

जिम्नास्टिक्स, साइकिल चालन और एथलेटिक्स में भारत की खेल सामर्थ्य, नगण्य चुनौती की तुलना में कहीं विशाल और धारदार है।

भारत को निश्चय ही आतिथेय होने के कारण स्थानीय परिस्थितियों और स्थानीय दर्शक समर्थन का लाभ मिलेगा साथ ही पूर्ववर्ती खेलों की तुलना में भारतीय खिलाड़ी दल की तैयारी भी बेहतर होगी, जिससे दिल्ली राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का पदकीय प्रदर्शन अब तक का सर्वोत्तम रहने की संभावना है। अगर भारत के निशानेबाज मैनचेस्टर और मेलबोर्न खेलों के अपने प्रदर्शन की पुनरावृत्ति करते हैं, तो उनका पदक तालिका में तीसरा स्थान पाना निश्चित है। निशानेबाजी के अलावा भारत की परंपरागत शक्ति कुश्ती और भारोत्तोलन, विशेषकर महिलाओं की भारोत्तोलन में है। एक बार फिर राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल तीरंदाजी प्रतियोगिता से भी स्वर्णिम सफलता की आशा की जा सकती है। मुक्केबाजी, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, एथलेटिक्स और टेनिस से भी सीमित सफलता की उम्मीद की जा सकती है। पर तैराकी, जिम्नास्टिक्स, लॉन बोलस, नेटबाल, रग्बी सेवन, स्क्वैश और साइकिल चालन से पदकीय सफलता की अपेक्षा घोर आशावादिता होगी। इनमें सिर्फ स्क्वैश से ही कुछ उम्मीद की जा सकती है। पर दिलचस्प बात रहेगी हॉकी में भारतीय पुरुष टीम का प्रदर्शन। एक बार फिर प्रश्न उठेगा कि क्या भारतीय हॉकी की खोई अस्मिता की तलाश दिल्ली राष्ट्रमंडल खेलों में पूरी हो सकेगी?

राष्ट्रमंडल खेलों की चार प्रमुख शक्तियों— ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, मेज़बान भारत और कनाडा के अलावा दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड, स्कॉटलैंड भी अच्छे पदकीय प्रदर्शन की क्षमता रखते हैं। अफ्रीका और कैरिबियाई देशों की नैसर्गिक प्रतिभा एथलेटिक्स स्पर्धाओं में, विशेषकर दौड़ों में देखने को मिलेगी। एशियाई देशों में मलेशिया बैडमिंटन में और सिंगापुर टेबल टेनिस में श्रेष्ठ प्रदर्शन की क्षमता रखते हैं। संक्षेप में, दिल्ली के राष्ट्रमंडल खेल राष्ट्रमंडल की इंद्रधनुषी छवि को साकार करेंगे और इनमें मैत्री तथा सद्भावना के गहरे रंग भारत का परंपरागत आतिथ्य-सत्कार भरेगा। □

ज्ञानवान समाज का निर्माण

● शैलेन्द्र सिन्हा

झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं का साक्षरता स्तर काफी कम है। परंपरा से वे अपने घरों और खेतों तक सीमित रही हैं; उनकी दुनिया इन्हीं दायरों में बंधी हुई है। उन्होंने शायद ही कभी अपने दैनिक जीवन और स्थानीय विकास से जुड़े क्षेत्रों के बारे में सूचना के नये तरीके जानने की कोशिश की हो। कम-से-कम तब तक तो नहीं ही, जब तक 'सचल पुस्तकालय' मैदान में प्रकट नहीं हुए। यह पीएसीएस (सर्वाधिक निर्धन क्षेत्र का सभ्य समाज- पुअरेस्ट एरियाज़ सिविल सोसायटी) का एक प्रयास है, जो सामाजिक रूप से वंचित, विशेषकर महिलाओं के अधिकारों के बारे में जानकारी पहुंचाने के लिए भारत के 120 जिलों में गरीबी के कारणों के निराकरण के लिए काम कर रहा है। स्थानीय जोशीले लड़के महेशपुर विकास खंड (पाकुड़ जिला, झारखंड) के 30 गांवों में साइकिल से आते-जाते हैं। उनके साथ साइकिल में केवल पुस्तकें और अखबार ही नहीं होते बल्कि वृद्धावस्था पेंशन के आवेदन पत्र, मनरेगा और वनाधिकार पर सूचनाएं भी होती हैं जो वे गांव वालों को बांटते हैं। शुरू-शुरू में महिलाओं ने इन सामग्रियों में कोई रुचि नहीं दिखाई। संभवतः साक्षरता के अभाव के कारण उनको पता ही न था कि इनका उससे क्या संबंध हो सकता है। परंतु धीरे-धीरे इन युवाओं (पुस्तकालय कार्यकर्ताओं) ने उनसे बातचीत करनी शुरू की और अपनी सामग्री के बारे में जानकारी दी और यह भी

बताया कि इनसे उन्हें क्या लाभ हो सकता है। महिलाओं ने धीरे-धीरे आगे आना शुरू किया और अन्नपूर्णा योजना के बारे में जानने की उत्सुकता दिखाई। संभवतः उनके हृदय में सदा से ही यह इच्छा थी कि नया ज्ञान प्राप्त करें और नयी-नयी बातें सीखें ताकि उनका जीवन बेहतर हो सके। इन कार्यकर्ताओं की जरा-सी मदद से उनकी यह इच्छा सामने आ सकी। सचल पुस्तकालय ने तो केवल उसको थोड़ी हवा भर दी। बारकिटा गांव की स्टैन्सिला हेम्ब्रम का कहना है कि महिलाओं को अब सचल पुस्तकालय का महत्व समझ में आने लगा है। "हम उन्हें अपने अधिकारों के बारे में जागरूक बना रहे हैं, महिलाओं से संबंधित कानून, विशेषकर महिलाओं के विरुद्ध हिंसा रोकने का कानून, पंचायती राज प्रणाली और इसमें भागीदारी के बारे में समझा रहे हैं।"

शहर के वातावरण में रहने वाले लोगों के मन में गांव में पुस्तकालय की बात आसानी से गले नहीं उतरती। बावजूद इसके, झारखंड के इन्हीं ग्रामीण क्षेत्रों में सूचना प्रवाह की आवश्यकता है, क्योंकि ये गांव अभी भी स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन और आवास जैसे बुनियादी मुद्दों से जूझ रहे हैं। ऐसा नहीं हुआ तो ग्रामीण समुदाय, निर्धन, पिछड़े वर्गों के लोग और आदिवासी किस प्रकार मुख्यधारा से जुड़ पाएंगे और किस प्रकार वे विकास का फल चख पाएंगे और प्रगति की दौड़ में शामिल हो सकेंगे?

इस प्रकार के पुस्तकालयों से धीरे-धीरे गांवों में सूचनाओं का प्रसार हो रहा है। बजाय इसके कि लोग इस संस्था के पास आएँ, इसने स्वयं ही संस्था को लोगों के पास पहुंचाने की अग्रगामी भूमिका निभाई है। इसने सूचना की गूढ़ता को तोड़कर उन्हें इस तरह से प्रस्तुत किया है कि कोई निरक्षर भी उसे आसानी से समझकर अपना सकता है। पुस्तकालय का जो पारंपरिक स्वरूप और अर्थ है, उसे तोड़कर नया, सरल, सहज, सुलभ रूप दिया गया है। ऐसा करते समय इन सचल पुस्तकालयों ने उच्च आदर्श और सिद्धांत को सम्मान दिया है कि ज्ञान तो निःशुल्क है और इसको प्राप्त करने में वर्ग, धर्म, जाति, भाषा और लिंग का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। सथाल परगना के दुमका जिले की सिडो-कांतू मुर्मू विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. विक्रम तिग्गा कहते हैं, "सूचना का प्रवाह अति महत्वपूर्ण है, यह आम लोगों के विचार बदल देता है। तेजी से बदलती दुनिया में तमाम बातों को जानना बेहद जरूरी है। परंतु दुर्भाग्यवश, सूचना क्रांति से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को लाभ नहीं पहुंचा है।"

इस परियोजना की सफलता का श्रेय इसके सदस्यों के उत्साह को जाता है, जो ज़मीनी स्तर पर सकारात्मक परिवर्तन लाना चाहते हैं। माइकेल हेम्ब्रम का कहना है कि, 'मैं समाज के लिए कुछ करना चाहता हूँ। सचल पुस्तकालय का सदस्य होने के नाते मैं समाचार, सूचना और ज्ञान के वाहक का काम कर रहा हूँ। आज

ग्रामीण क्षेत्र जागरूक हो गया है। समाज के पिछड़ेपन से लड़ने का यही एक प्रभावी औजार है।”

शुभ समाचार यह है कि पिछड़ेपन और अल्प विकास के बावजूद ग्रामीण समुदायों में बेहतर बदलाव आता स्पष्ट दिख रहा है। कृषि, बाजार और रोजगार के बारे में जानने की उत्सुकता लोगों में बढ़ी है। यहां तक कि अपने गांवों से परे अन्य क्षेत्रों की घटनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने की इच्छा तीव्र हुई है। एक प्रकार से समग्र और स्थायी विकास की यही कुंजी है। एक ऐसा विकास जो समाज के भीतर से उद्भूत होता है, न कि ऊपर से थोपा हुआ। नागरिक समाज के अभाव में सरकारी कल्याण कार्यक्रम और विकास योजनाएं सिमटकर एक सीमित दायरे में ही रह जाएंगी। समाज जागरूक होगा तो स्वयं ही आगे बढ़कर उसका लाभ

उठाने का प्रयास करेगा। किसी भी योजना का बेहतर और प्रभावी लाभ तभी उठाया जा सकता है जब उसमें जमीनी स्तर से लोगों की भागीदारी हो। एक सामूहिक प्रयास के रूप में सचल पुस्तकालय इस भागीदारी को आगे बढ़ाने की दिशा में बेहतर योगदान दे सकते हैं। इससे सरकार और जनता के बीच गतिशील भागीदारी बन सकती है।

ग्रामीण परिदृश्य में इस तरह के प्रयासों की अनंत संभावनाएं हैं और यह शैक्षणिक रुचि अथवा पठन सामग्री के संग्रह से भी आगे बढ़कर सामाजिक परिवर्तन के लिए एक गतिशील माध्यम का रूप ले सकता है। यह एक दिशा की ओर संकेत करता है, जिसे उन एजेंसियों को हाथ में लेना चाहिए जो सरकारी और निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देने का काम कर रही हैं। उन्हें इस अवसर का लाभ उठाकर उसे आगे

बढ़ाना चाहिए जिसका रास्ता पीएसीएस की पहल से खुल गया है।

लंबे समय से प्रतीक्षित शिक्षा के अधिकार विधेयक के पारित होने से पढ़ना-लिखना प्रत्येक बच्चे का मौलिक अधिकार हो गया है। अज्ञान के अंधकार को नष्ट करने में पुस्तकालय अथवा सचल पुस्तकालय, पूरे ग्रामीण भारत में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। साक्षरों की नयी पीढ़ी के ज्ञानवर्धन के लिए ये पुस्तकालय सूचना और ज्ञान के उपयोगी माध्यम बन सकते हैं। इससे निश्चय ही उनका सशक्तीकरण हो सकेगा। हमारे लिए ऐसे समाज के स्वप्न को साकार करने का समय आ गया है जिसमें मन में कोई भय न हो— गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर ने कुछ इसी तरह की संकल्पना की थी। □

(चरखा फीचर्स)

राष्ट्रमंडल खेलों में भारत : पदक तालिका

वर्ष	खेलों का क्रम	स्थान	स्वर्ण	रजत	कांस्य	कुल पदक	पदक तालिका में स्थान
1930	प्रथम	हैमिल्टन (कनाडा)	-भारत ने भाग नहीं लिया	-	-	-	-
1934	दूसरे	लंदन (इंग्लैंड)	0	0	1	1	-
1938	तीसरे	सिडनी (ऑस्ट्रेलिया)	0	0	0	0	-
1950	चौथे	ऑकलैंड (न्यूजीलैंड)	-भारत ने भाग नहीं लिया	-	-	-	-
1954	पांचवें	वैनकूवर (कनाडा)	0	0	0	0	-
1958	छठे	कार्डिफ (वेल्स)	2	1	0	3	आठवां
1962	सातवें	पर्थ (ऑस्ट्रेलिया)	-भारत ने भाग नहीं लिया	-	-	-	-
1966	आठवें	किंग्सटन (जमैका)	3	4	3	10	नौवां
1970	नौवें	एडिनबरा (स्कॉटलैंड)	5	3	4	12	छठा
1974	दसवें	क्राइस्टचर्च (न्यूजीलैंड)	4	8	3	15	छठा
1978	ग्यारहवें	एडमंटन (कनाडा)	5	4	6	15	छठा
1982	बारहवें	ब्रिस्बेन (ऑस्ट्रेलिया)	5	8	3	16	छठा
1986	तेरहवें	एडिनबरा (स्कॉटलैंड)	-भारत ने भाग नहीं लिया	-	-	-	-
1990	चौदहवें	ऑकलैंड (न्यूजीलैंड)	13	8	11	32	पांचवां
1994	पन्द्रहवें	विक्टोरिया (कनाडा)	6	11	7	24	छठा
1998	सोलहवें	कुआलालम्पुर (मलेशिया)	7	10	8	25	सातवां
2002	सत्रहवें	मैनचेस्टर (इंग्लैंड)	30	21	18	69	चौथा
2006	अठारहवें	मेलबोर्न (ऑस्ट्रेलिया)	22	17	11	50	चौथा
अब तक कुल पदक			102	95	75	272	

स्वर्ग में संकट

पिछले महीने 6 अगस्त की आधी रात को, जम्मू-कश्मीर के लद्दाख जिले में ऊंचाई पर स्थित लेह क्षेत्र में अचानक बादल फट पड़े फलस्वरूप दो-ढाई घंटे तक मूसलाधार वर्षा हुई। इसके कारण जो बाढ़ आई उसने लेह और आस-पास के गांवों में भारी तबाही मचाई। अनेक ज़िंदगियों को लील लिया और अनेक आशियानों का उजाड़ दिया। अधिकृत सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार अब तक लगभग 175 लोग मारे जा चुके हैं। इनमें 25 के करीब विदेशी हैं, जो पर्यटन के सिलसिले में लेह आए हुए थे। इसके अलावा करीब 500 लोग लापता हैं। मृतकों में अनेक बच्चे भी हैं।

इस आपदा ने निजी तथा सार्वजनिक संपत्ति को बड़े स्तर पर नुकसान पहुंचाया है। सड़क संपर्क टूट जाने से लोगों को भोजन, पीने के पानी, दवाइयों की कमी की समस्या से भी जूझना पड़ रहा है। ठप हुई संचार व्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने के लिए सरकारी और गैर-सरकारी संस्थाएं लगातार काम में जुटी हुई

हैं। पर्यटन को गहरा धक्का लगा है। पर्यटन के अलावा यहां की मुख्य आर्थिक गतिविधि पशुपालन है। बाढ़ में भारी संख्या में पशुओं के मारे जाने से यह क्षेत्र भी तबाह हो गया है। कारगिल में हुए 1999 के युद्ध के बाद लेह में बादल फटना इस क्षेत्र की सबसे दुर्भाग्यपूर्ण घटना है।

सदियों से लेह सिंधु घाटी के व्यापार मार्ग का एक महत्वपूर्ण पड़ाव रहा है। प्राचीन शहर लेह को विश्व स्मारक की 100 सर्वाधिक लुप्तप्राय स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। अत्यधिक वर्षा और जलवायु परिवर्तन के अन्य प्रभावों के कारण लेह का अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया है। शहर का पुराना भाग बसाहट के तौर-तरीकों में बदलाव और उपेक्षा का शिकार भी रहा है। लेह की जलवायु एक शीतल मरुस्थली जैसी है जहां शीतकालीन ऋतु लंबी और बड़ी निर्मम होती है और तापमान आमतौर पर हिमांक से काफ़ी नीचे रहता है। बाकी महीनों में मौसम आमतौर पर सुहावना रहता है। गत अगस्त 8 को

आई अचानक बाढ़ से यहां जान-माल को भारी क्षति पहुंची है।

हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं में बसे लेह तक सड़क मार्ग से दो रास्तों से पहुंचा जा सकता है। कश्मीर की ओर से जोजी ला और मनाली की ओर से यहां रोहतांग और तंगलन दर्रा से होकर पहुंचा जा सकता है। लद्दाख का यह नाम इन्हीं दर्रा के नाम पर पड़ा। 'ला' अर्थात् 'दर्रा' और दख का अर्थ है संबंधित। ये पहाड़ी दर्रे व्यापार मार्गों के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं और प्राचीन समय में तिज्जारीतों काफ़िले इन्हीं दर्रा से होकर आया-जाया करते थे। जून के आरंभ से लेकर अगस्त के अंत तक के समय को छोड़कर साल के बाकी दिनों में यह क्षेत्र अन्य क्षेत्रों से कट जाता है। नदियां और झीलें जम जाती हैं। जाड़ों में तापमान -20°C तक गिर सकता है।

लेह लद्दाख का मुख्य नगर है। पर्यटकों, विशेषकर अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों से भरा यह शहर

हिमालय पर्वत का विहंगम दृश्य प्रस्तुत करता है। ओल्ड फोर्ट रोड जैसे बाजार और विक्रय केंद्र में व्यापारिक कारोबार जोर-शोर से चलता है। विक्रेता नग-नगीने और ऊनी कपड़े बेचते नजर आते हैं। रेस्तराओं में जायकेदार 'धूपका', 'मोमो' और 'गुर गुर' चाय पेश की जाती है।

लेह उत्तर की ओर तिब्बत से लगा हुआ है, इसलिए तिब्बती संस्कृति की झलक यहां स्पष्ट दिखाई देती है। किसी लद्दाखी के घर पर रहने अथवा अतिथि गृह में रहने पर जैसे ही आप परिवार के लोगों से घुलना-मिलना शुरू करेंगे, आपको उनकी संस्कृति का आभास होने लगेगा। अतिथि गृह आपको प्राचीन सिल्क रूट पर सुदूर स्थित डेसक्रेट जैसे स्थान पर मिल जाएंगे। पास के हंडर में पाए जाने वाले दो कूबड़ वाले बैक्ट्रियन ऊंट इस क्षेत्र का विशेष आकर्षण हैं।

गर्म झरने और महल

प्रसिद्ध खार्दुंग-ला को पार करने के बाद हंडर पहुंचा जा सकता है, जहां सफेद रेत आपका स्वागत करने को तैयार मिलेगी। लगभग 18,300 फीट की ऊंचाई पर बना यह दर्रा विश्व में सबसे अधिक ऊंचाई पर बना मोटर यातायात योग्य सड़क है। यहां सेना के अधिकारी आपका स्वागत हर्बल चाय से करते हैं ताकि आप ऊंचाइयों पर होने वाली बीमारियों से बच सकें। पनामिक में गर्म झरने हैं और संयोगवश सिल्क रूट का यह अंतिम गांव है। सिंधु और जंस्कार नाम की दो शानदार नदियां, लेह में प्रवेश के पहले थोड़ा ऊपर आपस में आकर मिलती हैं और यही नदी आगे जाकर सिंधु नदी के रूप में पाकिस्तान में प्रवेश करती है।

ट्रेकिंग और रैफ्टिंग की गतिविधियों के अलावा शीतकाल में जमी हुई नदियों पर चलना भी यहां

का एक दुस्साहसभरा खेल है। इन गतिविधियों के अलावा लद्दाख बौद्ध धर्म के वज्रयान मतानुयायियों का तीर्थ है। भगवान बुद्ध की प्रतिमा यहां देखने योग्य है। हेमिस, स्पितुक और माथो के भव्य बौद्ध मठ अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं। इन्हें स्थानीय भाषा में 'थंगका' पेंटिंग्स कहा जाता है। इस क्षेत्र के प्राचीन शासकों द्वारा निर्मित 'शे' जैसे महल समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं और तत्कालीन पारंपरिक वास्तुशिल्प की झलक दिखाते हैं। ग्रीष्म ऋतु में यहां के पोलो और तीरंदाजी मुक्काबले काफ़ी लोकप्रिय हैं। यह 17वीं शताब्दी के नामग्याल शासकों की धरोहर है।

प्रकृति प्रेमियों के लिए पांगोंग त्यों झील से बड़ा कोई आकर्षण नहीं। चंद्रमा जैसी स्थलाकृति में एक नीली बूंद जैसी यह झील भारत-चीन सीमा पर 14 हजार फीट की ऊंचाई पर स्थित है। दिन के विभिन्न चरणों में इसके पानी का रंग सिलेटी से नीला और फिर हल्के बैंगनी रंग में बदलता हुआ-सा दिखता है। दरअसल पास की चांग चैनमों और पांगोंग पर्वत श्रृणियों की छाया जैसे-जैसे झील में उतरती जाती है, उसका रंग बदला-बदला दिखने लगता है।

लेह का यह क्षेत्र अपने जीव-जंतुओं के लिए भी प्रकृति प्रेमियों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। गंजे सिर वाली ब्राह्मिणी बत्तख और भूरी दुम वाली समुद्री पक्षी (गल) के अलावा याक को देखने के लिए भी सैलानी यहां आते रहते हैं। पशमीना ऊन देने वाली भेड़ें भी यहां की विशेषता है।

लेह में बादल फटा

यह एक ऊंचाई वाला रेगिस्तान है, अतः यहां शायद ही कभी वर्षा होती हो। यहां सालभर

में मुश्किल से पांच इंच की बरसात होती है और वह भी बर्फ़ के रूप में। अतः जब पिछले महीने अगस्त के पहले सप्ताह में यहां मूसलाधार वर्षा हुई तो लोगों के लिए यह आश्चर्य की बात थी। करीब दो घंटे तक लेह में बादल फटने से जो बारिश हुई उसने जमकर तबाही मचाई। खूबसूरत शहर लेह कीचड़ और मलबे के ढेर में बदल गया है। बादल फटने की घटना आधी रात के आसपास हुई और फलस्वरूप हुई हाहाकारी वर्षा ने अस्पताल, बस अड्डा, रेडियो स्टेशन का ट्रांसमीटर, टेलीफोन एक्सचेंज, मोबाइल फोन टावर और हवाईअड्डे, सब कुछ तबाह कर दिया। परंतु ऐसा लगता है कि यह तबाही शायद होने को ही थी। कहते हैं कि पिछले वर्ष भी यहां बर्फ़ से ज्यादा पानी गिरा। यह एक समस्या थी, क्योंकि यह क्षेत्र सिंचाई के लिए पिघले हुए पानी पर निर्भर करता है।

क्या यह वैश्विक तपन का प्रतिफल है? या फिर, जैसाकि न्यूयार्क टाइम्स के स्तंभकार और पुलित्ज़र पुरस्कार विजेता लेखक टॉमस फ्रीडमैन कहते हैं, वैश्विक अनोखेपन का नमूना है, जहां मौसम में अजीबोगरीब परिवर्तन होते हैं और वह अनिश्चित होता जाता है। रूस, कनाडा, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसी अजीबोगरीब बेमौसमी मार पड़ चुकी है। चूंकि लेह में बारिश नहीं के बराबर होती है, वहां अधिकतर मकान कच्ची मिट्टी के बने हैं। इसलिए नुकसान भी ज्यादा हुआ। शहर के पुननिर्माण में लंबा वक्त लगेगा।

प्रधानमंत्री ने लेह में बादल फटने की घटना के शिकार लोगों के लिए एक अरब 25 करोड़ रुपये के राहत पैकेज की घोषणा की है। डॉक्टर मनमोहन सिंह राहत और पुनर्वास कार्यों का जायजा लेने सत्रह अगस्त को लेह के दौरे पर गए थे। उन्होंने कहा कि अचानक आई भीषण बाढ़ से नष्ट हुए मकान ढाई महीनों में बना दिए जाएंगे।

बाढ़ की सबसे अधिक चपेट में आए गांव चोगलामसर के लोगों को प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया कि उनकी मदद के लिए धन की कमी नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि केंद्र और जम्मू-कश्मीर सरकार पीड़ित परिवारों की मदद के लिए हर संभव उपाय करेंगी।

प्रधानमंत्री ने कहा कि विभिन्न योजनाओं को कारगर तरीके से लागू करने के लिए राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक निगरानी समिति बनाई जाएगी। चोगलामसर के एक राहत शिविर में उन्होंने कहा कि वे सर्दियों से पहले फिर एक बार लेह आएंगे। □



विकलांगों के लिए जुगाड़ वाली कार

जनवरी 1974 में जन्मे मुजीब खान, जयपुर में रहते हैं और पेशे से मोटर मैकेनिक (मिस्त्री) हैं। बचपन में पोलियो के हमले से उनके नीचे के अंग कमजोर हो गए और आंशिक रूप से ही काम करते हैं। स्वयं विकलांग होने के कारण वे चलने-फिरने की उन सभी समस्याओं से रू-ब-रू हुए हैं, जो किसी विकलांग व्यक्ति के जीवन में आती हैं। उन्होंने किसी भी कार में कुछ अतिरिक्त कलपुर्जे लगाकर उसे विकलांगों के उपयोग के अनुकूल बनाने की तकनीक विकसित की है।

मुजीब का बचपन विकलांगता के कारण बड़ी मुश्किलों में गुजरा। परंतु वे हार मानकर घर में बैठने वाले इंसान नहीं थे। 1990 के दशक में उन्होंने आर्डर पर चादरें बनाने और निर्यातकों को बेचने का कारोबार शुरू किया। परंतु जब निर्यात का बाजार ठंडा पड़ने लगा और निर्माण में प्रयोग होने वाले कुछ रंगों के बारे में आपत्तियां उठाई जाने लगीं, उन्हें अपना यह काम बंद कर दूसरा पेशा अपनाना पड़ा। मशीनों में उनकी गहरी दिलचस्पी थी, इसलिए उन्होंने स्कूटर और मोटरसाइकिल की मरम्मत की वर्कशॉप खोली। 5' x 5' की इस छोटी-सी दुकान में वे दो पहिया वाहनों की मरम्मत से जुड़े सभी काम खुद किया करते थे।

अपनी इसी छोटी-सी दुकाननुमा वर्कशॉप में तमाम कोशिशों के बाद उन्होंने हाथ से चलाई जाने वाली कार का विकास किया और विकलांग व्यक्तियों को स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बनने का रास्ता दिखाया। इस घटना ने मुजीब को हीरो बना दिया और वे अपने क्षेत्र के युवाओं के आदर्श

बन गए। लोग जब मुजीब को अपनी कार से बैसाखियों के साथ उतरते देखते, तो उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता था। कोई अपंग व्यक्ति मुख्य राजमार्ग पर कार चलाता है, वे यह बात आसानी से सोच नहीं पाते थे।

उत्पत्ति

मुजीब के घर में एक मारुति कार थी, जो उनके पिता और भाई चलाया करते थे। मुजीब को इस बात को लेकर बहुत अफ़सोस होता था कि अपनी विकलांगता के कारण वे कार नहीं चला पाते थे। परिवार वालों की नज़रें बचाकर उन्होंने चुपचाप कार पर अपना काम शुरू किया। शुरुआती प्रयोगों के बाद उन्होंने कार में

एक छड़ (रॉड) लगाई ताकि वे ब्रेक लगा सकें और ऐक्सीलरेटर दबा/छोड़ सकें। माता-पिता की अनुपस्थिति में उन्होंने एक दिन कार भी चलाई।

कार में अपनी जुगाड़ (संशोधन) करने के बाद, उन्होंने धीरे-धीरे कार चलाना सीखना शुरू किया। करीब दो महीने के अभ्यास के बाद वे कार चलाने में पारंगत हो गए। किसी भी स्तर पर किसी ने उनकी मदद नहीं की और अपने आप ही उन्होंने यह सब सीखा। तब वे अपनी गाड़ी अपनी वर्कशॉप में ले गए ताकि उसमें एक ऐसी प्रणाली लगाई जा सके जिससे सामान्य और संशोधित ढंग, दोनों प्रकार से गाड़ी चलाने में सुविधा हो।





उन्होंने इस पर 6 महीनों तक काम किया। इसके बाद भी कार में जो सुधार किए गए थे, वे कुछ अटपटे से लग रहे थे। गाड़ी के डैशबोर्ड और नियंत्रण प्रणाली से उसका सामंजस्य ठीक से नहीं बैठा था। परंतु धीरे-धीरे लोग उनके प्रयासों को समझने और स्वीकार करने लगे थे। विकास की प्रक्रिया जारी रही और उन्होंने उस अतिरिक्त पुर्जों का वाणिज्यिक उत्पादन शुरू कर दिया। दर्जनों कारों में सुधार करने के बाद अंततः वे ऐसा जुगाड़ (रिट्रोफिट) तैयार करने में सफल हो गए जो कार के इंटीरियर (आंतरिक बनावट और रूप-रंग) से पूरी तरह से मेल खा रहा था।

उन्होंने मारुति 800, महिन्द्रा स्कोर्पियो आदि कारों में सुधार कर उन्हें निचले अंगों से विवश लोगों के उपयोग के अनुकूल बनाने में सफलता प्राप्त की। गाड़ियों के ब्रेक्स, क्लच और ऐक्सीलरेटर में बदलाव किए गए। ये सब बदलाव इस प्रकार किए गए थे कि उन्हें हाथों से भी चलाया जा सकता था। एक पैर वाले व्यक्ति के लिए वाहन में क्लच तो अपनी मूल स्थिति में ही थे, जबकि नये बदलावों के अनुसार नियंत्रण की अन्य प्रणालियों का संचालन हाथों से किया जा सकता था। ये बदलाव इस प्रकार किए गए थे कि सामान्य व्यक्ति इन कारों का इस्तेमाल पारंपरिक ढंग से कर सकते थे।

नवाचार

कारों में जो नया बदलाव किया गया है, वह मुख्य रूप से ऐक्सीलरेटर, ब्रेक और क्लच को हाथ से चलाने के लिए किया गया है। इसकी नियंत्रण प्रणाली ऐसी रखी गई है कि गाड़ी को चलाने में कोई समस्या नहीं आए और चालक को आराम मिले। विकलांगों के लिए उपयुक्त कारों में संशोधन के बारे में साहित्य प्रौद्योगिकी में उल्लेख मिलता है। इनमें से अधिकांश में, ब्रेक और ऐक्सीलरेटर के पैडलों के संचालन के

लिए दूरबीनी यांत्रिकी संख्याएं दी हुई हैं। मुजीब ने हस्तचालित नियंत्रण प्रणाली के लिए समानांतर प्रणाली का इस्तेमाल किया है, इससे सुरक्षा में वृद्धि हुई है। कार्य करने का सिद्धांत गाड़ी चलाने के तरीके में बदलाव पर आधारित है ताकि लीवरों, तारों और संपर्क यांत्रिकी (लिंकेज मेकेनिज्म) के उपयोग से नियंत्रण के सूत्र हाथों में आ सकें। ब्रेक पैडल को या तो यांत्रिकी व्यवस्था से सक्रिय किया गया है या फिर एक अतिरिक्त हाइड्रॉलिक सिलिंडर लगाकर उसे लगाया जाता है। डैशबोर्ड में एक ऐसा स्विच लगाया गया है जिसको दबाने और खींचने से ऐक्सीलरेटर सक्रिय हो जाता है। इसके लिए उसको एक तार के जरिये इंजन से जोड़ा गया है। क्लच के तार को अर्द्ध वृत्ताकार स्टीयरिंग से जोड़ा गया है जोकि स्टीयरिंग एसंबली के जरिये क्लच-प्लेट से जुड़ा हुआ है।

फिलहाल, यह डिजाइन स्कोर्पियो और मारुति में अपनाई गई है। अन्य वाहनों में इस्तेमाल के लिए उसका मानकीकरण करना होगा। मुजीब चाहते हैं कि इस किट में इस प्रकार बदलाव किए जाएं कि वह एक हाथ और एक पैर से अपंग व्यक्ति के भी काम आ सके और उसकी लागत भी कम हो सके।

यह किट इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि अनेक कार निर्माता कंपनियों ने विकलांग व्यक्तियों के लिए पहले जो विशेष उपकरण बनाए थे, वे बहुत महंगे थे और अब उनका उत्पादन भी बंद हो गया है।

मुजीब एक समय में एक ही कार पर काम करते हैं और इसमें उन्हें 3-4 दिन का समय लगता है। यह उपकरण मूल मॉडल की किस्म पर निर्भर करता है। मारुति 800 में लगाने वाले किट का मूल्य करीब 10,000 रुपये है जबकि होंडा सिटी कार के लिए उसी प्रकार के किट का

मूल्य 15,000 से 20,000 के बीच है। उन्होंने अपना पहला किट 1995 में जयपुर के एसएसएस अस्पताल के चंद्रपाल सिंह के लिए बनाया था, जो उनके इस कार्य से बहुत प्रसन्न हुए और 15-20 अन्य कारों में बदलाव के आर्डर दिलाने में उनकी मदद की और अब करीब 70-80 कारों में बदलाव करने के बाद उनकी किट प्रायः सभी प्रकार के कारों में इस प्रकार फिट होने लगी है जैसी कि वह उसी कार की आंतरिक साज-सज्जा (इंटीरियर) का ही हिस्सा हो। विकलांग वाहन चालकों के लिए वरदान साबित हुई है।

नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन (एनआईएफ) ने इस जैसे और भी अन्य कई उपयोगी आविष्कारों के विवरण दर्ज किए हैं। नवाचार कर्ता कारीगरों के काम में हनी-बी नेटवर्क के स्वयंसेवक ने मदद करते हैं। एनआईएफ ऐसे आविष्कारों को मान्यता देता है और प्रोत्साहित करता है। वह उत्पाद विकास, पेटेंट लेने और व्यापार विकास में भी सहायता करता है और परंपरागत ज्ञान को बढ़ावा देता है। अपनी सातवीं द्विवार्षिक राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के लिए एनआईएफ ने गत वर्ष किसानों, छात्रों, कारीगरों, मिस्त्रियों, मछुआरों, महिलाओं, जड़ी-बूटी के जानकारों और अन्य जमीनी कार्यकर्ताओं से प्रविष्टियां आमंत्रित की थी एनआईएफ को आप पोस्ट बाक्स नं. 15051 अंबावाड़ी, अहमदाबाद-380015 पर या फिर ई-मेल campaign@nifindia.org पर संपर्क कर सकते हैं। पाठक अब तक प्रस्तुत नवाचारों के विवरण www.nifindia.org पर देख सकते हैं।

जो लोग इस ज़मीनी नवाचारी आंदोलन के अंग बनना चाहें वे एनआईएफ से संपर्क कर सकते हैं। ऐसा करते हुए वे भारत को सतत विकास की टेक्नोलॉजी में अग्रणी बनाने में योगदान करेंगे। □

हिंदी के प्रसार में मीडिया की भूमिका

● सुभाष सेतिया

अज से 60 वर्ष पूर्व 14 सितंबर, 1949 को देवनागरी में लिखी जाने वाली हिंदी को भारत की राजभाषा स्वीकार किया गया था। इसलिए हर वर्ष 14 सितंबर का दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह तो नहीं कहा जा सकता कि हिंदी दिवस पर होने वाले भव्य और खर्चीले आयोजनों तथा राजभाषा कानून लागू किए जाने के बावजूद हिंदी सचमुच केंद्र की राजभाषा बन गई है किंतु यह तथ्य आज सभी स्वीकार करते हैं कि हिंदी अब व्यावहारिक तौर पर इस देश की संपर्क भाषा बन चुकी है। अब तो भारत के साथ संपर्क रखने के लिए हिंदी की अनिवार्यता विदेशी सरकारें भी महसूस कर रही हैं। इसलिए अमरीका, चीन, यूरोप तथा अन्य प्रमुख देशों में हिंदी के अध्ययन की व्यवस्था की जाने लगी है। विदेशों से बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं केंद्रीय हिंदी संस्थान, विभिन्न विश्वविद्यालयों और अन्य शिक्षण संस्थाओं में हिंदी पढ़ने के लिए आते हैं। हाल में आम चुनाव के बाद नयी सरकार के मंत्रियों ने शपथ ली तो पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्य मेघालय से निर्वाचित सबसे कम उम्र की मंत्री सुश्री अगाथा संगमा ने हिंदी में शपथ लेने में गौरव महसूस किया। उनके इस निर्णय पर शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद अन्य मंत्रियों व नेताओं ने भी तालियां बजाकर अपना समर्थन व्यक्त किया। मेघालय वह राज्य है जिसने अंग्रेजी को अपनी राजभाषा घोषित किया था। वर्ष 1960 और 1970 के दशकों में दक्षिण के जिन राज्यों में हिंदी के विरुद्ध आंदोलन चले थे, अब उन राज्यों के नेता हिंदी में बोलने को आतुर दिखाई देते हैं। इसके अलावा विभिन्न विश्वविद्यालयों में हिंदी विषय को लेकर बीए-एमए, करने वाले बच्चों की संख्या भी बढ़ती जा रही है।

उद्योग और व्यापार के क्षेत्र में, जहां भारतीय भाषाओं के प्रयोग की पूर्ण उपेक्षा की जाती थी, अब हिंदी सम्मानजनक स्थान प्राप्त कर रही है। रेडियो, टीवी तथा पत्र-पत्रिकाओं में हिंदी में विज्ञापन देने की होड़ लगी रहती है। इन तथ्यों को देखते हुए कहा जा सकता है कि हिंदी को

देशव्यापी स्वीकार्यता मिल चुकी है और वह समय दूर नहीं जब हिंदी पूर्ण रूप से भारत की एकमात्र संपर्क भाषा बन जाएगी।

हम सब जानते हैं कि भारत की संपर्क भाषा और राजभाषा के रूप में हिंदी के विकास की प्रक्रिया सविधान बनने से बहुत पहले स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ही शुरू हो चुकी थी। सच तो यह है कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की पहल हिंदी भाषी नेताओं ने नहीं बल्कि महात्मा गांधी, रवींद्रनाथ टैगोर, राजगोपालाचारी और नेताजी सुभाषचंद्र बोस सरीखे गैर-हिंदी भाषी लोगों की ओर से की गई। महात्मा गांधी देशभर में अपने भाषण हिंदी या हिंदुस्तानी में ही दिया करते थे। सुभाषचंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की तो विभिन्न राज्यों के सैनिकों को जोड़ने का काम हिंदी के माध्यम से ही किया। गांधीजी ने आज़ादी से पहले ही विभिन्न अहिंदी भाषी राज्यों,

14 सितंबर, हिंदी दिवस पर विशेष

विशेषकर दक्षिण भारत में हिंदी प्रचारिणी सभाएं बनाईं। इन सभाओं के माध्यम से हज़ारों हिंदीसेवी तैयार हुए जो देशभक्ति की भावना से हिंदी का प्रचार-प्रसार और शिक्षण करते थे। किंतु आज के संदर्भ में देखें तो हिंदी के प्रचार-प्रसार और इसे देशव्यापी स्वीकार्यता दिलाने में सबसे अधिक योग मीडिया यानी पत्र-पत्रिकाएं और रेडियो-टेलीविज़न का रहा है।

एक समय था जब पढ़े-लिखे होने का मतलब था अंग्रेजी भाषा का ज्ञान होना। इसलिए आज़ादी के समय सभी बड़े या तथाकथित राष्ट्रीय समाचार पत्र अंग्रेजी में ही छपते थे। किंतु शिक्षा और साक्षरता के प्रसार की दिशा में किए गए प्रयासों के फलस्वरूप यह अवधारणा बदलने लगी तथा हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के अख़बार पढ़ने वाले लोगों की संख्या में इज़ाफ़ा होने लगा। यह प्रक्रिया दुतरफ़ा चली। एक ओर जहां साक्षरता दर बढ़ने से हिंदी पत्र-पत्रिकाएं पढ़ने के इच्छुक लोगों की संख्या में वृद्धि हुई, वहीं हिंदी अख़बारों की प्रसार संख्या बढ़ने से

हिंदी के बोलचाल और प्रयोग में बढ़ोतरी हुई। हिंदी अख़बारों ने नये-नये प्रयोग किए और समाचार को औपचारिकता और स्टीरियोटाइप के घेरे से निकालकर उसे स्थानीय रंगत तथा रोचकता प्रदान की। ज़िला स्तर के विशेष संस्करण निकलने से अख़बार पढ़ना केवल उच्च शिक्षित वर्ग ही नहीं बल्कि मामूली पढ़े-लिखे लोगों का भी शौक बन गया। आज हालत यह है कि आम लोगों के एकत्र होने के किसी भी स्थान पर अंग्रेजी अख़बार गायब हो गए हैं और ऐसे हर स्थान या केंद्र पर हिंदी अख़बार ही पढ़ने को मिलते हैं। यही बात पत्रिकाओं के बारे में कही जा सकती है। अंग्रेजी की सभी प्रमुख समाचार पत्रिकाएं अपने हिंदी संस्करण भी निकाल रही हैं जो काफ़ी लोकप्रिय हुई हैं। इसके अलावा हल्की-फुल्की सामग्री देने वाली हिंदी की पत्रिकाओं की भरमार है और इनमें कुछ पत्रिकाएं तो लाखों की संख्या में छपती हैं। भले ही गंभीर विषयों पर हिंदी पत्रिकाएं कम निकलती हैं, किंतु सामान्य ज्ञान, फ़िल्म, फ़ैशन, स्वास्थ्य, साहित्य, पर्यटन, विज्ञान, कथा-कहानियां जैसे विषयों पर बहुत अच्छी पत्रिकाएं हिंदी में निकलती हैं और खूब पढ़ी जाती हैं। बच्चों और महिलाओं की हिंदी पत्रिकाएं विशेष रूप से लोकप्रिय हैं। जाहिर है कि ये सभी पत्र-पत्रिकाएं बिना शोर मचाए हिंदी भाषा को गांव-गांव तक लोकप्रिय बना रही हैं।

राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हिंदी को सर्वस्वीकार्य बनाने में रेडियो की उल्लेखनीय भूमिका रही है। आकाशवाणी ने समाचार, विचार, शिक्षा, सामाजिक सरोकारों, संगीत, मनोरंजन आदि सभी स्तरों पर अपने प्रसारण के माध्यम से हिंदी को देश के कोने-कोने तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण योगदान किया है। इसमें हिंदी फ़िल्में और फ़िल्मी गीतों का विशेष स्थान रहा है। हिंदी फ़िल्मी गीतों की लोकप्रियता भारत की सीमाओं को पार कर रूस, चीन और यूरोप तक जा पहुंची। आकाशवाणी की विविध भारती सेवा तथा अन्य कार्यक्रमों के अंतर्गत प्रसारित फ़िल्मी

गानों ने हिंदी को देशभर के लोगों की ज़बान पर ला दिया। हिंदी को देशव्यापी मान्यता दिलाने में फ़िल्मों की भी महती भूमिका रही है किंतु फ़िल्मों से अधिक लोकप्रिय उनके गीत रहे हैं जिन्हें जन-जन तक पहुंचाने का काम आकाशवाणी ने किया। अब वही काम निज़ी एफएम चैनल कर रहे हैं। एफएम चैनल हल्के-फुल्के कार्यक्रमों, वाद-संवाद और हास्य-प्रहसन के जरिये हिंदी का प्रसार कर रहे हैं। इस समय आकाशवाणी के 225 केंद्रों और 361 ट्रांसमीटरों के साथ-साथ लगभग 400 एफएम और सामुदायिक रेडियो चैनल प्रसारण कर रहे हैं। इनमें अधिकतर चैनल हिंदी में कार्यक्रम प्रसारित करते हैं। रेडियो प्रसारण में हिंदी के महत्व को इसी प्रकरण से समझा जा सकता है कि मुंबई में जब एफएम स्टेशनों के लाइसेंस दिए गए तो पहले आधे स्टेशन अंग्रेज़ी प्रसारण के लिए निर्धारित थे किंतु कुछ ही महीनों में वे भी हिंदी में प्रसारण करने लगे क्योंकि अंग्रेज़ी श्रोता बहुत कम थे। मनोरंजन के अलावा आकाशवाणी के समाचार, खेल कार्यक्रम, प्रमुख खेल प्रतियोगिताओं का आंखों देखा हाल तथा किसानों, मज़दूरों और बाल व महिला कार्यक्रमों ने हिंदी की स्वीकार्यता बढ़ाने में बहुत बड़ा योग दिया है और आज भी दे रहे हैं।

मीडिया का सबसे मुखर, प्रभावशाली और आकर्षक माध्यम टेलीविज़न माना जाता है। टेलीविज़न श्रव्य के साथ-साथ दृश्य भी दिखाता है इसलिए यह अधिक रोचक है। भारत में अपने आरंभ के लगभग 30 वर्ष तक टेलीविज़न की प्रगति धीमी रही किंतु वर्ष 1980 से 1990 के दशक में दूरदर्शन ने राष्ट्रीय कार्यक्रम और समाचारों के प्रसारण के जरिये हिंदी को जनप्रिय बनाने में काफ़ी योगदान किया। वर्ष 1990 के दशक में मनोरंजन और समाचार के निज़ी उपग्रह चैनलों के पदार्पण के उपरांत यह प्रक्रिया और तेज़ हो गई। रेडियो की तरह टेलीविज़न ने भी मनोरंजन कार्यक्रमों में फ़िल्मों का भरपूर उपयोग किया और फ़ीचर फ़िल्मों, वृत्तचित्रों तथा फ़िल्मी गीतों के प्रसारण से हिंदी भाषा को देश के कोने-कोने तक पहुंचाने के सिलसिले को आगे बढ़ाया। टेलीविज़न पर प्रसारित धारावाहिक ने दर्शकों में अपना विशेष स्थान बना लिया। सामाजिक, पौराणिक, ऐतिहासिक, पारिवारिक तथा धार्मिक विषयों को लेकर बनाए गए हिंदी धारावाहिक घर-घर में देखे जाने लगे। रामायण, महाभारत, हमलोग, भारत एक खोज जैसे धारावाहिक न केवल हिंदी प्रसार के वाहक बने बल्कि राष्ट्रीय

एकता के सूत्र बन गए। देखते-ही-देखते टीवी कार्यक्रमों से जुड़े लोग फ़िल्मी सितारों की तरह चर्चित और विख्यात हो गए। समूचे देश में टेलीविज़न कार्यक्रमों की लोकप्रियता की बंदौलत देश के विभिन्न भागों के अहिंदी भाषी लोग हिंदी समझने और बोलने लगे।

‘कौन बनेगा करोड़पति’ जैसे कार्यक्रमों ने लगभग पूरे देश को टेलीविज़न से बांधे रखा। हिंदी में प्रसारित ऐसे कार्यक्रमों में पूर्वोत्तर राज्यों, जम्मू-कश्मीर और दक्षिणी राज्यों के प्रतियोगियों ने भी बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया और इस तथ्य को दृढ़ता से उजागर किया कि हिंदी की पहुंच समूचे देश में है। विभिन्न चैनलों द्वारा अलग-अलग आयु वर्गों के लोगों के लिए आयोजित संगीत प्रतियोगिताओं के सीधे प्रसारणों में भी अनेक अहिंदीभाषी राज्यों के प्रतियोगियों ने हिंदी गीत गाकर प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त किए। इन कार्यक्रमों में पुरस्कार के चयन में श्रोताओं द्वारा मतदान देने के नियम ने इनकी पहुंच को और विस्तृत कर दिया। टेलीविज़न चैनलों पर प्रस्तुत किए जा रहे तरह-तरह के लाइव-शो में भाग लेने वाले लोगों को देखकर लगता ही नहीं कि हिंदी कुछ खास प्रदेशों की भाषा है। हिंदी फ़िल्मों की तरह टेलीविज़न के हिंदी कार्यक्रमों ने भी भौगोलिक, भाषायी तथा सांस्कृतिक सीमाएं तोड़ दी हैं।

हिंदी समाचार भी सबसे अधिक दर्शकों द्वारा देखे-सुने जाते हैं। हालांकि इन दिनों हिंदी समाचार चैनल समाचारों के स्तरीय प्रसारण के बजाय अविश्वसनीय और सनसनीखेज ख़बरें प्रसारित करने के लिए आलोचना झेल रहे हैं किंतु फिर भी टीआरपी के मामले में वे अंग्रेज़ी चैनलों से कहीं आगे हैं। इन आलोचनाओं के बावजूद हिंदी ख़बरिया चैनलों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है जून 2009 में 22 नये चैनलों को प्रसारण की अनुमति मिली जिनमें से अधिकांश चैनल हिंदी के हैं और लगभग सभी ने ख़बरें प्रसारित करने की भी अनुमति मांगी है। इस समय देश से अपलिंग होने वाले चैनलों की संख्या 357 है जिनमें से 197 ख़बरिया चैनल हैं। इनमें आधे से अधिक चैनल हिंदी कार्यक्रम या समाचार प्रसारित करते हैं। विदेशों से अपलिंग होने वाले चैनलों की संख्या 60 है। इस संदर्भ में यह जानना दिलचस्प होगा कि स्टार, सोनी, ज़ी जैसे विदेशों से अपलिंग होने वाले चैनलों ने जब भारत में प्रसारण प्रारंभ किया तो उनकी योजना अंग्रेज़ी कार्यक्रम प्रसारित करने की थी, किंतु बहुत जल्दी उन्होंने महसूस किया कि वे हिंदी कार्यक्रमों के जरिये ही इस देश में टिक सकते हैं और वे हिंदी चैनलों में परिवर्तित

होते गए। समाचार प्रसारण में हिंदी के बढ़ते महत्व का ही प्रताप है कि रेडियो और टेलीविज़न की ख़बरों के लिए सभी विशेषज्ञ और नेता अपने साउंडबाइट, टूटी-फूटी और अंग्रेज़ी मिश्रित ही सही, हिंदी में ही देने की कोशिश करते हैं।

जब इंटरनेट ने भारत में पांव पसारने शुरू किए तो यह आशंका व्यक्त की गई थी कि कंप्यूटर के कारण देश में फिर से अंग्रेज़ी का बोलबाला हो जाएगा। किंतु यह धारणा निर्मूल साबित हुई है और आज हिंदी वेबसाइट तथा ब्लॉग न केवल धड़ल्ले से चले रहे हैं बल्कि देश के साथ-साथ विदेशों के लोग भी इन पर सूचनाओं का आदान-प्रदान तथा चैटिंग कर रहे हैं। इस प्रकार इंटरनेट भी हिंदी के प्रसार में सहायक होने लगा है।

हिंदी को लेकर कुछ लोग यह शिकायत करते हैं कि मीडिया व इंटरनेट के कारण हिंदी भाषा विकृत हो रही है और इसका मूल स्वरूप नष्ट हो रहा है। किंतु हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि भाषा एक बहती नदी है और जब उसका अधिक इस्तेमाल होगा तो उसके स्वरूप में कुछ-न-कुछ बदलाव अवश्य आएगा। वास्तव में यह बदलाव विकार नहीं संस्कार है। अकसर कहा जाता है कि मीडिया में इस्तेमाल की जाने वाली भाषा हिंदी नहीं ‘हिंग्लिश’ है। इसी तर्क के आधार पर देखा जाए तो आज अंग्रेज़ी में भी हिंदी का खूब समावेश हो चुका है। अंग्रेज़ी मीडिया और विज्ञापनों में हिंदी मुहावरों, शब्दों और उक्तियों का खुलकर प्रयोग होता है। यदि मीडिया की भाषा परिनिष्ठित हिंदी ही होती तो क्या इतने अधिक अहिंदी भाषी लोग रेडियो या टीवी के हिंदी कार्यक्रमों और समाचारों में अपनी बात हिंदी में रख पाते? हिंदी की स्वीकार्यता बढ़ाने के लिए उसमें स्वच्छंदता लाना आवश्यक है। यह ऐतिहासिक सत्य है कि जब भी कोई भाषा पुराने तटबंधों को तोड़कर नये क्षेत्रों में प्रवेश करती है तो शुद्धतावादी तत्व उससे चिंतित हो जाते हैं। सच तो यह है कि हिंदी इस समय स्वीकार्यता के राजमार्ग पर सरपट दौड़ रही है और हिंदी अश्वमेध के घोड़ों को रोक पाना किसी के बस में नहीं है। मीडिया इस दौड़ को और गतिशील बना रहा है। आज का सच यह है कि जिस तरह हिंदी को अपने प्रसार के लिए मीडिया की ज़रूरत है उसी तरह मीडिया को अपने विस्तार के लिए हिंदी की आवश्यकता है। □

(लेखक आकाशवाणी के समाचार निदेशक रह चुके हैं।)

ई-मेल : setia_subhash@yahoo.co.in)

सीमाओं के आर-पार हिंदी को दुलार

● उमेश चतुर्वेदी

हिंदी को अपनी ज़बान बताते वक्त महमूद बहरी हक़ीक़त में अपनी ही भावनाओं को अभिव्यक्त कर रहे थे। आलमगीर के शासनकाल के दौर के कवि बहरी के ये भाव उनके सैकड़ों साल बाद पैदा हुए विदेशी हिंदी सेवियों पर भी उसी शिद्दत से लागू होता है। ये सच है कि सन् 1835 में ब्रिटिश सरकार के अधिकारी मैकाले ने जो शिक्षा योजना लागू की उसी का नतीजा है कि भारत की देसी संस्कृति पर अंग्रेज़ियत पूरी तरह हावी हो गई। आजादी के तिरैसठ साल बीत गए हैं। विकास की समाजवादी धारा से होते हुए हमने उदारीकरण की व्यवस्था को पूरी तरह आत्मसात कर लिया है। इसके चलते हमारी रोज़ाना की ज़िंदगी पर बाज़ार की संस्कृति हावी हो गई है। यह बाज़ार ही है कि अब हमारी हिंदी को ज्यादा स्वीकार्य बनाता जा रहा है। इसके बावजूद आज भी हमारी सोच से अंग्रेज़ियत का भूत उतरने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन यह भी सच है कि कई विदेशी भी हुए हैं जिनके लिए हिंदी उतनी ही अपनी थी, जितनी हमारे लिए है। हिंदी हमारे लिए महज़ भाषा ही नहीं मां का दूध है। कुछ उसी तरह उन विद्वानों ने भी हिंदी से वैसे ही प्यार किया है जैसे कोई बेटा अपनी मां से करता है। इस कड़ी में सबसे पहला नाम आता है फादर कामिल बुल्के का। 17 अगस्त, 1982 को उनकी मौत के बाद तत्कालीन हिंदी सेवी सांसद शंकर दयाल सिंह ने कहा था— जब कभी अब हिंदी के बारे में कोई संयत विचार होगा, चाहे वह विश्व हिंदी सम्मेलन के मंच पर हो या केंद्रीय समिति की बैठक में अथवा किसी

विश्वविद्यालय में या किसी सभा-समिति में, सभी को बस एक चेहरा याद आएगा— फादर कामिल बुल्के का। इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कामिल बुल्के ने हिंदी के लिए क्या योगदान किया। आज जब भी हमें अंग्रेज़ी-हिंदी शब्दकोश की याद आती है तो हमारी ज़बान पर सबसे पहला नाम फादर कामिल बुल्के के शब्दकोश का ही आता है। संत साहित्यकार के रूप में प्रसिद्ध बुल्के ने रांची (झारखंड) के सेंट जेवियर्स कॉलेज में हिंदी का अध्यापन करते वक्त इस शब्दकोश की रचना की थी। कहां भारत और कहां बेल्जियम, लेकिन

14 सितंबर, हिंदी दिवस पर विशेष

कामिल बुल्के के लिए भारत अपनी मातृभूमि से कहीं ज्यादा प्यारा था। बेल्जियम के वेस्टफ़्लैंड्स प्रांत के एक गांव रांपस में एक सितंबर, 1909 को पैदा हुए बुल्के के घर वाले उन्हें इंजीनियर बनाना चाहते थे। माता-पिता की ख़्वाहिश पर उन्होंने सन् 1930 में वहां के सबसे बेहतर लुवैन विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। लेकिन उनका मन इंजीनियरिंग में नहीं रमा। फिर उन्होंने रोम का रुख किया और वहां के ग्रेगोरियन विश्वविद्यालय से सन् 1932 में दर्शनशास्त्र में एमए किया। यहीं उनका भारतीय दर्शन से परिचय हुआ और उन्होंने भारत आने का निश्चय किया। सन् 1935 में जब उन्होंने भारत की धरती पर क़दम रखा तो मानो उनकी मुग़द ही पूरी हो गई। यहां तुलसी साहित्य से उनका परिचय हुआ। लेकिन उसे समझने के लिए हिंदी सीखना ज़रूरी था। लिहाज़ा सन् 1936 में उन्होंने हिंदी सीखना

शुरू कर दिया। हिंदी के प्रति इस प्यार ने उन्हें संस्कृत से भी जोड़ दिया और बुल्के ने सन् 1945 में बाकायदा कलकत्ता विश्वविद्यालय से संस्कृत की डिग्री हासिल की। इसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने इलाहाबाद का रुख किया और सन् 1947 में यहां से एमए और सन् 1949 में डीफिल की डिग्री हासिल की। सन् 1939 से 1942 के बीच वे धर्मशास्त्र का भी अध्ययन करते रहे। धर्मशास्त्र, संस्कृत और हिंदी के अध्ययन ने उन्हें हिंदी का ही बनाकर छोड़ दिया। इसी का नतीजा था कि उन्होंने सन् 1950 में रामकथा पर पीएचडी की डिग्री हासिल की। जो बाद में *रामकथा- उत्पत्ति और विकास* के नाम से प्रकाशित हुई। इसके बाद जीविका के लिए उन्होंने अध्यापन का पेशा अख़्तियार कर लिया और जीवनपर्यंत वे रांची के सेंट जेवियर्स कॉलेज में हिंदी पढ़ाते रहे। मौत के वक्त वे हिंदी विभागाध्यक्ष की भूमिका निभा रहे थे। उनकी सबसे विख्यात पुस्तक अंग्रेज़ी-हिंदी शब्दकोश है जो सन् 1968 में प्रकाशित हुआ था। इसके पहले सन् 1955 में उनकी पुस्तक हिंदी-अंग्रेज़ी लघुकोश भी प्रकाशित हो चुकी थी। उन्होंने *बाईबिल* का हिंदी में अनुवाद भी किया है जो *नीलपक्षी* नाम से सन् 1978 में प्रकाशित हुआ था। इसके अलावा उनकी एक और पुस्तक *मुक्तिदाता* और *नया विधान* भी प्रकाशित हो चुकी है। फादर कामिल बुल्के का भारत से कितना लगाव था इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने सन् 1950 में भारत की नागरिकता ग्रहण कर ली। इसी साल उन्हें बिहार राष्ट्रभाषा परिषद की कार्यकारिणी

का सदस्य भी बनाया गया। हिंदी के प्रति उनके काम को भारत सरकार ने मान्यता दी। यही वजह है कि उन्हें सन् 1972 से 1977 तक केंद्रीय हिंदी समिति का सदस्य बनाया गया। सन् 1973 में बेल्लिजयम सरकार ने भी अपने इस पूर्व नागरिक को अपनी रॉयल अकादमी का फेलो बनाकर सम्मानित किया।

हिंदी के विदेशी क्षितिज पर चमकते सितारों की फेहरिस्त इतनी लंबी है कि अगर उनमें से खास-खास विद्वानों पर भी चर्चा की जाए तो पत्रिका का पृष्ठ कम पड़ सकता है। बहरहाल, जिस ब्रिटेन के शासकों ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए भारत के भाल की बिंदी हिंदी को दायम दर्जे का बनाने में कोई क्रसर नहीं छोड़ी, उसी ब्रिटेन की धरती पर आज हिंदी फल-फूल रही है। लंदन के हाउस ऑफ़ लार्ड्स के हॉल में हिंदी कथाकारों को हर साल तेजिंदर शर्मा कथा सम्मान से सम्मानित किया जाता है। लंदन की धरती पर हिंदी को प्रतिष्ठित करने में जितना योगदान भारतीय मूल के लोगों का है, उतना ही योगदान ब्रिटेन के अंग्रेज़ हिंदी सेवियों का भी है। उन्हीं में से एक हैं—रूपर्ट स्नेल। उन्हें भारत में हिंदी सेवी के नाम से जाना जाता है। कुछ साल पहले उन्होंने एक प्रमुख हिंदी पत्र को लेखनुमा चिट्ठी भेजी थी, उसमें उन्होंने खुद को हिंदी सेवी के तौर पर ही पेश किया था। डॉ. स्नेल इन दिनों लंदन विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के प्राचार्य हैं। *हित चौरासी* नाम के प्राचीन ग्रंथ पर शोध के लिए विख्यात रूपर्ट स्नेल ने ब्रिटेन की धरती पर हिंदी के क्लासिक रूप को प्रचारित-प्रसारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा को अंग्रेज़ी के विशाल पाठक वर्ग से परिचित कराने वाले रूपर्ट स्नेल अगर हिंदी के कवि के तौर पर जाने जाते हैं तो इसीलिए कि वे ब्रजभाषा में कविताएं लिखते हैं। ब्रज में लिखे उनके सुंदर दोहों को ब्रिटेन के हिंदी प्रेमी काफ़ी शिद्दत से पढ़ते-गुनते रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि वे अच्छी हिंदी बोलते हैं। उनका सबसे बड़ा योगदान यह है कि उन्होंने विदेशी छात्रों के लिए हिंदी शिक्षण पर कई पुस्तकें, ऑडियो टेप के साथ लिखी हैं। उनकी लिखी *टीच योरसेल्फ़ हिंदी* और *बिगिनर्स हिंदी स्क्रिप्ट* विदेशी छात्रों के बीच काफ़ी लोकप्रिय हैं। ये पुस्तकें अपनी रोचकता और उपयोगिता के कारण विभिन्न देशों के स्कूलों और विश्वविद्यालयों में हिंदी शिक्षा हेतु

शिक्षकों द्वारा शिक्षण कार्यक्रमों में प्रयोग में लाई जा रही हैं। इतना ही नहीं ब्रज भाषा पर उनके शोध को न सिर्फ़ भारत, बल्कि पूरी दुनिया में गंभीरता से लिया जाता है।

विदेशी धरती पर हिंदी की अलख जगाने वाले विद्वानों की कड़ी में अगला नाम चेकोस्लोवाकिया के डॉ. ओदोलन स्मेकल का है जो अपनी चमत्कारिक हिंदी कविताओं के लिए काफ़ी विख्यात हैं। उनसे इस लेख के लेखक को करीब एक दशक पहले एक संक्षिप्त मुलाक़ात का मौका मिला था। तब वे दिल्ली में चेकोस्लोवाकिया के राजदूत थे। नृतत्वशास्त्र की पढ़ाई करते वक्त स्मेकल भारतीय संस्कृति से प्रभावित हुए। संस्कृति से इस जुड़ाव ने उन्हें हिंदी का बनाकर रख दिया। उनकी पत्नी हेलेना भी उनकी ही तरह न सिर्फ़ नृतत्वशास्त्री हैं, बल्कि भारतप्रेमी भी हैं। उनके भारत प्रेम का उदाहरण उनकी दोनों संतानें भी हैं, जिनका नाम उन्होंने इंदिरा और अरुण रखा है। ओदोलन स्मेकल ने प्राग विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए और पीएचडी की डिग्री प्राप्त की। उसके बाद वहीं हिंदी के प्राध्यापक नियुक्त हुए। तीस वर्षों तक प्राध्यापक के पद को सुशोभित करने के उपरांत आप कई वर्षों तक भारत-विद्या-विभागाध्यक्ष भी रहे। ओदोलन स्मेकल ने हिंदी साहित्य की कई रचनाओं को चेक भाषा में अनूदित किया है जिनमें प्रमुख हैं— *गोदान* (1957), *आधुनिक हिंदी कविता संकलन* (1975), *भारतीय लोक कथाएं* (1967, 1974)। इसके अलावा उन्होंने हिंदी कवियों की ढेरों रचनाओं और लोक कथाओं का अनुवाद भी किया है जिन्हें संकलित किया जाना अभी बाकी है। ओदोलन स्मेकल ने भारतीय संस्कृति और समाज को कितनी गहराई से समझा है इसे जानने का जरिया है—उनका निबंध संग्रह *भारत के नवरूप* जो सन् 1974 में प्रकाशित हुआ। रूपर्ट स्नेल ने जहां लंदन की धरती से हिंदी के प्रचार-प्रसार में खास भूमिका निभाई है तो स्मेकल ने प्राग विश्वविद्यालय से *हिंदी वार्तालाप* (1968), *हिंदी पाठमाला* (1968), *हिंदी भाषा* (1956), *हिंदी क्रियाएं* (1970, 1971) जैसी कई पाठ्यपुस्तकें भी प्रकाशित की, जिनके जरिये यूरोपीय छात्रों को हिंदी सीखने में आसानी हुई है। इतना ही नहीं, स्मेकल ने केंद्रीय हिंदी निदेशालय के सहयोग से हिंदी-चेक तथा चेक-हिंदी शब्दकोश भी तैयार किया है। हिंदी और भारत के प्रति उनका यह प्यार ही रहा कि उन्हें चेक सरकार ने भारत में अपना राजदूत

नियुक्त किया था।

विदेशी सितारों की इस फेहरिस्त में अगर पोलैंड के क्षितोफ़ मारिया ब्रिस्की का नाम न लिया जाए तो यह फेहरिस्त पूरी नहीं हो पाएगी। क्षितोफ़ मारिया ब्रिस्की नब्बे के दशक के शुरुआती दिनों में भारत में पोलैंड के राजदूत थे। तब दिल्ली में हिंदी की गोष्ठियों में उनकी उपस्थिति अनिवार्य समझी जाती थी। दिल्ली के राष्ट्रीय अभिलेखागार संग्रहालय में उन्होंने अनंतशायी का अंकगणित जैसे विषय पर धाराप्रवाह हिंदी में भाषण देकर लोगों का दिल जीत लिया था। ब्रिस्की ने संस्कृत की पढ़ाई काशी हिंदू विश्वविद्यालय से की। इसके बाद वे पोलैंड लौट गए। वहां उन्हें प्राच्यविद्या अध्ययन संस्थान में प्राध्यापक की नौकरी मिल गई। जहां बाद में उन्हें निदेशक बना दिया गया। सन् 1932 से स्थापित यह संस्थान पोलैंड में भारतीय संस्कृति और हिंदी और बांग्ला भाषा में अध्ययन-अध्यापन का प्रमुख केंद्र रहा। ब्रिस्की के प्रयास से ही बाद में यहां एक और भारतीय भाषा तमिल की भी पढ़ाई होने लगी। चूंकि ब्रिस्की भारत में रहे हैं और भारतीय धर्म-संस्कृति के साथ ही पर्व और त्यौहारों को न सिर्फ़ गहराई से देखा-समझा है, बल्कि उसे जिया भी। शायद यही वजह है कि हिंदी शिक्षण को लेकर उनके मन में खास भाव रहा। खालिस हिंदी रचनाओं की कविताओं को पोलिश भाषा में अनुवाद के जरिये पोलैंड में लोकप्रिय बनाने में भी ब्रिस्की की खास भूमिका रही है। ब्रिस्की को भारतीय भाषाओं के शब्दों की गहरी समझ है। यही वजह है कि उनके अनुवाद पोलैंड में न सिर्फ़ क्लासिक के तौर पर सम्मानित हुए हैं, बल्कि वे लोकप्रिय भी हुए हैं। हिंदी कविताओं के अलावा उनकी दिलचस्पी लोकनाटकों और नाटकों में भी रही है। भारतीय लोकनाट्य परंपरा से पोलैंडवासियों को पहली बार ब्रिस्की ने ही भारतीय लोकनाटक नामक लेख लिखकर परिचित कराया है। नाटकों में अपनी दिलचस्पी की वजह से ही उन्होंने कई मशहूर नाटकों मसलन लक्ष्मीनारायण लाल का नाटक तोता-मैना और सर्वेश्वरदयाल सक्सेना के नाटक बकरी का अनुवाद किया। ब्रिस्की हिंदी में भी लिखते रहे।

हिंदी के दूसरे सितारे हैं जापान के मिवाको कोईजुका। जापान के ओसाको शहर में रह रहे कोईजुका ने जापान में हिंदी को लोकप्रिय बनाने में खास भूमिका निभाई है। आज भी हिंदी

साहित्य के शिक्षण में हिंदी सिनेमा को उचित और गंभीर स्थान नहीं मिल पाया है। साहित्य के शिक्षण में सिनेमा की चर्चा आते ही लोग नाक-भौं सिकोड़ने लगते हैं। हिंदी के प्रचार में बॉलीवुड के सिनेमा के योगदान की तो चर्चा जमकर होती है लेकिन साहित्य और भाषा के शिक्षण में उसके योगदान को अभी तक खास स्थान नहीं मिल पाया है। लेकिन जापान के विद्वान मिवाको कोईजुका ने हिंदी सिनेमा के ही जरिये जापानी धरती पर हिंदी शिक्षण में नयी क्रांति ला दी है। इतना ही नहीं, वहां हिंदी फ़िल्मों के साथ टीवी धारावाहिकों और नाटकों का भी हिंदी शिक्षण में व्यापक उपयोग किया जा रहा है। इस सिलसिले में हिंदी के सुप्रसिद्ध धारावाहिक रामायण को हिंदी पाठ्य सामग्री के तौर पर तैयार किया गया है। कोईजुको जैसे विद्वानों की मेहनत और निष्काम हिंदी सेवा का क्या योगदान है, इसकी चर्चा यह जापान के हिंदीभाषियों को अच्छी तरह से पता है। टोकियो या ओसाका की

धरती पर कोईजुको से हिंदी में विनम्रतापूर्वक बात करते छात्र अकसर मिल जाते हैं। उन्होंने आगे बताया कि पिछले वर्ष उनके नेतृत्व में जापानी छात्रों ने भारत के प्रमुख शहरों में हिंदी में नाटकों का सफलतापूर्वक मंचन किया था। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर गिरीश बख्शी के सहयोग से रामायण के लोकप्रिय धारावाहिक को हिंदी पाठ्यसामग्री के रूप में तैयार करने के लिए लिप्यांकित करके प्रकाशित भी करवाया है।

विदेशी धरती पर हिंदी की सेवा करने वाले सितारों में रूस के पी.ए. वारान्निाकोव और जर्मनी के लोठार लुत्से का भी नाम शिद्दत से लिया जाता है। लोठार लुत्से भारत में जर्मनी के सांस्कृतिक केंद्र मैक्समूलर केंद्र के निदेशक रहे हैं। उनकी पत्नी बारबरा लुत्से भी नब्बे के दशक के आखिरी दिनों में मैक्समूलर भवन की निदेशक रहीं। पति-पत्नी दोनों के कार्यकाल में दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस स्थित मैक्समूलर भवन में हर महीने

हिंदी कवियों की रचनाओं के पाठ और हिंदी गोष्ठियों का आयोजन होता रहा है। लुत्से दंपति को हिंदी में बातचीत करते देख अच्छे-भले लोग हैरत में पड़ जाते थे। लोठार लुत्से ने हिंदी के कई मशहूर कवियों मसलन- विष्णु खरे और अशोक वाजपेयी की कविताओं का अनुवाद किया है। जर्मनी में वे भारतविद के तौर पर मशहूर हैं। वहीं रूस के पी.ए. वारान्निाकोव ने रामायण का रूसी भाषा में अनुवाद किया है। इसके साथ ही वे हिंदी में लिखते रहे हैं। मास्को विश्वविद्यालय में हिंदी पढ़ाते वक्त वारान्निाकोव हिंदी अखबारों के लिए समय-समय पर लेख भी लिखते रहे हैं। जन्म से विदेशी लेकिन दिल से हिंदी इन हिंदी सेवियों के योगदान की चर्चा के बिना हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास पूरा नहीं होता। बाजारवाद के इस दौर में अंग्रेज़ियत के खिलाफ़ खड़े होने के लिए इन हिंदीसेवियों की याद ही काफी है। □

(लेखक टेलीविजन पत्रकार हैं।

ई-मेल : uchaturvedi@gmail.com)

राष्ट्रमंडल खेल : महत्वपूर्ण घटनाक्रम

- 1930 – अगस्त 1930 में हैमिल्टन (कनाडा) में प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन। महिलाएं सिर्फ़ तैराकी में।
- 1934 – अगस्त 1934 में लंदन (इंग्लैंड) में दूसरे राष्ट्रमंडल खेल। भारत ने पहली बार भाग लिया। महिला एथलीटों ने भी पहली बार भाग लिया। साइकिल चालन खेल कार्यक्रम में शामिल।
- 1938 – फरवरी 1938 में सिडनी (ऑस्ट्रेलिया) में तीसरे राष्ट्रमंडल खेल। ऑस्ट्रेलियाई धाविका डेसिमा नौरमन का शानदार प्रदर्शन।
- 1942 – मांट्रियल (कनाडा) में होने वाले चौथे राष्ट्रमंडल खेल विश्व युद्ध के कारण रद्द।
- 1946 – विश्व युद्ध के कारण खेल नहीं हो सका। ये खेल कार्डिफ (वेल्स) में होने थे।
- 1950 – फरवरी 1950 में चौथे राष्ट्रमंडल खेल आकलैंड (न्यूजीलैंड) में संपन्न हुआ। फेंसिंग (तलवारबाजी) और भारोत्तोलन खेल कार्यक्रम में शामिल हुआ। भारत ने भाग नहीं लिया।
- 1954 – जुलाई-अगस्त 1954 में वैनकूवर (कनाडा) में पांचवें राष्ट्रमंडल खेल हुए।
- 1958 – जुलाई 1958 में छठे राष्ट्रमंडल खेल कार्डिफ (वेल्स) में आयोजित हुआ। इसमें भारत को पहली बार स्वर्णम सफलता मिली।
- 1994 – अगस्त 1994 में विक्टोरिया (कनाडा) में पंद्रहवें राष्ट्रमंडल खेल आयोजित किए गए। 36 वर्ष बाद दक्षिण अफ्रीका ने पुनः राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लिया। 1958 के बाद पहली बार भारतीय पहलवान स्वर्ण पदक से वंचित रहा।
- 1998 – सितंबर 1998 में सोलहवें राष्ट्रमंडल खेल कुआलालंपुर (मलेशिया) में संपन्न हुए। इस तरह यह एशिया में पहली बार राष्ट्रमंडल खेल हुआ। पहली बार हॉकी, क्रिकेट, स्क्वैश, रग्बी और नेटबॉल खेल कार्यक्रम में शामिल किए गए। पहली बार टीम खेल शामिल।
- 2002 – जुलाई-अगस्त 2002 में सत्रहवें राष्ट्रमंडल खेल मानचेस्टर (इंग्लैंड) में खेले गए। करीब सात दशक बाद दूसरी बार ये खेल इंग्लैंड में हुए। कार्यक्रम में 17 खेल विधाएं शामिल। महिलाओं का भारोत्तोलन, माउंटन बाइकिंग, ट्रायथलन और टेबल टेनिस पहली बार सम्मिलित हुए। पहली बार ईएडी स्पेर्द्धाएं शामिल।
- 2006 – मार्च 2006 में अठारहवें राष्ट्रमंडल खेल मेलबोर्न (ऑस्ट्रेलिया) में। ऑस्ट्रेलिया चौथी बार राष्ट्रमंडल खेलों का आतिथेय। बास्केटबॉल पहली बार खेल कार्यक्रम में शामिल। निशानेबाजी में 5 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीतने वाला भारत का समरेश जंग मेलबोर्न खेलों का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित हुआ। समरेश जंग को डेविड डिकसन पुरस्कार दिया गया।
- 2010 – भारत 2010 में दिल्ली में होने वाले उन्नीसवें राष्ट्रमंडल खेलों का आतिथेय।
- 2014 – बीसवें राष्ट्रमंडल खेल स्कॉटलैंड के सबसे बड़े नगर ग्लासगो में आयोजित होंगे।



पर्यावरण

प्रोजेक्ट चीता

● सुरेश प्रकाश अवस्थी

भारत सरकार ने हाल ही में देश में लुप्त हो चुके चीते को फिर से जंगलों में बसाने की तीन अरब रुपये की योजना को स्वीकार कर वन्यजीव प्रेमियों को एक बड़ी खुशखबरी दी है। क़रीब आधी सदी पूर्व देश से गायब हो चुके चीते को बसाने की परियोजना—प्रोजेक्ट चीता के पहले चरण को स्वीकृति मिल गई है। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री जयराम रमेश के अनुसार मध्य प्रदेश में दो और राजस्थान में एक वन क्षेत्र को इस परियोजना के लिए चुना गया है। इन वन क्षेत्रों में शुरू में छह-छह चीते लाए जाएंगे। आशा है कि तीन-चार वर्षों में चीते भारत में फिर से छलांगें भरने लगेंगे।

मध्य प्रदेश के कूनो-पालपुर वन्यजीव अभयारण्य और नौरादेही वन्यजीव अभयारण्य के अलावा राजस्थान के जैसलमेर जिले के शाहगढ़ का चयन प्रोजेक्ट चीता के लिए किया गया है। इन अभयारण्यों में अफ़्रीकी प्रजाति के चीते लाए जाएंगे। इनके लिए नामीबिया और दक्षिण अफ़्रीका से बात चल रही है। उत्तरी अफ़्रीका के चीते पश्चिम एशिया के कई देशों में पल रहे हैं और वहीं से भारत लाए जाएंगे। ईरान से भी बात हो चुकी है। ये देश बिना किसी लागत के भारत को दो चीते देने को तैयार हैं। विशेषज्ञों ने भी ईरानी और अफ़्रीकी नस्ल के चीतों को भारत की जलवायु के अनुकूल पाया है। दोनों देशों में पाए जाने वाले चीतों में आनुवांशिक समानता

भी है। श्री रमेश के अनुसार पिछले छह महीने से उनका मंत्रालय देश में चीता लाने की परियोजना पर काम कर रहा है। पिछले वर्ष सितंबर 2009 में देश में चीते पर एक अंतरराष्ट्रीय बैठक भी हुई थी। इसके बाद पर्यावरणविद रणधीर सिंह, चीता विशेषज्ञ दिव्यभानु सिंह और भारतीय वन्यजीव संस्थान के श्री वी.के. झाला की सदस्यता वाली तीन सदस्यों की एक समिति बनाई गई जिसने देश के 10 वन्य क्षेत्रों (अभयारण्यों आदि) का अध्ययन कर 28 जुलाई को अपनी रिपोर्ट मंत्रालय को सौंपी। इस रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए श्री रमेश ने प्रोजेक्ट चीता को मूर्त रूप देने के निर्देश दिए हैं।

विशेषज्ञों के अनुसार चीता भारतीय जीवन से अभिन्न रूप से जुड़ा वन्यप्राणी है। यह संभवतः एकमात्र स्तनपायी जंतु है जिसे आज भी विश्वभर में चीता कह कर ही बुलाया जाता है। चीता संस्कृत के 'चित्राकु' शब्द का अपभ्रंश है, जिसका अर्थ है— धब्बेदार। वनक्षेत्रों से जुड़े हुए चरागाहों में रहने वाला संसार का सबसे तेज प्राणी मानव जाति के लालच का शिकार हुआ है। अपनी खूबसूरत और आकर्षक खाल के लिए यह शुरू से ही शिकारियों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा। विशेषज्ञों के अनुसार पिछली शताब्दी के पचासवें दशक तक चीता भारत के जंगलों में विचरता था। परंतु राजे-रजवाड़ों के शिकार के शौक और तस्करों के लालच ने इसे

शीघ्र ही देश से गायब कर दिया। देखने में समानता के कारण लोग अभी भी तेंदुए को चीता समझने की भूल कर बैठते हैं। परंतु दोनों काफ़ी अलग हैं। लगभग एक दशक पूर्व, यूरोप में जब क्लोनिंग से एक भेड़ का विकास किया गया था तब हैदराबाद स्थित सेंटर फॉर सेल्युलर एंड कालेकुअर बायोलॉजी में चीते की क्लोनिंग के जरिये उसे पुनर्जीवन देने का प्रयास किया गया था और आशा जताई गई थी कि वर्ष 2005 तक उसका क्लोन तैयार हो जाएगा। परंतु लगता है कि अभी तक यह प्रयास सफल नहीं हो पाया है। मैसूर के वन्यप्राणी संग्रहालय (चिड़ियाघर) ने भी 2001 में अफ़्रीकी नस्ल के चीते के पालन-पोषण की बात कही थी पर किन्हीं कारण वश यह विचार भी साकार नहीं हो सका।

जाने-माने वन्यजीव विशेषज्ञ दिव्यभानु सिंह ने चीते के बारे में काफ़ी कुछ लिखा-पढ़ा है। उनका कहना है कि क़रीब 2 हजार वर्ष पूर्व चीते भारत में पाले जाते थे और बारहवीं शताब्दी के आते-आते राजे-महाराजे उनका उपयोग हिरणों के शिकार के लिए करने लगे थे। इन सदियों के दौरान हजारों चीतों का शिकार किया जा चुका है। कहा जाता है कि मुगल सम्राट अकबर के पास एक हजार चीते थे। चीतों की संख्या में कमी आने का सबसे बड़ा कारण उसकी खुद की शिकार करने की आदत है। वह अपने शिकार को आखिर तक दौड़ाता है और इस प्रयास में

वह प्रायः घास के मैदानों एवं चरागाहों में प्रवेश कर जाता है। आबादी के विस्तार के कारण धीरे-धीरे घास के मैदान कम होते गए और चीतों को अपना जीवन बचाना कठिन हो गया। चीता विशेषज्ञों के अनुसार वर्ष 1947 में अंतिम तीन चीतों का शिकार किया गया और वर्ष 1968 में देश में अंतिम बार चीते को देखा गया।

श्री रमेश ने प्रोजेक्ट चीता को मंजूरी देते हुए कहा था कि चीते को भारत लाने से भारत की पर्यावरण प्रणाली और पारिस्थितिकी के संरक्षण में भी बड़ी मदद मिलेगी। चूक बाघ जंगल में होते हैं और चीता चरागाहों में रहता है, इसीलिए यदि चीता लाया गया तो इस बहाने घास के मैदानों और चरागाहों को भी बचाया जा सकेगा। परंतु इस परियोजना की सबसे बड़ी समस्या भी यही है। जिस देश में चरागाह, जनसंख्या के बोझ तले और विकास की आवश्यकताओं के कारण निरंतर समाप्त होते जा रहे हैं, वहां 5,600 वर्ग किलोमीटर चरागाह क्षेत्र को चीतों के लिए विकसित करना सचमुच एक चुनौतीपूर्ण कार्य

होगा। आज की परिस्थिति में गांवों को उजाड़ना और विस्थापितों का पुनर्वास एक जटिल समस्या है। परंतु सरकार ने इसके लिए जो 80 करोड़ रुपये की योजना बनाई है इस पर यदि ईमानदारी से और मन से अमल किया गया तो सुखद नतीजे देखने को मिल सकते हैं। चीतों को बसाने के लिए तीन जगहों का चुनाव किया गया है, उनकी पर्यावरणीय स्थिति ऐसी है कि उन्हें शीघ्र ही इस परियोजना के लिए तैयार किया जा सकता है और वहां तत्काल चीते लाकर छोड़े जा सकते हैं।

मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में स्थित कूनो-पालपुर वन्यप्राणी अभयारण्य को चीता पालन के लिए आदर्श माना जा रहा है। वाइल्डलाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया (डब्ल्यूटीआई) और वाइल्डलाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (डब्ल्यूआईआई) ने पांच राज्यों के उन वन्य क्षेत्रों का व्यापक सर्वेक्षण किया था, जिसमें करीब 50 वर्ष पूर्व चीते रहा करते थे और इनमें कूनो पालपुर को सर्वोत्तम माना गया है। इस

क्षेत्र में गुजरात के सिंहों को भी बसाने की योजना है। डब्ल्यूटीआई के प्रमुख एम.के. रणजीत सिंह का कहना है कि यदि चीतों और सिंहों को कूनो से लाकर बसाया जाता है तो यह एक अनूठी पर्यावरणीय स्थिति होगी, जिसमें चीता, सिंह और तेंदुए साथ-साथ रह सकेंगे। लेकिन इसके लिए चीते को पहले लाकर बसाना होगा। परियोजना के तहत लगे जैसलमेर जिले के इस अभयारण्य में चीते को सुरक्षित रूप से बसाने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने होंगे। इसके लिए 140 किमी लंबी बाड़ तैयार करनी होगी, जबकि सीमावर्ती क्षेत्र में पहले से ही बाड़ लगी हुई है। तीसरा इलाका मध्य प्रदेश का नौरादेही अभयारण्य है, जो सागर संभाग में स्थित है। यह अभयारण्य प्राकृतिक रूप से चीता पालन के लिए आदर्श है। ऐसे में चीतों की वापसी होती है तो चरागाहों को भी नया जीवन मिलेगा साथ ही देश में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। इसे एक स्वागत योग्य कदम ही कहा जाएगा। □

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं)



सदस्यता कूपन

नयी सदस्यता / नवीकरण / पता बदलने के लिए
(जो लागू होता हो उस पर '✓' का चिह्न लगाएं।)

मैं (पत्रिका का नाम एवं भाषा) का वार्षिक (100 रुपये) द्विवार्षिक (180 रुपये)

त्रिवार्षिक (250 रुपये) सदस्य बनने का इच्छुक हूँ। डिमांड ड्राफ्ट/भारतीय पोस्टल आर्डर/मनीआर्डर संख्या तारीख

नाम

वर्ग विद्यार्थी शिक्षक संस्था अन्य

पता :.....
.....
.....

पिन

नवीकरण/पता बदलने के लिए कृपया अपनी सदस्य संख्या यहां लिखें

डिमांड ड्राफ्ट/भारतीय पोस्टल आर्डर/मनीआर्डर 'निदेशक, प्रकाशन विभाग' के नाम से बनवाएं और कूपन के साथ इस पते पर भेजें :

व्यापार व्यवस्थापक (प्रसार) प्रकाशन विभाग,

पूर्वी खंड-IV, सातवां तल, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली-110066



रोज़गार समाचार

साप्ताहिक

क्या आप सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम/कर्मचारी चयन आयोग/संघ लोक सेवा आयोग/रेलवे भर्ती बोर्ड/सशस्त्र सेनाओं/बैंकों में रोज़गार तलाश रहें हैं?



रोज़गार समाचार आपका श्रेष्ठ मार्गदर्शक है। यह विगत तीस वर्षों से नौकरियों के लिए सबसे अधिक बिकने वाला साप्ताहिक है। आप भी इसके सहभागी बनें।

आपका हमारी वेबसाइट: employmentnews.gov.in

पर स्वागत है, जो कि नवीनतम प्रौद्योगिकी से विकसित है।

- उन्नत किस्म के सर्च इंजिन से युक्त है।
- आपके प्रश्नों का विशेषज्ञों द्वारा शीघ्र समाधान करती है।

रोज़गार समाचार/एम्प्लॉयमेंट न्यूज की प्रति के लिए निकटतम वितरक से संपर्क करें।

व्यापार संबंधी पूछताछ के लिए संपर्क करें:

रोज़गारसमाचार, पूर्वीखण्ड 4, तल 5, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली।

फोन : 26182079, 26107405, ई-मेल : enabmsa@yahoo.com



प्रकाशन विभाग
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
भारत सरकार

ख़बरों में

● निशानेबाज तेजस्विनी सावंत ने रचा इतिहास

तेजस्विनी सावंत ने जर्मनी के म्यूनिख में आईएसएसएफ विश्व निशानेबाजी प्रतियोगिता में इतिहास रचते हुए पहली भारतीय महिला विश्व चैंपियन बनने का गौरव हासिल कर लिया। तेजस्विनी ने 50 मीटर राइफल प्रोन स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड की बराबरी करने के साथ विश्व चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। यह गैर ओलंपिक स्पर्धा थी और इसमें 2012 के लंदन ओलंपिक के लिए कोई कोटा नहीं था। भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ (एनआरएआई) से प्राप्त जानकारी के अनुसार तेजस्विनी ने 600 में से 597 का स्कोर कर रूस की मारिना बोकोवा के 1998 में बनाए विश्व रिकॉर्ड की बराबरी कर ली।

मेलबर्न कॉमनवेल्थ गेम्स में एयर राइफल स्पर्धा में दो स्वर्ण पदक जीतने वाली 29 वर्षीया तेजस्विनी और पोलैंड की इवा जोआना नोवाकोवस्का का विश्व चैंपियनशिप में 50 मीटर राइफल प्रोन स्पर्धा में 597 का एक बराबर स्कोर रहा। तेजस्विनी ने अपने कुल स्कोर में 100, 100, 100, 99, 99, 99 की सीरीज़ खेली। चूंकि यह गैर-ओलंपिक स्पर्धा थी इसलिए इसमें कोई फाइनल नहीं था। तेजस्विनी और नोवाकोवस्का का स्कोर बराबर रहने के बाद भारतीय निशानेबाज ने टाई शॉट में बाजी मारकर विश्व चैंपियन बनने का गौरव हासिल कर लिया। कजाकिस्तान की ओल्गा डोवगन को 596 के स्कोर के साथ कांस्य पदक मिला। हालांकि ओलंपियन अंजलि भागवत ने एक बार चैंपियन ऑफ चैंपियंस का खिताब जीता था लेकिन वह टूर्नामेंट विश्व चैंपियनशिप नहीं था इसलिए तेजस्विनी के नाम ही पहली भारतीय महिला विश्व चैंपियन निशानेबाज बनने का गौरव लिखा गया।

म्यूनिख में विश्व चैंपियनशिप भारत के लिए बेहद यादगार रही है। इस चैंपियनशिप से गगन नारंग और हरिओम सिंह ने 2012 के लंदन ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है जबकि 17 वर्षीय अशेर नौरिया ने जूनियर विश्व रिकॉर्ड की बराबरी करने के साथ जूनियर विश्व खिताब भी जीता।

इतिहास रचने के बाद तेजस्विनी ने कहा कि वह अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना चाहती थी। उन्हें पदक या विश्व रिकॉर्ड की उम्मीद नहीं थी।

कोल्हापुर की इस निशानेबाज ने कहा, “हमारी ट्रेनिंग को देखते हुए यह मेरा सर्वश्रेष्ठ व्यक्तिगत प्रदर्शन था। मैं पदक या विश्व रिकॉर्ड के बारे में नहीं सोच रही थी। लेकिन दोनों ही उपलब्धि हासिल कर ली। मैं नहीं बता सकती कि इस समय मैं कैसा महसूस कर रही हूं। यह शानदार है।” उन्होंने कहा, “कजाकिस्तान के कोच स्टेनिसलास लैपिडस समेत मेरे कोचों ने मेरे लिए योजना बनाई और मैं खुश हूं कि सब कुछ मेरे हिसाब से हुआ।” तेजस्विनी ने कहा, काफ़ी मुश्किलें भी आती हैं, लेकिन शिकायत करने के बजाय मुझे लगता है कि इनका प्रेरणा के तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए और कड़ी मेहनत करनी चाहिए। मेरे माता-पिता ने भी मुझे यही सीख दी है।

● सायना नेहवाल को राजीव गांधी खेल रत्न

विश्व की दूसरी वरीयता प्राप्त महिला बैडमिंटन खिलाड़ी सायना नेहवाल को इस वर्ष राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया

अब तक के राजीव गांधी खेल रत्न विजेता

1. विश्वनाथन आनंद (शतरंज 1991-92)
2. गीत सेठी (बिलियर्ड्स, 1992-93)
3. मोतीवाला/गर्ग (नौकायन, 1994-95)
4. कर्णम मल्लेश्वरी (वेटलिफ्टिंग, 1995-96)
5. कुंजुरानी/लिण्डर पेस (वेटलिफ्टिंग/टेनिस, 1996-97)
6. सचिन तेंडुलकर (क्रिकेट 1997-98)
7. सिकंदर (एथलेटिक्स, 1998-99)
8. धनराज पिल्लै (हॉकी, 1999-2000)
9. पुलेला गोपीचंद (बैडमिंटन, 2000-01)
10. अभिनव बिंद्रा (निशानेबाजी, 2001-02)
11. अंजली भागवत/के. बीनामोल (निशानेबाजी/एथलेटिक्स, 2002-03)
12. अंजू बॉबी जॉर्ज (एथलेटिक्स, 2003-04)
13. राज्यवर्धन सिंह राठौर (निशानेबाजी, 2004-05)
14. पंकज आडवाणी (बिलियर्ड्स, 2005-06)
15. मानवजीत सिंह (निशानेबाजी, 2006-07)
16. महेंद्र सिंह धोनी (क्रिकेट, 2007-08)
17. मैरीकॉम/वीजेंद्र सिंह/सुशील कुमार (बॉक्सिंग/बॉक्सिंग/कुश्ती, 2008-09)
18. सायना नेहवाल (बैडमिंटन) 2009-10

है। यह देश का सर्वोच्च खेल सम्मान है। सायना ने इस वर्ष न सिर्फ जकार्ता में इंडोनेशिया ओपन सुपर सीरीज बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब अपने पास बरकरार रखा बल्कि इंडियन ओपन व सिंगापुर ओपन जीतने का भी श्रेय पाया। इतना ही नहीं उन्होंने अपना विश्व रैंकिंग क्रम छठे से दूसरे स्थान पर लाने में कामयाबी हासिल की। सायना की सफलताओं ने उन्हें विश्व वरीयता क्रम में दूसरे स्थान पर पहुंचा दिया। वह इस वर्ष बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2010 में कांस्य पदक जीतने में सफल रही थी। इसी वर्ष सायना ने ऑल इंग्लैंड सुपर सीरीज 2010 के सेमीफाइनल में पहुंचकर भारतीय खिलाड़ियों के लिए एक और मील का पत्थर स्थापित किया था।

सायना को उनकी शानदार अंतरराष्ट्रीय उपलब्धियों के लिए 29 अगस्त को खेल दिवस के दिन राष्ट्रपति भवन में देश के सर्वोच्च खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेलरत्न से सम्मानित किया गया।

● 15 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार

भारतीय फुटबॉल टीम के स्टार स्ट्राइकर सुनील छेत्री, विश्व की नंबर एक महिला गेंदबाज झूलन गोस्वामी, ओलिंपियन पहलवान राजीव तोमर और हॉकी के ड्रैग पिलकर संदीप सिंह सहित 15 खिलाड़ियों को 29 अगस्त को राष्ट्रपति भवन में प्रतिष्ठित अर्जुन पुरस्कार के लिए चुना गया है। पी.टी. ऊषा की अध्यक्षता में राजीव गांधी खेल रत्न, अर्जुन और ध्यानचंद पुरस्कारों के लिए गठित 15 सदस्यीय समिति ने अर्जुन पुरस्कारों के लिए 15 खिलाड़ियों का चयन किया।

● महिला उम्मीदवारों का परीक्षा शुल्क माफ़

केंद्र सरकार द्वारा आयोजित की जाने वाली सभी तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं में अब महिलाओं से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। रोजगार में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने यह क़दम उठाया है।

परीक्षाओं के साथ-साथ साक्षात्कार आदि के लिए भी लगने वाले शुल्क से महिलाओं को पूरी तरह छूट दी गई है। केंद्र सरकार की नौकरियों में महिलाओं की औसत हिस्सेदारी 15-20 फ़ीसदी के बीच है, जबकि महिलाओं की आबादी करीब 48 फ़ीसदी है। इस हिसाब

से नौकरियों में उनका प्रतिनिधित्व कम है। कार्मिक मंत्रालय द्वारा जारी ताजा आदेश में कहा गया है कि केंद्र सरकार के किसी भी मंत्रालय, स्वायत्त संस्थान या संबद्ध एजेंसियों द्वारा आयोजित कराई जाने वाली सभी तरह की प्रतियोगी परीक्षा व साक्षात्कार के लिए महिलाओं को शुल्क से पूरी छूट प्रदान की जाएगी। इसमें इंजीनियरिंग, मेडिकल समेत तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं को शामिल किया गया है। मेडिकल और इंजीनियरिंग जैसी परीक्षाओं में महिलाओं की हिस्सेदारी सात-आठ फ़ीसदी से ज्यादा नहीं बढ़ पाई है।

इससे पूर्व पिछले साल सरकार ने इस दिशा में पहला क़दम बढ़ाया था। तब संघ लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षाओं में लगने वाले शुल्क से महिलाओं को छूट दी गई थी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। केंद्र सरकार ने यह भी तय किया है कि यदि 10 से ज्यादा नियुक्तियां होती हैं तो नियुक्ति बोर्ड में एक महिला उम्मीदवार की नियुक्ति होना ज़रूरी होगा। साथ ही अब विज्ञापनों में महिलाओं को नौकरियों में मिलने वाले सरकारी लाभों की जानकारी देना ज़रूरी कर दिया गया है।

● मौलाना वहीदुद्दीन खान को राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार के लिए मौलाना वहीदुद्दीन खान हो चुना गया है। यह जानकारी पुरस्कार की सलाहकार समिति के सदस्य सचिव मोतीलाल बोरा ने दी। मौलाना को सद्भावना पुरस्कार सांप्रदायिक सौहार्द, शांति और सद्भावना को बढ़ावा देने में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया गया है। यह पुरस्कार राजीव गांधी के जन्मदिवस 20 अगस्त को एक विशिष्ट समारोह में प्रदान किया गया। पुरस्कार के तौर पर एक प्रशस्ति पत्र और पांच लाख रुपये ऐसे व्यक्ति या संस्था को दिया जाता है जिसने कौमी एकता की स्थापना और हिंसा और आतंकवाद के खिलाफ उल्लेखनीय योगदान किया हो। पूर्व में यह पुरस्कार मदर टेरेसा, बिस्मिल्लाह खान, लता मंगेशकर, स्वामी अग्निवेश समेत कई ख्यातिप्राप्त विभूतियों को मिल चुका है।

● राष्ट्रीय नवाचार परिषद को मंजूरी

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने नेशनल इनोवेशन काउंसिल के गठन की मंजूरी दे दी है। यह



सरकार के समग्र विकास एजेंडे के लिए उपयुक्त मॉडल सुझाएगी। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है, “यह सरकारी ज़रूरतों के मुताबिक उपयुक्त पॉलिसी की रूपरेखा तय करेगी, ताकि

सायना का विजयी सफ़र

- 2003 – चेकोस्लोवाकिया जूनियर ओपन
- 2005 – एशियन सेटेलाइट बैडमिंटन टूर्नामेंट
- 2006 – फिलिपींस ओपन
- 2006 – एशियन सेटेलाइट बैडमिंटन
- 2007 – इंडियन नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप
- 2008 – योनेस्क चीनी ताइपे ओपन
- 2008 – वर्ल्ड जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप
- 2009 – इंडोनेशियन ओपन सुपर सीरीज
- 2010 – इंडियन ओपन ग्रां प्री
- 2010 – सिंगापुर ओपन सुपर सीरीज
- 2010 – इंडोनेशियन ओपन सुपर सीरीज

अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन

कॉमनवेल्थ गेम्स 2006 कांस्य पदक (मिक्सड डबल्स) बीजिंग ओलंपिक 2008 क्वार्टर फाइनल, बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2010-कांस्य पदक, ऑल इंग्लैंड सुपर सीरीज 2010-सेमीफाइनल

अर्जुन पुरस्कार के लिए चुने गए खिलाड़ी

कृष्णा पूनिया (एथलेटिक्स), दिनेश कुमार (मुक्केबाज), परिमार्जन नेगी (शतरंज), झूलन गोस्वामी (क्रिकेट), दीपक मंडल और सुनील छेत्री (फुटबाल), राजीव तोमर (कुश्ती), संदीप सिंह (हॉकी), जसजीत कौर (हॉकी), जोसफ अब्राहम (एथलेटिक्स), जजसीर सिंह (पैरालंपिक्स), दिनेश (कबड्डी), कपिल देव (वालीबॉल), रेहान पांचा (तैराकी) और संजीव राजपूत (निशानेबाजी)।

आजीवन उपलब्धि के लिए ध्यानचंद पुरस्कार

सतीश पाल (एथलेटिक्स), कुलदीप सिंह (कुश्ती) और अनीता चानू (भारोत्तोलन)।

नवाचार को बढ़ावा दिया जा सके। यह क्षेत्रीय नवाचार परिषद और स्टेट इनोवेशन काउंसिल (राज्यस्तरीय नवाचार परिषद) को स्थापित करने में बड़ी भूमिका निभाएगी।” यह परिषद नवाचार दशक, 2010-20 के लिए रूपरेखा तैयार करेगी। इसमें सूक्ष्म, छोटे और मध्यम उद्यमों और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए नवाचार पर खास जोर रहेगा। जनसूचना संबंधी बुनियादी ढांचे और नवाचार पर प्रधानमंत्री के सलाहकार सैम पित्रोदा इस

16 सदस्यीय परिषद की अगुवाई करेंगे। इसके सदस्यों में योजना आयोग के अरुण मायरा और के. कस्तूरीरंगन के अलावा किरण मजूमदार शां, किरण कार्णिक, शंखर कपूर और टाटा संस के निदेशक आर. गोपालकृष्णन शामिल हैं।

● देश के 200 जिलों में ‘सबला’ को हरी झंडी

लंबे इंतज़ार के बाद राजीव गांधी किशोरी सशक्तीकरण योजना (सबला) को आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने मंजूरी दे दी है। किशोरियों के बेहतर स्वास्थ्य और आर्थिक मजबूती के लिए शुरू की गई इस योजना को देश के चुनिंदा 200 जिलों में लागू किया जाएगा। इनमें शानदार, सामान्य, खराब प्रदर्शन वाले यानी हर स्तर के जिले शामिल किए जाएंगे। 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत इस योजना के लिए 4,500 करोड़ रुपये का बजट मंजूर किया गया है, जिसमें वित्त वर्ष 2010-11 के लिए हजार करोड़ रुपये का प्रावधान है।

‘सबला’ के तहत सालाना 92 लाख से लेकर 1.15 करोड़ किशोरियों के लाभान्वित होने का अनुमान है। योजना को समेकित बाल विकास योजना के तहत चल रहे आंगनवाड़ी केंद्रों के मार्फत लागू किया जाएगा। जहां आंगनवाड़ी केंद्रों में पर्याप्त बुनियादी ढांचे का अभाव होगा, वहां स्कूलों, पंचायत घरों अथवा सामुदायिक भवनों में वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी। योजना के तहत 11 से 18 वर्ष तक की किशोरियों को रोजाना घर ले जाने के लिए पोषणयुक्त राशन दिया जाएगा। जो राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश पका हुआ गर्म भोजन मुहैया कराने पर जोर देंगे, उनके लिए मानक एकसमान होगा। साल के 300 दिन किशोरियों को पोषणयुक्त राशन (600 कैलोरी और 1820 ग्राम प्रोटीन) मुहैया कराने का खर्चा केंद्र और राज्य सरकारें पचास-पचास फीसदी भागीदारी के हिसाब से उठाएंगी। □

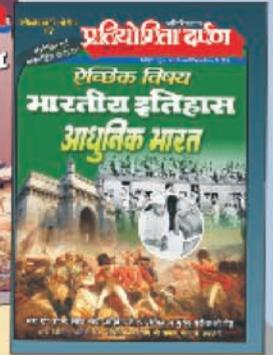
खेल	सं.	खिलाड़ी का नाम	स्वर्ण पदक	प्रतिस्पर्धा	वर्ष तथा स्थान
निशानेबाजी	34.	अनुजा जंग	1	50 मीटर राइफल श्री पोजीशंस	2006 मेलबोर्न खेल
	35.	विजय कुमार	1	25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल	"
	36.	समरेश जंग	1	10 मीटर एयर पिस्टल	"
	37.	राज्यवर्द्धन सिंह राठौर	1	डबल ट्रैप	"
	38.	गगन नारंग	1	50 मीटर राइफल श्री पोजीशंस	"
भारोत्तोलन	1.	ई. करुणाकरण	1	52 किलोग्राम फ्लाइवेट	1978 एडमंटन खेल
	2.	राघवन चंद्रशेखर	3	52 किलोग्राम	1990 आकलैंड खेल
	3.	पोन्नुस्वामी रंगास्वामी	3	56 "	"
	4.	परवेश शर्मा	2	60 "	"
	5.	परमजीत शर्मा	3	67.5 "	"
	6.	कर्णधर मंडल	1	75 "	"
	7.	बी. आदिशेखर	2	54 "	1994 विक्टोरिया खेल
	8.	मुरुगन वीरासामी	1	54 "	"
	9.	अरुमुगम पांडियन	1	56 "	1998 कुआलालंपुर खेल
	10.	धर्मराज विल्सन	1	56 "	"
	11.	सतीश राय	1	77 "	"
	12.	एन. कुंजूरानी देवी	3	48 "	2002 मैचेस्टर खेल
	13.	सानामाचा चानू	3	53 "	"
	14.	प्रतिभा कुमारी	2	63 "	"
	15.	शैलजा कुमारी	3	75 "	"
	16.	एन. कुंजूरानी देवी	1	48 "	2006 मेलबोर्न खेल
	17.	रेणु बाला चानू	1	58 "	"
	18.	गीता रानी	1	75 "	"
कुश्ती	1.	लीला राम	1	हेवीवेट	1958 कार्डिफ खेल
	2.	बिसंभर सिंह	1	बैंटमवेट	1966 किंग्सटन खेल
	3.	मुख्तियार सिंह	1	लाइटवेट	"
	4.	भीम सिंह	1	हेवीवेट	"
	5.	वेद प्रकाश	1	लाइट फ्लाइवेट	1970 एडिनबरा खेल
	6.	सुदेश कुमार	1	फ्लाइवेट	"
	7.	उदयचंद	1	लाइटवेट	"
	8.	मुख्तियार सिंह	1	वेल्टरवेट	"
	9.	हरिशचंद्र	1	मिडिलवेट	"
	10.	सुदेश कुमार	1	फ्लाइवेट	1974 क्राइस्टचर्च खेल
	11.	प्रेम नाथ	1	बैंटमवेट	"
	12.	जगरूप सिंह	1	लाइटवेट	"
	13.	रघुनाथ पवार	1	वेल्टरवेट	"
	14.	अशोक कुमार	1	लाइट फ्लाइवेट	1978 एडमंटन खेल
	15.	सतबीर सिंह	1	बैंटमवेट	"
	16.	राजेंद्र सिंह	1	वेल्टरवेट	"
	17.	रामचंद्र सारंग	1	लाइट फ्लाइवेट	1982 ब्रिस्बेन खेल
	18.	महावीर सिंह	1	फ्लाइवेट	"
	19.	जगमिंदर सिंह	1	लाइटवेट	"
	20.	राजेंद्र सिंह	1	वेल्टरवेट	"
	21.	कृष्ण कुमार	1	55 किलोग्राम	2002 मैनचेस्टर खेल
	22.	रमेश कुमार	1	66 "	"
	23.	पलविंदर सिंह चीमा	1	120 "	"

रजि.सं.डीएल (एस)-05/3231/2009-11 तथा डाक व्यय की पूर्व अदायगी के बिना डाक में डालने के लिए लाइसेंस-प्राप्त
Reg. No. D.L.(S)-05/3231/2009-11 Licenced to post without pre-payment at RMS, Delhi
26 अगस्त, 2010 को प्रकाशित • 29-30 अगस्त, 2010 को डाक द्वारा जारी

प्रतियोगिता दर्पण

के अतिरिक्तांक

टॉपर्स की नजर में



New Revised & Enlarged Editions

Series-1	Indian Economy	790	225.00
Series-2	Geography (India & World)	793	190.00
Series-3	Indian History	798	110.00
Series-4	Indian Polity	797	125.00
Series-6	General Science Vol. 1	814	90.00
Series-6	General Science Vol. 2	818	65.00
Series-7	Current Events Round-up Vol. 2	819	70.00
Series-12	Indian National Movement & Constitutional Development	812	90.00
Series-15	Indian History—Ancient India	804	110.00
Series-16	Indian History—Medieval India	806	120.00
Series-17	Indian History—Modern India	802	110.00
Series-22	Political Science	821	180.00
Series-23	Public Administration	824	165.00
Series-24	Commerce	805	199.00
प. सीरीज-1	भारतीय अर्थव्यवस्था	791	220.00
प. सीरीज-2	भूगोल (भारत एवं विश्व)	792	140.00
प. सीरीज-3	भारतीय इतिहास	795	120.00
प. सीरीज-4	भारतीय राजव्यवस्था	794	125.00
प. सीरीज-5	भारतीय कला एवं संस्कृति	796	95.00
प. सीरीज-6	सामान्य विज्ञान Vol. 1	829	90.00
प. सीरीज-6	सामान्य विज्ञान Vol. 2	830	75.00
प. सीरीज-7	समसामयिक घटनाचक्र	809	60.00
प. सीरीज-9	वस्तुनिष्ठ सामान्य हिन्दी	822	75.00
प. सीरीज-10	बौद्धिक एवं तर्कशक्ति परीक्षा	825	95.00
प. सीरीज-11	सामाजशास्त्र	810	90.00
प. सीरीज-12	भारत का राष्ट्रीय आन्दोलन एवं संवैधानिक विकास	823	90.00
प. सीरीज-13	खेलकूद	828	130.00
प. सीरीज-14	कृषि विज्ञान	836	120.00
प. सीरीज-15	प्राचीन इतिहास	837	120.00
प. सीरीज-16	मध्यकालीन इतिहास	838	125.00
प. सीरीज-17	आधुनिक इतिहास	839	145.00
प. सीरीज-18	दर्शनशास्त्र	842	90.00
प. सीरीज-19	न्यू रीजनिंग टेस्ट	843	120.00
प. सीरीज-20	हिन्दी भाषा	860	85.00
प. सीरीज-21	संख्यात्मक अभियोग्यता	861	145.00
प. सीरीज-22	राजनीति विज्ञान	866	165.00
प. सीरीज-23	लोक प्रशासन	813	170.00
प. सीरीज-24	वाणिज्य	816	195.00

...मैंने प्रतियोगिता दर्पण के राजव्यवस्था तथा अर्थव्यवस्था के अतिरिक्तांक को पढ़ा, वास्तव में दोनों स्पेशल अंक बेहतरीन हैं. इसे प्रत्येक अभ्यर्थी को पढ़ना चाहिए.

—जय प्रकाश मौर्य

सिविल सेवा परीक्षा, 2009 में हिन्दी माध्यम से सर्वोच्च स्थान

...प्रतियोगिता दर्पण के अतिरिक्तांक विषयपरक समझ विकसित करने में अत्यंत सहायक हैं.

—अखंड प्रताप सिंह

सिविल सेवा परीक्षा, 2009 में हिन्दी माध्यम से द्वितीय स्थान

...मैंने अर्थव्यवस्था के अतिरिक्तांक का प्रारम्भिक व मुख्य दोनों परीक्षाओं हेतु लाभ लिया था. प्रारम्भिक परीक्षा हेतु भूगोल, विज्ञान एवं राजव्यवस्था के अतिरिक्तांक का भी सहारा लिया. अर्थव्यवस्था का अतिरिक्तांक तो विकल्पहीन है.

—तरुण राठी

सिविल सेवा परीक्षा, 2009 में 19वाँ स्थान

...प्रतियोगिता दर्पण के अतिरिक्तांक विशेषकर अर्थशास्त्र का लाभदायक सिद्ध हुआ.

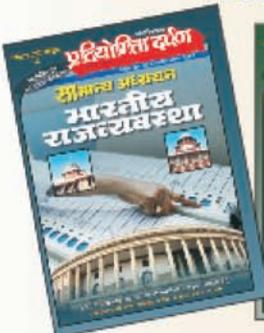
—कर्मवीर सिंह

सिविल सेवा परीक्षा, 2009 में 28वाँ स्थान

...प्रतियोगिता दर्पण का भारतीय अर्थव्यवस्था का अतिरिक्तांक बेजोड़ है.

—पुष्पराज सिंह

उ.प्र. पी.सी.एस. परीक्षा, 2007 में सर्वोच्च स्थान



To purchase online log on to www.pdgroup.in

प्रतियोगिता दर्पण

2/11 ए, स्वदेशी वीमा नगर, आगरा — 282 002

फोन : 4053333, 2530966, 2531101; फैक्स (0562) 4053330

E-mail : publisher@pdgroup.in

श्रीव साक्षरितः • नई दिल्ली फोन : 23251844/08 • ईपत्रवाचक क्रम : 68753390